R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 11
01 से 15 मार्च 2023
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

विधानसभा या औपचारिकता

4 साल में म.प्र. विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चला

15वीं विधानसभा के इस आखिरी बजट सत्र से सबको बड़ी उम्मीदें

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

प्रशासनिक

9 | मप्र की ऑफिसर्स फैमिली

राजनीति में वंशवाद तो आपने खूब सुना होगा। वर्तमान समय में तो परिवारवाद, वंशवाद आदि को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसकी वजह यह है कि कुछ पार्टियां और नेता योग्यता नहीं होने के बाद भी अपनों को राजनीति...

राजपथ

10-11 | जातियों को साधने में...

मप्र में एससी-एसटी और ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक हैं। एससी और एसटी को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। अब पार्टी ओबीसी की छोटी जातियों को साधने का अभियान चलाएगी। प्रदेश में हमेशा से...

मप्र कांग्रेस

15 | असंतुष्टों को मिलेगी जिम्मेदारी

विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इनके पहले असंतुष्ट नेताओं का महत्व बढ़ जाता है। इसी कड़ी में मप्र में कांग्रेस का फोकस अपने असंतुष्ट नेताओं पर है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपने हर नेता को साधने में जुटी हुई है।

तैयारी

18 | पैक्स को मजबूत...

मप्र में सहकारिता से उन्नति का पथ प्रशस्त हो रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के साथ समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं, धान आदि फसलों का उपार्जन किया जा रहा है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू हो गया है। 29 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार चुनावी बजट भी पेश करेगी। चुनावी साल में होने वाले इस सत्र पर सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा जनता की नजर में अपने आपको विकासशील सरकार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार को असफल बताने की कोशिश करेगी।

राजनीति

30-31 | सज गई बिसात...

हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका लक्ष्य भारत को परम वैभव दिलाना है। इस यात्रा में कोई आपकी पीठ थपथपाए, कोई शाबाशी दे या कोई उपेक्षा करे, आपको प्रसन्न होने या विचलित होने की जरूरत नहीं। आज आप विस्तारक हैं, कल आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हो सकते...

महाराष्ट्र

35 | अब शिवसेना शिंदे की

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का धड़ा ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया है। 78 पन्नों के फैसले में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और सिंबल धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। आयोग ने ये भी बताया...

बिहार

38 | राजद को राम नाम...

अगर आप हिंदू हैं, तो संभवत: रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से आपकी भावना भी आहत हुई होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

यात्रा ने उजागर की विकास की खामियां

किसी कवि ने क्या खूब लिखा है...

जहां भी देखो विकास नजर नहीं आता, बेईमानों की भीड़ में ईमानदार नजर नहीं आता
अगर होता गांव में विकास और तरक्की, तो युवा गांव छोड़कर शहर नहीं आता

यह हाल वर्तमान समय में पूरे देश का है। अगर बात मप्र की करें तो यहां पिछले 18 सालों में भाजपा सरकार ने विकास तो खूब किया है, लेकिन उसके बावजूद कई कमियां रह गई हैं। शायद इन्हीं कमियों को जानने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरी सरकार ने 20 दिनों तक विकास यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े-बड़े नेता सहित विधायक गांव-गांव पहुंचे और जनता से रूबरू होकर उनकी बातों को सुना। वैसे देखा जाए तो विकास यात्रा की अगवानी खूब धूम-धड़ाके और डीजे के साथ तो हुई लेकिन यह उत्साह का माहौल केवल जनप्रतिनिधियों को उत्साहित कर सका। आम आदमियों से दूरी यह उन जनप्रतिनिधियों के लिए भी चिंता का विषय है। पूरी विकास यात्रा के दौरान देखा जाए तो स्कूली छात्र-छात्राओं ने यात्रा की अगवानी बड़े हर्षोल्लास के साथ की लेकिन इन सब में आम जनता दिखाई नहीं दी जो कि निश्चित रूप से प्रदेश सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। कहीं-ना-कहीं आम जनता के मन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कार्यकलापों को लेकर टीस है। अब उसका निराकरण समय पर नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से यह वोट खिलाफ में जाने की संभावना बनी रहेगी। दरअसल, प्रदेश में जिस भी क्षेत्र से विकास यात्रा निकली, वहां खराब सड़कें और पानी की समस्या सबसे अधिक सामने आई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने सारी समस्याएं दूर करने का आश्वासन भी दिया है। कहीं-कहीं जनप्रतिनिधियों को विरोध का भी सामना करना पड़ा। इस पर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि जनता का विरोध हमारे लिए संजीवनी है। यानी यह इस बात का प्रतीक है कि यात्रा के दौरान जो खामियां सामने आई हैं, उसे सरकार तत्परता से दूर करने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि प्रदेशभर में विकास यात्रा के नाम से सरकार और उसके नुमाइंदों ने गांव- गांव, गली-गली जाकर अपनी सरकार का बखान किया और करें भी क्यों नहीं क्योंकि विगत 18 सालों में (15 महीने की सरकार को छोड़कर) वादे तो खूब हुए लेकिन धरातल पर काम कम ही हो पाया। विकास यात्रा के दौरान आम आदमियों को टटोलने की कोशिश की। उनका मानना है कि अब भ्रष्टाचार की बात तो बेईमानी हो गई है। भ्रष्टाचार पर चर्चा ही करना बेकार है। भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार का रूप ले चुका है। लोकायुक्त के छापों के बाद भी कर्मचारियों पर नेताओं का वरदहस्त रहता है, जिसके कारण उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा के दौरान सत्ता और संगठन को जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाकर काम किया जाएगा। यानी आने वाले समय में प्रदेश में विकास की गति तेज होगी। सरकार के सामने इस समय दोहरी चुनौती है। पहली यह कि विकास यात्रा के दौरान जनता से जो शिकायतें मिली हैं, उन्हें तत्काल दूर करना है। दूसरी यह कि विकास यात्रा के दौरान जिन कार्यों का भूमिपूजन किया जा रहा है, उन्हें भी चुनावी बिगुल बजने से पहले पूरा करना होगा। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 11, पृष्ठ-48, 1 से 15 मार्च, 2023

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

akshnews.com

चुनावी तैयारियां

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मिशन 2023 को साधने के लिए भाजपा ने किसी एक वर्ग को नहीं बल्कि सभी वर्गों को साधने का जतन कर रही है। वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। ये चुनाव देखना दिलचस्प होगा।

● **मिथलेश सिंह,** भोपाल (म.प्र.)

माफिया पर लगाम लगे

सरकार की कड़ी कार्यवाही के बाद भी प्रदेशभर में खनन माफिया सक्रिय हैं। अवैध रेत खनन चोरी छिपे किया जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार को और अधिक कठोर कदम उठाने होंगे। ताकि अवैध खनन रोका जा सके और माफियाओं पर लगाम लग सके।

● **हिमांशी खरे,** इंदौर (म.प्र.)

बजट का इंतजार

आने वाले बजट का सभी को इंतजार है। खासकर हम जैसे युवाओं को इस बजट से बहुत आस है। कोरोनाकाल में कईयों की नौकरियां चली गईं। अब अधिकतर लोग स्टार्टअप खोलने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार से उम्मीद है कि वो युवाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा करे।

● **आरती शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

राजनीतिक पार्टियां सक्रिय

इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जब भी केंद्र को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत होती है तो विपक्षी दलों के कई नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आते हैं। ये नेता किसी भी पार्टी से चुनावी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के जनाधार को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो पदयात्रा की, जिसमें उन्होंने भाजपा विरोधी सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित भी किया था। अन्य विपक्षी पार्टियां भी सत्तापक्ष को घरने की तैयारियों में जुट गई हैं। आए दिन नए-नए मुद्दे उठाकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आते हैं।

● **आशीष सेन,** रायसेन (म.प्र.)

पर्यटन को बढ़ावा

प्रदेश में अब चीतों का कुनबा बढ़ने से यहां पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। देशभर सहित विदेशों से भी यहां लोग घूमने आएंगे। जिससे मप्र की आर्थिक स्थिति और अधिक सुधरेगी। हमारा प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में देशभर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। सरकार का ये कदम बड़ा सराहनीय है। इससे जहां एक ओर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इससे जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो मप्र को आत्मनिर्भर बनाएगा।

● **संतोष प्रजापति,** राजगढ़ (म.प्र.)

सड़क हादसों पर लगाम

प्रदेशभर में ओवर स्पीड और लापरवाही की वजह से कई लोगों की सड़क हादसों में जान गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना भी सड़क हादसे की मुख्य वजह बन गई है। इसलिए ट्रैफिक नियमों को अब शिक्षा के साथ पढ़ाया जा रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर ब्लेक स्पॉट चिन्हित कर स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। जो कि एक अच्छी पहल है। इससे न सिर्फ सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी, बल्कि लोगों का जीवन भी बचेगा।

● **राहुल जाधव,** नई दिल्ली

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स, एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

बेबाक बागी

वरुण गांधी के बागी तेवर बरकरार हैं। अपनी डफली पर अपना राग वे 2017 से ही बजाते आ रहे हैं। इस समय पीलीभीत से लोकसभा सदस्य हैं। जबकि 2014 में सुल्तानपुर से विजयी हुए थे। उनकी मां मेनका गांधी तो लंबे समय से भाजपा में ही हैं पर वरुण ने पहला चुनाव 2009 में पीलीभीत से ही लड़ा था। तब उनकी मां ने उनके लिए सीट छोड़ी थी। खुद वे आंवला सीट से चुनाव लड़ी थीं। बेटे वरुण ने 2017 में उप्र में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनने का सपना संजोया था। पर, उनकी अति महत्वाकांक्षा ने उन्हें तो हाशिये पर धकेला ही, 2019 में उनकी मां मेनका का केंद्र का मंत्री पद भी झटक लिया। उप्र हो या केंद्र की सरकार। वरुण गांधी मुद्दों पर बेबाकी और मुखरता से अपनी बात कहते रहे हैं। किसान आंदोलन और कोरोना संक्रमण के लिए उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार की संवेदनहीनता के लिए तीखी आलोचना की थी। वरुण चाहते हैं कि विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद होनी चाहिए। वे अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में लोगों को अपने अधिकार के लिए सरकारी तंत्र से उलझ जाने की खुलकर सलाह दे रहे हैं। अब तो मुफ्त रेवड़ियां बांटने की सियासी प्रवृत्ति के लिए भी मुखरता से बयान दिया है।

सोरेन ने सुलगाई सियासत

अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक कर राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने की कवायद को एक बार फिर हवा दे दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन से इतर एक नए गठबंधन बनाए जाने पर भी बातचीत हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में केजरीवाल ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। राव राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं। वे कांग्रेस से भी दूरी बनाकर चल रहे हैं। केजरीवाल की राजनीतिक लाइन भी यही है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप दोनों विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला करने में आगे रही हैं। बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर मुख्यमंत्री सोरेन ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला था। मुख्यमंत्री सोरेन ने धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भाजपा को केवल व्यापारियों की चिंता है, जबकि हमारी सरकार आदिवासियों- मूलवासियों, गरीबों, पिछड़ों, दलितों, किसानों के लिए काम करती है।

रिक्त स्वप्न

बुजुर्ग नेता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिए जाने के बाद राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता का पद खाली हो गया है। कटारिया संघ की पसंद तो रहे ही, सूबे में भाजपा का जनाधार बढ़ाने वाले नेताओं में भी गिनती हुई सदैव उनकी। अब कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? इस सवाल पर भाजपा आलाकमान फिलहाल चुप्पी साधे है। कायदे से तो यह कुर्सी दो बार मुख्यमंत्री रह चुकीं वसुंधरा राजे को मिलनी चाहिए। जो कहने को पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हैं पर सूबे की सियासत का मोह उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वे मुख्यमंत्री पद का चेहरा खुद को घोषित कराने के फेर में कब से तिकड़म लगा रही हैं। पार्टी नेतृत्व ने पिछले 5 साल के दौरान उनकी अनदेखी में कोई कसर नहीं रखी पर वे भी घर बैठने को तैयार नहीं हुई। उनके धुर विरोधी जाट नेता सतीश पूनिया को आलाकमान ने वसुंधरा का कद घटाने के लिए ही पार्टी का सूबेदार बनाया था। यह बात अलग है कि पूनिया वसुंधरा की हैसियत घटा नहीं पाए। अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो आलाकमान की दुविधा बढ़ गई है। आलाकमान कह चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी।

खोया मान

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का रामपुर ही नहीं सूबे की सियासत में भी बोलबाला था। मुलायम सिंह यादव का मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान की इच्छा सपा में फैसला बन जाती थी। अखिलेश यादव के राज में उनकी चोरी गई भैंस को भी पुलिस ने मुस्तैदी से बिना देर किए बरामद कर लिया था। जो एक मजाक का किस्सा भी बन गया। पर 2017 में सूबे में सत्ता परिवर्तन हुआ तो आजम खान और उनके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। आजम खान व उनके सभी परिवारजनों के खिलाफ अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज होते गए और उन्हें ही नहीं उनकी पत्नी और बेटे को भी जेल जाना पड़ा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ही उनकी हिमायत में आया और उन्हें जमानत मिली। जेल में ही पिता-पुत्र को कोरोना संक्रमण भी झेलना पड़ा। एक तरह से तो मौत के मुंह से वापसी हुई 75 वर्ष के आजम की। इससे पहले रामपुर की स्वार टांडा सीट के विधायक उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता दो जन्मतिथि होने के आधार पर रद्द कर दी गई।

त्रिशंकु विस की आशंका

इसी साल मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। राज्य में जिस अंदाज में भाजपा और कांग्रेस की तैयारी हो रही है और जनता दल (एस) की अकेले लड़ने की तैयारी है, उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को यह चिंता सता रही है कि अगर पिछली बार की तरह इस बार भी त्रिशंकु विधानसभा बनी तो क्या होगा? दरअसल कर्नाटक में कई बार त्रिशंकु विधानसभा बनी है और इसका फायदा जेडीएस को मिलता रहा है। एचडी देवगौड़ा की पार्टी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में कभी भाजपा के साथ मिलकर तो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती रही है। पिछले यानी 2018 के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी हारी थी लेकिन भाजपा को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था। इसका फायदा उठाकर जेडीएस ने कांग्रेस संग हाथ मिला साझा सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने महज 37 सीट के बावजूद जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनवाया था।

तू डाल-डाल, मैं पात-पात

यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत को वर्तमान समय में मप्र पुलिस के अधिकारी साकार कर रहे हैं। दरअसल, प्रदेश में कई पुलिस अधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास दर्जनों सरकारी नौकर सेवाएं दे रहे थे। इनमें सेवानिवृत्त अधिकारी भी शामिल थे। हाल में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश सरकार के मुखिया ने जिस नब्ज पर उंगली रखी उसने हिंदुस्तान में सामंती राज में सेवा-चाकरी करवाने वाले दिनों की याद ताजा कर दी। उन्होंने प्रदेश की भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों को चेताया कि पुलिस वालों को अपने घरों में घरेलू कामों के लिए बहुत ज्यादा तैनात करने से बाज आएं। सरकार के मुखिया की इस सख्ती के बाद आईपीएस अफसरों ने अपने यहां तैनात कारिंदों की छंटनी शुरू कर दी। जिन रिटायर्ड अफसरों के पास कारिंदे थे, उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया। लेकिन 1985 बैच के एक प्रमोटी आईपीएस अधिकारी ने दिखावे के लिए अपने यहां तैनात सरकारी कारिंदों को वापस तो कर दिया, लेकिन उनके आईपीएस दामाद ने सरकार के इस आदेश का तोड़ निकालते हुए तू डाल-डाल, मैं पात-पात की तर्ज पर अपने यहां तैनात कारिंदों को अपने ससुर के यहां अटैच कर दिया। सरकारी सेवा से रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी नौकर-चाकरों के आदी हो चुके साहब को हींग लगे न फिटकरी और रंग चोखा हो की तर्ज पर बिना खर्चे के कारिंदे मिल गए हैं।

एक करोड़ का अपमान

शीर्षक पढ़कर आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो रहे होंगे, लेकिन यह पूरी तरह सत्य है। दरअसल, मामला महाकाल की नगरी का है। वहां आयोजित विक्रमोत्सव में कथा सुनाने के लिए सरकार ने एक प्रख्यात कवि और नए-नए कथाकार बने महाशय को आमंत्रित किया था। आयोजकों को उम्मीद थी कि नाम और काम के धनी इन महाशय को आमंत्रित करने से सरकार की साख में चार चांद लगेगा। इसके पीछे वजह भी थी। क्योंकि ये महाशय देश के सबसे चर्चित कवि तो हैं ही, साथ ही युवाओं में इनका बड़ा क्रेज है। कभी कवि, कभी मोटिवेटर, कभी कथाकार के रूप में ये लगातार सक्रिय रहते हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें सबसे अधिक सुना और देखा जाता है। शायद यही वजह है कि आयोजकों ने इन्हें 3 दिन के लिए 1 करोड़ रुपए की मोटी फीस देकर आमंत्रित किया था। लेकिन पहले ही दिन कथा के दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के आधार स्तंभ रहे एक संगठन पर कुछ इस तरह का बयान दे दिया कि आयोजन विवादों में फंस गया। उसके बाद से लोग कहने लगे हैं कि सरकार ने क्या अपमान कराने के लिए एक करोड़ की फीस दी थी। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी भोजपुर महोत्सव में ये महाशय सरकार की फजीहत कर चुके थे।

मामा के राज में 5 के बदले 150 करोड़ पाओ

प्रदेश में इन दिनों नई स्कीम चालू हुई है। 5 करोड़ दो, 150 करोड़ पाओ। ऐसा ही कुछ वाक्या विंध्य प्रदेश के जिले का है। यहां पर कलेक्टर साहब ने एक सीनियर एडवोकेट और प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता की सिफारिश पर मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। वकील साहब भी वकालत करने की फीस संबंधित पार्टी से ले चुकी हैं। वहीं कलेक्टर साहब को भी अच्छी खासी आमदनी हो गई है। कौन कहता है कि विंध्य में कुछ नहीं है। एक ही शॉट में करोड़ों का खेल करने वाले कलेक्टर साहब को बतौर सजा कुछ महीनों के लिए राजधानी की राह दिखा दी थी। पर कलेक्टर साहब तो जुगाड़ लगाकर मुआवजे की राशि में से आधी राशि देकर फिर जिले में काबिज हो गए। यह भी कोई छोटा-मोटा जिला नहीं है। हमेशा से इस जिले पर सिंधिया घराने की नजरें रही हैं। अब देखते हैं कि कलेक्टर साहब क्या नया गुल खिलाते हैं। यहां यह बता दें कि उक्त राशि रेलवे को जमीन का अधिग्रहण करने के एवज में मिली है और घूस मुआवजे की राशि को ज्यादा निर्धारण करने पर। इससे नेताजी को भी फायदा, वकील साहब भी खुश और कलेक्टर की बीसों उंगलियां घी में। जब इतनी बात हो ही रही है तो नेताजी कोई छोटे-मोटे नेता नहीं हैं। वह पहले बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। नेताजी, वकील साहब और कलेक्टर साहब की जोड़ी अगर ऐसे ही जिलों में बनी रही तो 5 के बदले 150 करोड़ पाओ वाली स्कीम लागू हो जाएगी।

जोर का झटका...धीरे से

2020 में कांग्रेसियों की बगावत के बाद सत्ता में आने वाले कुलीनों के कुनबे में जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। यह झटका कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे कद्दावर नेता के परिजन देने वाले हैं। जिन नेताजी की यहां बात हो रही है, वे ग्वालियर-चंबल अंचल से आते हैं और उन्होंने प्रदेश में मंत्री पद भी सुशोभित किया है। बताया जाता है कि नेताजी आगामी विधानसभा चुनाव में पेंच लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देने के मूड में नहीं है। इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ पाला बदलने की तैयारी कर ली है। सूत्रों का कहना है कि इस दिशा में उन्होंने कदम भी बढ़ा लिया है और कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के साथ उनकी पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी उनकी बैठक हो चुकी है। बताया जाता है कि पिछले 4 साल से राजनीति में हाशिए पर चल रहे इन नेताजी ने पाला बदलने की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही वे विपक्ष का हाथ थामेंगे। बताया जाता है कि विपक्षी पार्टी ने उन्हें उनकी मनपसंद सीट से चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी भी दे दी है।

कांग्रेस में रार

विलुप्त पड़ी कांग्रेस में चिलम फूंकने का काम प्रदेश के नेता बखूबी निभा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने मप्र के नेताओं को नसीहत दे डाली। ये वह नेताजी हैं जो राहुल गांधी को अपनी मोटरसाइकिल पर मंदसौर जिले में किसान आंदोलन में ले गए थे। कांग्रेस के आपस की फूट इतनी जबरदस्त है कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को डराने का काम गाए-बजाए एक साजिश के तहत 10 वर्षों तक राज करने वाले मुख्यमंत्री जी की शह पर किया जाता है। भाजपा की 18 साल की सरकार को इस बार कांग्रेस की नहीं बल्कि जनता की चुनौती मिली हुई है। ऐसे में भाग्य से बिल्ली का छींका किस्मत में मिल गया तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वैसे कमलनाथ ही प्रदेश कार्यालय से लेकर सारे पार्टी कार्यक्रमों का खर्च उठाते हैं। इसलिए हाईकमान चाहता है कि सत्ता आने पर कमलनाथ मुख्यमंत्री ही बनें। अब देखना यह है कि यह नेताजी अपने दरबारियों को टिकट दिलाने में कितने कामयाब होते हैं। कमलनाथ का तो एक ही हिसाब है सर्वे में जो जीतेगा उसे ही टिकट दिया जाएगा।

दलालों से घिरा शासन

मप्र की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान कई सालों से फाइलों के बाहर नहीं आ पाया है। इसकी वजह है कुछ दलालों का रसूख। ये दलाल ऐसे हैं जो किसी भी सरकार में अपने आपको फिट कर लेते हैं। पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार में जब आयकर छापा पड़ा था तब उसकी जद में कई दलाल भी आए थे। प्रदेश में कबीना मंत्रियों के पास भी अपने-अपने दलाल हैं। वहीं प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक खास दलाल सबसे अधिक सक्रिय है। ये दलाल ब्यूरोक्रेसी के सबसे नजदीक हैं। इस दलाल ने पिछले 4 वर्ष में अनगिनत संपत्ति बना ली है। ये सही है या नहीं, परंतु यह सही है कि इस दलाल ने सरकार के मुखिया के नाम पर जमकर कमाई की है और शहर के चारों तरफ जमीनें खरीद ली हैं। ऐसे ही काली कमाई करने वाले रसूखदारों के कारण मास्टर प्लान धरातल पर उतर नहीं पा रहे हैं।

दरअसल, जब भी मास्टर प्लान का खाका तैयार होता है, वह लीक हो जाता है। इस कारण जमीनों का भाव आसमान पर पहुंच जाता है। ग्रीन बेल्ट और कैचमेट एरिया के नाम पर मास्टर प्लान में बाधा उत्पन्न की जाती है, जो सरासर गलत है। क्योंकि बड़ा तालाब हो या छोटा तालाब इनके कैचमेट एरिया और इनके किनारों पर बड़े पैमानों पर मकानों का निर्माण किया गया है। यह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा है। दरअसल, दलालों द्वारा मास्टर प्लान को प्रभावित करने का यह एक तरीका है। ऐसे ही एक दलाल हावी हैं। उन्होंने ब्राह्मण होकर पंजाबी लड़की से शादी की है। उक्त महिला ने रसूख का फायदा उठाते हुए पुराने मुख्य सचिव की नजदीकी का भी खूब इस्तेमाल किया। शहर में रहने वाले नामचीन अफसर भी इस दलाल के नजदीक हैं। लेकिन इस व्यक्ति की खासियत यह है कि वह ज्यादा दिन दोस्ती नहीं रखता है। इस आदमी के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डीबी मॉल के सामने फ्रूट कोर्ट के लिए जमीन आवंटित करवा ली है। यही नहीं एक पॉश इलाके में पेट्रोल पंप भी ले लिया है। सूरज नगर के पास जहां हॉर्स फार्म होता था, वहां की जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली है और एक वैश्य जाति के व्यक्ति के माध्यम से उसे बिकवा रहे हैं। इन जमीनों में से नाममात्र की ही परमिशन है। यहां बता दें कि दलाल के पिता भी राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर रहे हैं। जब वे नौकरी में थे तो उनके यहां लोकायुक्त का छापा भी पड़ा था।

सूत्रों का कहना है कि प्रशासनिक वीथिका में रसूख के कारण इस दलाल ने कई लोगों से पैसा ले रखा है और अब लौटाने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि इस व्यक्ति ने अपने घर पर सीसीटीवी का ऐसा मकड़जाल बना रखा है जिससे हर आने-जाने वाले पर नजर रख जाती है। अगर कोई व्यक्ति उससे मिलने आता है तो वह सीसीटीवी में देखकर तय करता है कि किससे मिलना है, किससे नहीं। यहां यह बता दें कि यह व्यक्ति क्रेशर व्यापारी है।

इसी तरह प्रदेश सरकार के मंत्रियों के भी अपने-अपने दलाल हैं। किसी के परिजन मंत्री के लिए दलाली कर रहे हैं तो किसी ने अपने चहेतों को सक्रिय कर रखा है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस बात की जानकारी सरकार को भी है, लेकिन सरकार इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही है। इस कारण पूरी सरकार दलालों से घिरी हुई है।

एक तरफ सरकार दलालों से घिरी पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के मुखिया रोज नई घोषणाएं कर रहे हैं। आलम यह है कि घोषणाओं का अंबार लग चुका है। उधर, दलालों के रसूख से घिरी सरकार में मास्टर प्लान कैसे लागू होगा यह सवाल निरंतर उठ रहा है। गौरतलब है कि किसी भी शहर का सुनियोजित विकास करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाता है। लेकिन मप्र में शहरों का विकास तो धड़ाधड़ किया जा रहा है, लेकिन मास्टर प्लान रसूखदारों के कारण मंत्रालय में अटका हुआ है। इस कारण मप्र के शहरों का विकास बेतरतीब तो हो रहा है। दसअसल, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के लगभग सभी बड़े शहरों का मास्टर प्लान अब तक तैयार नहीं हुआ है। जबकि इन शहरों में मेट्रो लाइन, सड़कों, नालियों और बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। भोपाल की बात करें तो यहां के मास्टर प्लान की अवधि वर्ष 2005 में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रदेश की राजधानी होने के बावजूद 17 वर्ष में नया मास्टर प्लान अब तक नहीं बन पाया है। अमृत योजना के तहत वर्ष 2035 तक के लिए मप्र के 34 शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाना है।

इंदौर और जबलपुर शहर का हाल यह है कि वहां भी बिना मास्टर प्लान के अनियोजित विकास हो रहा है। भोपाल की चूनाभट्टी कोलार रोड छह लेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है, लेकिन सड़क से लगे आवासीय क्षेत्रों में भवन निर्माण का फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) नहीं बढ़ाया गया है। चूनाभट्टी में अब भी एफएआर 0.75 निर्धारित है। घनी आबादी होने के बाद भी कम एफएआर होने के कारण भूमि का समुचित तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है। इससे निर्माण कार्य कम हो रहे हैं और शासन को राजस्व क्षति हो रही है। चूनाभट्टी के रहवासियों ने शासन से एफएआर बढ़ाने की मांग की है। मास्टर प्लान न बनने से यह समस्या आ रही है।

● **कुमार राजेंद्र**

हेरिटेज बिल्डिंग्स का मामला अधर में

अफसरों को नए मास्टर प्लान के आने का इंतजार है। अफसरों ने नए प्लान में लो डेनसिटी एरिया का एफएआर 0.75 प्रस्तावित किया है। नए प्लान के लागू होते ही अफसरों के बंगलों में हुए अवैध निर्माण स्वतः वैध हो जाएंगे। नया प्लान लागू होने पर आम लोगों को लगभग दोगुना फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर- प्लॉट का एरिया व कुल बिल्टअप एरिया का अनुपात) मिलने और सड़क की चौड़ाई के हिसाब से लैंडयूज का चयन करने की छूट मिलना है, पर यह अटकी हुई है। साथ ही पुराने शहर की हेरिटेज बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट भी अटक गया है। मास्टर प्लान में इन बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले मकानों व जमीन पर हेरिटेज एफएआर का प्रावधान किया है। भोपाल मास्टर प्लान के अनुसार तीन एरिया लॉ डेनसिटी में आते हैं, पुलिस लाइन के पीछे फायरिंग रेंज वाला एरिया, लॉ एकेडमी के पीछे सूरज नगर वाला एरिया और साक्षी ढाबे के सामने वाला एरिया लॉ डेनसिटी में आता है।

मप्र की ऑफिसर्स फैमिली

राजनीति में वंशवाद तो आपने खूब सुना होगा। वर्तमान समय में तो परिवारवाद, वंशवाद आदि को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसकी वजह यह है कि कुछ पार्टियां और नेता योग्यता नहीं होने के बाद भी अपनों को राजनीति में महत्वपूर्ण पद देकर उपकृत करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ नौकरशाहों का एक वर्ग ऐसा हैं, जिनके पुत्र-पुत्री अपने माता-पिता से प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह मेहनत करके प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। मप्र में ऐसी कई ऑफिसर्स फैमिली हैं, जिनमें पिता-पुत्र या पुत्री ब्यूरोक्रेट्स हैं।

इन ऑफिसर्स फैमिली के लिए सौभाग्य की बात यह है कि इन सभी को मप्र कैडर में सेवा देने का अवसर मिला है। राज्य के दो टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ कुछ ऐसे ही परिस्थिति है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बेटे अमनवीर सिंह बैंस भी मप्र कैडर के ही आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना की बेटी सोनाक्षी सक्सेना भी मप्र कैडर में ही आईपीएस हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों के दौरान मप्र के युवा बड़ी संख्या में पीएससी में चयनित हो रहे हैं। इनमें प्रदेश कैडर में कार्यरत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों के भी पुत्र-पुत्रियां हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों के बेटे और बेटी को समान सर्विस भी मिली है। मप्र के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बेटे अमनवीर सिंह भी आईएएस अधिकारी हैं। वह अभी बैतूल कलेक्टर हैं। इसके साथ ही डीजीपी सुधीर सक्सेना की बेटी भी आईपीएस अधिकारी हैं। सोनाक्षी सक्सेना अभी इंदौर में पदस्थ हैं। इसके साथ ही मप्र कैडर के आईएएस टी धर्माराव के बेटे भी प्रतीक राव आईएएस अधिकारी ही हैं। इसके साथ ही अन्य अधिकारियों के बेटे-बेटियों का कैडर तो एक है लेकिन सर्विस अलग है।

आईएएस एसएन मिश्रा के पुत्र आईआरएस हैं, आईएएस अजय शर्मा की पुत्री आईपीएस है, आईएएस मुक्तेश वार्ष्णेय के पुत्र आईआरएस हैं, आईपीएस एसएस लाल की पुत्री आईआरएस हैं, वहीं जेएन कंसोटिया की पुत्री आईआरएस हैं।

दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा साल 2021 में चयनित भारतीय वन सेवा के अफसरों को 2022 में अपना कैडर अलॉट किया गया था। इसमें मप्र से 7 कैंडिडेट का फॉरेस्ट सर्विस के लिए चयन हुआ था। इसमें से 4 अफसरों का मप्र कैडर अलॉट किया गया। इन 4 अफसरों में से एक अफसर श्रेयस श्रीवास्तव भोपाल के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शहर के कैंपियन स्कूल से की है। उनके पिता राजेंद्र कुमार 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। अब दोनों पिता-पुत्र मप्र कैडर में शामिल हो गए हैं। अब इनका मिलाकर यह परिवार 12वीं पारिवारित फैमिली बन गई है, जिनको एक जैसा कैडर मिला है। दोनों मप्र के अधिकारी बन गए हैं। आईएएस टी धर्माराव के बेटे प्रतीक राव का चयन आईएएस में हुआ है। बाकी का सेलेक्शन सब डिफरेंट सर्विस में हुआ है। इसमें पिता आईएएस हैं तो उनके बेटा या बेटी का चयन आईपीएस या आईएफएस में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक यूपीएससी 2021 का रिजल्ट आने के बाद आईएफएस के लिए मप्र के 4 अफसरों का चयन हुआ। जिन अधिकारियों को मप्र कैडर अलॉट हुआ उसमें शिवपुरी से गौरव जैन, भोपाल से श्रेयस श्रीवास्तव, रीवा से बीरेंद कुमार पटेल और ग्वालियर से नम्रता बिजोरिया शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रीवा के रहने वाले बीरेंद्र ने आरजीपीवी कॉलेज से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद वो भोपाल गए जहां उन्होंने 2012 से लेकर 2014 तक यूपीएससी की तैयारी और फिर यहां से दिल्ली का रुख किया। बीरेंद्र ने कहा कि उनके पिता किसान हैं और वे एक साधारण परिवार से आते हैं। वहीं मप्र के कई नौकरशाहों के पुत्र-पुत्री देश और विदेश में बड़ी-बड़ी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वैसे सबकी प्रमुखता भारतीय प्रशासनिक सेवा ही रहती है।

● **सुनील सिंह**

ये हैं मप्र के अफसर परिवार बेटा-बेटी

- **बीएन यादव-आईएएस**, अजय यादव-आईएएस
- **आरपी कपूर-आईएएस**, वरुण कपूर-आईपीएस
- **केएस शर्मा-आईएएस**, मनीष शंकर शर्मा-आईपीएस
- **एसएस वरवड़े-आईपीएस**, निशांत वरवड़े-आईएएस
- **ओपी गर्ग-आईपीएस**, अदिति गर्ग-आईएएस
- **भागीरथ प्रसाद-आईएएस**, सिमाला प्रसाद,-आईपीएस
- **इकबाल सिंह बैस-आईएएस**, अमनवीर सिंह बैस-आईएएस
- **राजेंद्र कुमार-आईपीएस**, श्रेयस श्रीवास्तव-आईएफएस
- **बीआर नायडू-आईएएस**, निवेदिता नायडू-आईपीएस
- **सुधीर कुमार सक्सेना-आईपीएस**, सोनाक्षी सक्सेना-आईपीएस
- **मुकेश जैन-आईपीएस**, अर्थ जैन-आईपीएस
- **टी धर्माराव-आईएएस**, प्रतीक राव-आईएएस

मप्र की राजनीति में इन दिनों विधानसभा चुनावों को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां सत्ता में काबिज होने के लिए रणनीति बना रही हैं। भाजपा रणनीतिक तैयारी में कांग्रेस से काफी आगे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सभी जातियों और क्षेत्रवाद को साधने में जुटी हुई है। पार्टी का सबसे अधिक फोकस एससी-एसटी के साथ ओबीसी की छोटी जातियों पर भी है।

जातियों को साधने में जुटी भाजपा

मप्र में एससी-एसटी और ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक हैं। एससी और एसटी को साधने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है। अब पार्टी ओबीसी की छोटी जातियों को साधने का अभियान चलाएगी। प्रदेश में हमेशा से ही एससी-एसटी का समीकरण सत्ता की चाबी मानी जाती है। क्योंकि इन दोनों वर्गों के लिए प्रदेश की 36 फीसदी यानी 82 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। ऐसे में जिस दल को इन वर्गों का साथ मिलता है, उसका सत्ता तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। बीते चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों की अधिकतर सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया जिसके चलते कांग्रेस 2018 के विधानसभा चुनाव में सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसलिए इस बार भाजपा एससी-एसटी के साथ ही ओबीसी की छोटी जातियों को साधने की कोशिश में जुट गई है।

भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पार्टी ने 51 फीसदी वोट के साथ 200 से अधिक सीटें जीतने का जो टारगेट सेट किया है उसके लिए सभी जातियों और सभी क्षेत्रों में पैठ बढ़ानी होगी। इसलिए एससी-एसटी वर्ग के लोगों को साधने के लिए **योजनाओं** का लाभ दिलाने के साथ भाजपा का फोकस अब अगले माह से ओबीसी वर्ग पर होगा। इसके लिए भाजपा ने ओबीसी वर्ग की सभी बड़ी और छोटी जातियों के लोगों से संपर्क साधने का कार्यक्रम तय किया है। पार्टी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल से अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक इसके लिए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश में रहने वाले सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी तथा जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी कम से कम 10 गांवों में जाकर संवाद करेंगे। प्रदेश संगठन के निर्देश पर पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने जो तैयारी की है उसमें कहा गया है कि ओबीसी के छोटी जाति के जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें रोहिणी कमीशन के माध्यम से आरक्षण दिलाने के लिए मोर्चा पदाधिकारी और कार्यकर्ता काम करेंगे। केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ दिलाने का काम भी करना है। मोर्चा ने यह भी तय किया है कि ओबीसी वर्ग के जिन अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूरों के विरूद्ध अन्याय हुआ है उन्हें केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में शिकायत कराकर न्याय दिलाने का काम भी करना है। जो जातियां प्रदेश में ओबीसी की सूची में हैं लेकिन केंद्र की सूची में ओबीसी कैटेगिरी में नहीं हैं, उनके लिए भी मोर्चा ने आवेदन कराने के लिए काम करने को कहा है। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के बड़े सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाएगा। ओबीसी वर्ग की बड़ी जातियों को लेकर भी मोर्चा द्वारा कार्यक्रम कराने के लिए क्षेत्र चिन्हित किए जाएंगे।

यह तो तय है कि विधानसभा चुनाव में ओबीसी वोटर्स किंगमेकर होंगे। इसलिए प्रदेश में भाजपा ओबीसी मोर्चा ओबीसी वर्ग के सामाजिक नेताओं, सेलिब्रिटी और प्रतिभावान लोगों की सूची तैयार करेगा। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी भी मोर्चा ने की है। इसके

ओबीसी को साधे बगैर चुनाव जीतना मुश्किल

मप्र की सियासत की सुई एक बार फिर ओबीसी वर्ग की ओर घूम गई है। अब इसे जरूरत कह लें या सियासी मजबूरी लेकिन ओबीसी को साधे बगैर विधानसभा चुनाव को जीतना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि इस वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने बड़ा दांव चल दिया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल ने बताया कि ओबीसी वर्ग के लिए सरकार नया प्लान लाई है। इसके तहत स्वरोजगार के लिए साढ़े बयालीस करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो मप्र में करीब 52 फीसदी ओबीसी वर्ग की आबादी है। विधानसभा की 100 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वर्ग का दखल है और फिलहाल सदन में ओबीसी वर्ग के 60 विधायक हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में 25.83 फीसदी पदों पर ओबीसी वर्ग काबिज है। जाहिर है, मप्र के सबसे बड़े वोट बैंक पर कांग्रेस और भाजपा दोनों की ही नजर है और दोनों ही दल एक-दूसरे को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी करार देने में जुटे हैं।

साथ ही 15 मार्च तक जिला कार्यसमिति और 30 मार्च तक मंडल कार्यसमिति की मोर्चा बैठकें करके रिपोर्ट प्रदेश संगठन को दी जाएगी।

भाजपा ने इस बार 200 से अधिक सीटें जीतने का जो लक्ष्य बनाया उसमें आकांक्षी (पिछले चुनाव में हारी) सीटों का बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए पार्टी का सबसे ज्यादा ध्यान आकांक्षी विधानसभा सीटों पर है। यह वह सीटें हैं जिनमें पार्टी को पिछली बार पराजय मिली थी। अब इन सीटों के हर बूथ में 51 प्रतिशत मत पाने के लिए पार्टी ने रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत इन क्षेत्रों में पार्टी ने अपने पुराने वरिष्ठ नेता-कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाया है। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के साथ तालमेल के अभाव में आकांक्षी सीटों को जीतने की रणनीति कमजोर पड़ रही है। गौरतलब है कि भाजपा ने आकांक्षी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने नई रणनीति पर काम शुरू करने का संकल्प लिया है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा को 121 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, इन क्षेत्रों में पार्टी ने अपने पुराने वरिष्ठ नेता-कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाया है। इन आकांक्षी सीटों के प्रभारियों को दायित्व के क्षेत्र में तालमेल और गृह जिले में पूछ-परख के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रभारियों में कई लोग टिकट के दावेदार भी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दो दिन पहले संगठन के नेताओं को समन्वय बढ़ाने की समझाइश दे चुके हैं। सत्ता-संगठन पदाधिकारियों के साथ आकांक्षी सीटों के प्रभारियों की अब तक 4-5 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में भी तालमेल का मामला उठ चुका है।

संगठन के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि बार-बार की समझाइश के बाद भी नेताओं में तालमेल नहीं बन पा रहा है। कई जिलों के प्रभारियों का कहना है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री, जिले के जनप्रतिनिधि, अध्यक्ष और संभागीय प्रभारियों के बीच बेहतर तालमेल नहीं बन पा रहा। इन क्षेत्रों में पार्टी ने दूसरे जिलों के नेता, पूर्व संगठन मंत्री, निगम-मंडलों के अध्यक्ष और पूर्व सांसद-विधायकों को प्रभारी बनाकर भेजा गया है। पन्ना जिले के बबलू पाठक को राजनगर सीट का प्रभार मिला है। इसी

तरह छतरपुर जिले के पुष्पेंद्र गुड्डन पाठक पर सागर जिले की देवरी सीट की जवाबदारी है। पन्ना के संजय नागाइच को दमोह सीट संभाल रहे हैं जबकि जयप्रकाश चतुर्वेदी पर महाराजपुर का दायित्व है। विनोद गोटिया को डिंडौरी जिले की सीट दी गई है। पार्टी ने पुष्पेंद्र सिंह को बंडा सीट जिताने को कहा है। इनके अलावा संगठन ने जिन नेताओं को आकांक्षी सीटों का प्रभार सौंपा है उनमें जितेंद्र लिटोरिया, केशव सिंह भदौरिया, आलोक संजर, प्रहलाद भारती, संतोष जैन, गुड्डन पाठक, चेतन सिंह, राजो मालवीय, डॉली शर्मा, हरिशंकर जायसवाल, वसंत माकोड़े, अजीत पवार और विक्रम बुंदेला जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इन सीटों पर बूथ स्तर पर त्रिदेवों अर्थात् बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए को पूर्व में दिया गया प्रशिक्षण याद दिलाकर नए सिरे से सक्रिय किया जा रहा है। भाजपा हाईकमान ने बूथ समितियों को एक्टिव कर वोट शेयर बढ़ाकर 51 फीसदी सुनिश्चित करने का टारगेट दिया है।

भाजपा ने इन 121 सीटों में से करीब 100 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं जिन पर विशेष रणनीति के तहत काम शुरू करने की जरूरत बताई गई है। ऐसी हारी हुई सीटों और जिन बूथों पर भाजपा प्रत्याशी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था वहां पन्ना प्रमुख के साथ हितग्राहियों से संपर्क का काम सघन करने को कहा गया है। सत्ता-संगठन के सर्वे में ग्वालियर-चंबल, महाकौशल अंचल से लेकर विंध्य, बुंदेलखंड और मालवा-निमाड़ की कई सीटों पर मैदानी स्थितियां अब भी सुधार के संकेत नहीं दे रहीं। आकांक्षी सीटों के जो प्रभारी स्वयं अपने लिए टिकट की दौड़ में हैं उनका फोकस अपने जिले के समीकरण साधने पर बना हुआ है। प्रभार के जिले में बेहतर समन्वय और अपेक्षित तवज्जो न मिलने से भी मैदानी कार्यकर्ताओं से उनका तालमेल नहीं बन पाया जिससे उनके प्रवास बढ़ नहीं पा रहे।

गौरतलब है कि भाजपा ने उन सीटों पर फोकस करने का प्लान बनाया है, जिनमें कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत का मार्जन बहुत कम था। प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि पार्टी इस बार वोट बैंक में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी चाहती है। बता दें कि 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 41 प्रतिशत था। प्रदेश में 10 सीटें ऐसी हैं, जहां जीत-हार का अंतर 1000 वोट का था। ये सीटें ग्वालियर चंबल की हैं। 18 सीटें वे हैं जहां भाजपा के कैंडिडेट 2000 वोट के अंतर से हारे। इसी तरह 30 सीटें हैं जहां पर जीत का अंतर 3,000 से कम रहा। वहीं 45 सीटें ऐसी हैं जहां जीत का अंतर 5,000 से कम रहा है। भाजपा इन सीटों को आकांक्षी सीटें मान रही है। ऐसी सीटों को मिला लिया जाए तो 100 के आसपास का आंकड़ा पार्टी की नजर में है। भाजपा को लग रहा है कि यदि इन सीटों को जीत लिया तो उसका मिशन 2023 पूरा हो जाएगा।

● **कुमार विनोद**

आदर्श ग्राम योजना से बड़े वोट बैंक पर नजर

चुनावी साल में केंद्र और राज्य सरकार का फोकस हर वर्ग को साधने पर है। इसके लिए चुनावी योजनाएं तो शुरू की ही जा रही हैं, वहीं पुरानी योजनाओं में भी ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं जिससे बड़े वोट बैंक को साधा जा सके। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति वर्ग (एससी) को साधने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को अपडेट किया है। पहले इस योजना में उन गांवों को शामिल किया जाता था, जहां 50 फीसदी या इससे अधिक आबादी एससी वर्ग की है। अब 40 फीसदी या इससे अधिक आबादी वाले गांवों को भी योजना में शामिल किया है। इसके चलते प्रदेश में 619 गांवों का चयन किया गया है, जबकि देश में यह आंकड़ा 11,500 है। मप्र में सरकार की नजर 16 फीसदी एससी वोट बैंक पर है। वर्ष 2021-22 में शुरू हुई इस योजना में चयनित गांवों में होने वाले सामुदायिक विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इस लिहाज से अब मप्र को 619 गांवों के लिए करीब 123 करोड़ रुपए मिलेंगे। योजना में अब तक प्रदेश के 1074 एससी बहुल्य गांव चयनित किए गए हैं। इनमें से 1029 गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

गुणवत्ता पर पीडब्ल्यूडी का फोकस

26 सड़कों के लिए केंद्र से मिले 2332 करोड़

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मप्र में 26 सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन के लिए 2332 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्र सरकार का आभार माना है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 22 हजार 394 करोड़ रुपए के व्यय से 10 हजार 195 किलोमीटर नई सड़कों तथा 45 नए पुलों का निर्माण किया गया है। इसी कड़ी में 31 दिसंबर को प्रदेश की 26 सड़कों में 625 किलोमीटर मार्ग के निर्माण एवं उन्नयन के लिए स्वीकृति दी गई है। नागौद से मैहर बापा सुरधारू परसामनिया रामपुर रोड में 61 किलोमीटर मार्ग के लिए 178 करोड़, खारदौन कलां उगली शुजालपुर रोड के लिए 71 करोड़ 23 लाख, एनएच-39 से सकरिया-काकराहटी-गुन्नौर-दिगौरा से एनएच-943 के लिए 63 करोड़ 37 लाख, मऊ-पदाना-तेलन के अपग्रेडेशन कार्य के लिए 79 करोड़ 15 लाख, सेमई से विजयपुर रोड के लिए 57 करोड़ 69 लाख, देवतालाब से पथराहा डाडन-हटवा-सोहरेन-अमोचपहाड़ी-निरपत सिंह रोड के लिए 49 करोड़ 72 लाख, एनएच-44 से जाडेरूआ-बेहाटा-सूरोचंदूपूरा-गुठिया-बहुदपुर रोड के लिए 47 करोड़ 62 लाख, शाहपुर-रंगोली-गिरवर-भाईसवाही-हिलगना-धाना-मोकलपुर चौराहे से एनएच-44 मार्ग के लिए 119 करोड़ 25 लाख, गढ़ाकोटा-बलहे रोड के अपग्रेडेशन कार्य के लिए 33 करोड़ 8 लाख रुपए स्वीकृत किए गए।

मप्र में लोक निर्माण विभाग हर साल मकानों, पुल-पुलियों और सड़कों का निर्माण करवाता है। निर्माण की आपा-धापी में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन जबसे विभाग के प्रमुख सचिव सुखबीर सिंह बने हैं, उन्होंने गुणवत्ता पर सबसे अधिक फोकस किया है। विगत दिनों उन्होंने पीडब्ल्यूडी द्वारा बनवाए जा रहे एक सैकड़ा से अधिक मकानों और सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने मकानों के कॉलम और सड़कों को खुदवाकर उनकी गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान उन्होंने चीफ इंजीनियरों को निर्देश भी दिया कि अमानक निर्माण तनिक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

गौरतलब है कि चुनावी साल को लेकर प्रदेश सरकार भी अब अलर्ट मोड में आ गई है। इसको देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्यों की गति बढ़ा दी है। लेकिन निर्माण के दौरान किसी प्रकार की खामी न रह जाए इस पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रमुख सचिव ने सभी को निर्देशित कर दिया है। इसी कड़ी में गत दिनों उन्होंने 10-12 चीफ इंजीनियरों को लेकर निर्मित की जा रहीं सड़कों को खुदवाकर उसकी गुणवत्ता को देखा। सड़कों का निर्माण मानक के अनुसार हुआ है कि नहीं इस पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सुखबीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 1200 किमी सड़कें स्वीकृत की गई हैं। मार्च तक इनका टेंडर स्वीकृत हो जाएगा। बारिश से पहले 70 फीसदी काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बाकी 30 फीसदी चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा।

प्रदेशभर में जहां सड़कें खराब हो गई हैं या फिर नए सिरे से निर्माण कराया जाना है, उसको लेकर लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सर्वे कराने के साथ ही निर्माण की तैयारी कर ली गई है। शहरों की सड़कों के कायाकल्प अभियान के अंतर्गत निकायों को सड़कों के उन्नयन के लिए आबादी के मान से राशि दी जाएगी। उन सड़कों का उन्नयन प्राथमिकता से किया जाएगा, जिन पर आवागमन अधिक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी नगरों की अंदरूनी सड़कों को ठीक करने के लिए राज्य सरकार ने राशि उपलब्ध कराई है। इन्हें ठीक रखना नगरीय निकायों का दायित्व है। इसे पूरा करने के लिए ही राज्य सरकार ने कायाकल्प अभियान शुरू किया है।

गौरतलब है कि गत दिनों मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 413 नगरीय निकायों को कायाकल्प अभियान के तहत 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। पहली किश्त के तौर पर 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को ट्रांसफर किए। कार्यक्रम से सभी 413 नगरीय निकाय जुड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर, मंदसौर, जौरा, रामपुर नैकिन और धनपुरी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों से संवाद भी किया। सड़कों के रखरखाव का कार्य समयसीमा में होगा। 15 से 20 दिन में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एजेंसी निर्धारित कर मई तक सभी सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे बारिश में नागरिकों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र ने पूरे देश में स्वच्छता के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। मार्च में स्वच्छता सर्वेक्षण फिर शुरू होगा। सभी नगरीय निकाय इस दिशा में प्रयास शुरू करें। नगरों में वार्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए प्रतियोगी भावना होनी चाहिए। इसमें रहवासी संघों और नागरिकों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

कायाकल्प अभियान में नगरीय निकायों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जनसंख्या के आधार पर पैसा दिया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को 25 करोड़, 2 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़, 1 से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़, 50 हजार से 1 लाख तक की जनसंख्या पर 2 करोड़ 50 लाख, 30 से 50 हजार तक की जनसंख्या पर 1 करोड़ 60 लाख, 20 से 30 हजार तक की जनसंख्या पर 1 करोड़ और 20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरों को 50 लाख रुपए दिए गए हैं। कार्यों की निगरानी के लिए राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति बनाई गई है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए संभाग स्तर पर **मोबाइल टेस्टिंग लैब बनाई** है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स मनोनीत किए हैं। शहरों में कार्यों की निगरानी के लिए संचालनालय और संभाग स्तर पर समिति का गठन किया जा रहा है।

● **जितेंद्र तिवारी**

माननीयों के खिलाफ जांच में आएगी तेजी!

पंजाब और हरियाणा कोर्ट

पंजाब और हरियाणा ने जिस तरह से पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों पर दर्ज मामलों में क्या रुख अपनाया है उसे देखते हुए जल्द ही दोनों राज्यों की सरकारें इस दिशा में सक्रिय होंगी। राज्य स्तर पर होने वाली जांचों में न केवल तेजी आएगी वरन जांच के बाद ट्रायल के लिए जरूरी मंजूरी के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे। उच्च न्यायालय के दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को ही पेश होने के समन नहीं समझा जाना चाहिए। यह दोनों राज्य सरकारों को भी एक तरह से नसीहत है। चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश है। लिहाजा यहां के पुलिस महानिदेशक को भी अपने क्षेत्र से जुड़े मामलों की स्टेट्स रिपोर्ट आगामी सुनवाई के दौरान दाखिल करनी है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ बढ़ते मामले और लंबित जांच गंभीर मामला है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिस तरह से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है उसे देखते हुए अन्य राज्यों में निकट भविष्य में हलचल हो सकती है। बरसों से बचते आ रहे कई जनप्रतिनिधि अब कठघरे में आएंगे।

मौजूदा और पूर्व सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों पर दर्ज मामलों में धीमा जांच और अनावश्यक देरी पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी की है। इन मामलों में पुलिस के रुख पर नाराजगी जताते हुए दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को फरवरी में होने वाली सुनवाई के दौरान निजी तौर पर पेश होकर पूरी स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। न्यायालय के अनुसार, आखिर पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ जांच तय समय में पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। ये जनप्रतिनिधि क्या आम लोगों से अलग है? जब कानून सभी के लिए बराबर है, तो फिर इनके मामलों में अनावश्यक देरी की कुछ तो वजह होगी। सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मामलों में सरकारी स्तर पर मंजूरी तय समय में हासिल कर ली जाती है, तो फिर जनप्रतिनिधियों के मामले में लंबा समय क्यों लगता है। विभिन्न राज्यों में मौजूदा और पूर्व सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में लेट-लतीफी पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया था।

देश के सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों से अपने अधिकार क्षेत्र के ऐसे मामलों की पूरी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। इसे देखते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान के आधार पर वर्ष 2021 में इस मामले की सुनवाई शुरू की। तब पंजाब में 96 पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों पर प्राथमिकी दर्ज थी। तब तक 12 प्रतिशत मामलों का ट्रायल भी नहीं हुआ था और 88 प्रतिशत मामलों की जांच जारी थी। कुल 163 में से 118 मामलों की जांच ही चल रही थी। लगभग दो साल के बाद स्थिति में कुछ सुधार जरूर हुआ है; लेकिन जनवरी 2023 में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में इसे असंतोषजनक पाया। न्यायालय ने कहा कि दोनों राज्यों की ओर से पेश किए गए हलफनामे में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था, जबकि उन्हें पूरी स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। बार-बार समय मांगने और स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करना बिलकुल गलत है। टिप्पणी में कहा गया कि आखिर जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले अंतिम निष्कर्ष पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? हलफनामे में जो कुछ बताया गया है, वह हकीकत में तर्कसंगत क्यों साबित नहीं हो रहा। फरवरी में होने वाली सुनवाई के दौरान पंजाब के पुलिस महानिदेशक को जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की न केवल पूरी सूची और स्थिति के बारे में बताना होगा, बल्कि उन कारणों का भी हवाला देना होगा, जिसके चलते जांच अधूरी है। पंजाब में पूर्व और मौजूदा सांसदों-विधायकों के लगभग 99 मामले विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, जबकि 42 मामलों की जांच चल रही है, जबकि हरियाणा में 11 ऐसे मामले लंबित हैं। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की बढ़ती संख्या, राज्य सरकारों, राज्य पुलिस और जांच एजेंसियों की निष्क्रियता पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया था।

विभिन्न राज्यों से सूचियां मिलने के बाद कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों ने निर्देश और मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे मामलों में जांच किस तरह से होती है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हरियाणा में ऐसे ही जनप्रतिनिधि के खिलाफ वर्ष 2005 में नौकरी के लिए चयन में अनियमितताओं और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, जबकि यह संदर्भ 2001-2002 का था। यानी तीन साल से ज्यादा समय प्राथमिकी दर्ज करने में ही लग गया। इस मामले की जांच में ही बरसों लग गए, जाहिर है ये लंबे समय तक अदालतों में भी चलेगा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों में ज्यादातर की जांच राज्य पुलिस की एजेंसियां ही कर रही हैं, इसलिए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठना लाजिमी ही है। पर क्या सभी मामलों मे पुलिस ही एकमात्र निर्णायक की भूमिका में होती है। बहुत-से मामलों में पुलिस को मामला दर्ज करने से पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसी अड़चनों के चलते कुछ मामलों में देरी हो सकती है, लेकिन आपराधिक मामलों में पूरे साक्ष्य मिलने के बाद भी जांच सुस्त रफ्तार से चलती है, तो संदेह होना स्वाभाविक ही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी पुलिस और सरकारी सिस्टम पर है। इसमें सुधार करना ही होगा, शायद इसीलिए न्यायालयों की टिप्पणियां काफी तल्ख होती हैं। पंजाब में एक पूर्व विधायक के खिलाफ जांच पूरी हो गई, लेकिन ट्रायल के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ी। ऐसे ही जनप्रतिनिधि सिमरजीत सिंह बैंस और उनके भाई बलविंदर सिंह बैंस के खिलाफ विभिन्न मामलों में एक दर्जन के करीब प्राथमिकियां दर्ज हैं। जनप्रतिधियों के खिलाफ देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं के तहत दर्ज मामले की जांच चल ही रही है, किसी निष्कर्ष पर कब पहुंचेगी क्या पता? हर राज्य में पूर्व या मौजूदा सांसदों और विधायकों पर मामले दर्ज होते हैं। इनमें काफी कुछ राजनीतिक भी होते हैं। मामला बहुत संगीन न हो, तो उनकी जांच राज्य पुलिस ही करती है। विरोधी को सबक सिखाना हो, तो सरकार का समर्थन होने पर ऐसे मामलों की जांच त्वरित गति से चलती है और तय समय में सबकुछ हो जाता है, लेकिन यही बात सत्तापक्ष से जुड़े किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ हो तो जांच की दिशा और दशा क्या होगी? इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है।

● **बृजेश साहू**

> *राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी बड़े शहरों में कलेक्टर गाइडलाइन की दरें तय की जा रही हैं, लेकिन 1 अप्रैल से ये दरें लागू होंगी कि नहीं इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि चुनावी साल में सरकार जनता पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती है।*

कलेक्टर गाइडलाइन पर असमंजस

राजधानी में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों की दरें 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। लेकिन सरकार इस साल कलेक्टर गाइडलाइन लागू करने के मूड में नहीं है। दरअसल, चुनावी साल में सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे जनता में असंतोष बढ़े। ऐसे में सरकार जमीनों की दरें बढ़ाने से बच रही है। यही कारण है कि इस बार राजधानी में शहरी क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ दिया गया है। सिर्फ कुछ लोकेशन में बढ़ोत्तरी की गई हैं, यह वो लोकेशन हैं, जहां पूर्व में बढ़ोत्तरी नहीं की गई थी। ऐसे में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र को नहीं छेड़ा जा रहा है।

प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन में महज 100 लोकेशन में बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई है। यह वो क्षेत्र हैं, जो नगर निगम सीमा से लगे ग्रामीण इलाके हैं। यहां बढ़ी दरों पर जमीनों की खरीद-फरोख्त हो रही है। इसी को आधार बनाते हुए 10 फीसदी दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही 14 लोकेशन वो हैं, जहां 20 फीसदी तक दरें बढ़ाई जा सकती हैं। अफसरों का तर्क है कि यहां दरें काफी कम हैं और खरीदी अधिक दरों पर हो रही है। बीते दिनों हुई उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में पंजीयन विभाग के अफसरों ने प्रस्ताव रखा था।

कलेक्टर गाइडलाइन में इस बार जमीनों के रेट बढ़ाने का जो **प्रस्ताव पंजीयन** अफसरों ने तैयार किया है उसमें नए प्रोजेक्ट के साथ दुकानों, मार्केट में अधिक दर पर हुई रजिस्ट्री को भी शामिल किया है। ऐसा करोंद और नीलबड़ क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिला है। यहां कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक दर पर बिकी दुकान को आधार बनाकर रेट बढ़ाना प्रस्तावित किए हैं। खास यह है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण भी लोगों का मकान का सपना महंगा हो रहा है। दो रूट पर दोनों तरफ जमीन के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पंजीयन विभाग के अफसरों के अनुसार ऐसे ही कुछ क्षेत्रों की कई लोकेशनों पर रजिस्ट्री भी अधिक दरों पर हुईं हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों को नवविकसित क्षेत्र मानते हुए यहां की कई लोकेशनों पर 5 से 10 फीसदी रेट बढ़ाने की तैयारी है। ऐसे ही रायसेन रोड पर भी तेजी से विकास हो रहा है। जाटखेड़ी, मिसरोद, दानिश नगर, कोलार में भी अच्छी खरीद फरोख्त हुई है, यहां जमीनें पहले से ही काफी महंगी हैं। इस कारण यहां बढ़त कम ही तय की गई है। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिन वार्डों में स्थित है वहां पर ट्रैक के दोनों तरफ 50 मीटर जगह छोड़कर कई लोकेशनों पर नई दरें प्रस्तावित की जा रही हैं। इससे करीब नौ वार्डों की जमीन के रेट पर असर पड़ेगा। यहां 5 से 15 फीसदी की बढ़त प्रस्तावित की जा रही है। शहरी सीमा में ही करीब 22 के लगभग नए क्षेत्र और ग्रामीण एरिया में 8 से 10 नए क्षेत्र इस बार कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल किए जा रहे हैं, जहां नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आसपास की चार कॉलोनियों के एक रेट जहां पर हैं वहां की लोकेशन को मर्ज कर दिया है।

शहर में कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जमीनों के रेट अब सेचुरेशन की स्थिति में है। खरीद फरोख्त इनमें भी हुई, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन से थोड़े बहुत अंतर पर सौदे हुए हैं। क्योंकि पहले ही यहां काफी रेट हैं। ऐसे क्षेत्रों में एमपी नगर, सुभाष नगर, अशोका गार्डन, अरेरा कॉलोनी, लिंक रोड नंबर एक, नर्मदापुरम रोड, कोलार, टीटी नगर, न्यू मार्केट, कोहेफिजा, वीआईपी रोड की प्रॉपर्टी व कई कमर्शियल प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। कलेक्टर गाइडलाइन में पहली बार बैरसिया क्षेत्र की लोकेशन में बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं। इसमें लांबाखेड़ा से लगे गांव हैं। यहां पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण तो हो रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में उद्योग भी लग रहे हैं। जिससे यहां खरीदी-बिक्री तेजी से बढ़ी है। इसमें अगरिया छापर पिपरिया जाहीर, निपानिया, गोलखेड़ी बीनापुर, दीपाडिया, खामखेडा, ईंटखेडी सहित अन्य में अधिकतम 10 फीसदी बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं।

ऐप आधारित कलेक्टर गाइडलाइन के लिए सब रजिस्ट्रार की तरफ से पॉलीगोन ड्रॉ तैयार किए गए हैं। नगर निगम के वार्ड स्तर पर तैयार किए जा रहे पॉलीगोन (एक ऐसा घेरा जिसमें प्लॉट की चारों दीवारें अंकित होती हैं) में कॉलोनी काटते समय की गईं विसंगतियां सामने आई हैं। गूगल की मदद से तैयार किए जा रहे पॉलीगोन ड्रॉ में नर्मदापुरम रोड पर ही चार कॉलोनी ऐसी सामने आई हैं जिनमें कॉलोनी की दीवारें सरकारी नाले तक पहुंच गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पूर्व की विसंगतियां हैं जो अब पकड़ में आ रही हैं। ऐसे ही अतिक्रमणों की संख्या बढ़ती है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

बन रहीं अवैध कॉलोनियां

ग्रामीण क्षेत्रों में महंगे बिक रहे प्लॉट, रजिस्ट्री कम दर पर चालू वित्तीय वर्ष में शहर से लगे ग्रामीण इलाकों में बन रही अवैध कालोनियों में सबसे अधिक जमीनों की खरीद-फरोख्त हुई है। पंजीयन अफसरों की पड़ताल में इसका खुलासा हुआ। गाइडलाइन कम होने के कारण इन क्षेत्रों में कम दरों पर रजिस्ट्री हो रही है, जबकि प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त अधिक दरों पर की जा रही है। उधर फंदा ब्लॉक में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी दरें प्रस्तावित की गई हैं। इसमें बैरागढ़ कला, सिकंदराबाद, नीलबड़, रातीबड़, नाथू बरखेड़ा, कलखेड़ा, नीलबड़, बेरखेड़ी बजायपत्ता, बेरखेड़ी, सेमरी, सुरैया नगर, देहरी कला में 10 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है।

असंतुष्टों को मिलेगी जिम्मेदारी

विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, इनके पहले असंतुष्ट नेताओं का महत्व बढ़ जाता है। इसी कड़ी में मप्र में कांग्रेस का फोकस अपने असंतुष्ट नेताओं पर है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस अपने हर नेता को साधने में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव में नेताओं की नाराजगी भारी न पड़े, इसलिए कांग्रेस असंतुष्ट नेताओं को प्रदेश संगठन में स्थान देकर उन्हें मनाएगी। इसके लिए ऐसे नेताओं को चिह्नित किया जा रहा है, जो संगठन में महत्व न मिलने के कारण नाराज हैं और घर बैठ गए हैं। साथ ही प्रदेश और जिला स्तर पर हुई नियुक्तियों से जो असंतोष पनपा है, उसे थामने के लिए भी प्रदेश सचिव, सह सचिव पद पर नियुक्ति की जा सकती है। वैसे भी अभी प्रदेश इकाई में केवल उपाध्यक्ष और महामंत्री ही नियुक्त किए गए हैं।

चुनावी साल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुट में बंट जाना पार्टी की जीत में कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। इसलिए पार्टी सभी नेताओं को साधने में जुट गई हैं। खासकर असंतुष्ट नेताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभी जिलों में पंगत में संगत कार्यक्रम किए थे। इसमें उन्होंने विभिन्न कारणों से नाराज चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं की न केवल सुनवाई की थी बल्कि उन्हें पार्टी हित में काम करने के लिए तैयार भी किया था। साथ ही पार्टी ने नाराज कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए प्रदेश इकाई में पदाधिकारी भी बना दिया था। हालांकि, इसके कारण संगठन पदाधिकारियों की संख्या सैकड़ों में पहुंच गई थी, जिसको लेकर भाजपा नेता आज तक कांग्रेस पर तंज कसते हैं। रायपुर में होने वाले अभा कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन से पूर्व एआईसीसी के सदस्यों की सूची प्रकाशित हुई है। इस बार मप्र से 99 सदस्य का चयन किया गया है, जबकि पिछली बार प्रदेश से 135 सदस्य बनाए गए थे। दरअसल, वर्ष 2017 में एआईसीसी से तय संख्या से अधिक ब्लॉक स्वीकृत होने की प्रत्याशा में अतिरिक्त सदस्य बना लिए गए थे। इससे संख्या 135 हो गई। इस बार उम्मीद थी कि सदस्यों की संख्या 135 से भी अधिक हो जाएगी और उसी हिसाब से करीब दो सौ नाम भोपाल से दिल्ली भेजे गए, पर एआईसीसी ने मप्र के लिए तय कोटे से अधिक सदस्य नहीं बनाए।

कुछ दिनों पूर्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और जिला इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए विनय बाकलीवाल के समर्थकों ने इसको लेकर विरोध किया। इसी तरह सागर में भी प्रदर्शन हुआ। खंडवा शहर और ग्रामीण के अध्यक्ष को लेकर शिकायत दिल्ली तक पहुंची और नियुक्ति को रोकना पड़ा। विरोध-प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए संगठन के प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने बयान दिया कि यह कोई अंतिम सूची नहीं है। इसमें संशोधन भी होगा और इसे विस्तार भी दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश इकाई में अभी सचिव, सह-सचिव सहित अन्य पदों पर नियुक्तियां होना बाकी हैं। इसमें उन सभी नेताओं को समायोजित किया जाएगा जो संगठन में उचित महत्व न मिलने के कारण नाराज हैं और घर बैठ गए हैं। चुनाव के समय में पार्टी किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी सभी बैठकों में कहते हैं कि जो नाराज हैं, उन्हें मनाएं। समन्वय बनाकर काम करें। हालांकि पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा का कहना है कि कोई भी असंतुष्ट नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में सभी आस्था जता चुके हैं। सबकी योग्यता का सम्मान करते हुए उन्हें उचित स्थान भी दिया जाएगा। कांग्रेस के अंदर खींचतान तलाशने वालों को पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आईना दिखा दिया है। पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में जुटी है। हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस को जन आशीर्वाद मिलेगा।

गौरतलब है कि पिछले चुनावों के पहले असंतुष्टों के इधर-उधर होने से भाजपा और कांग्रेस ने माहौल को बदला था। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने कांग्रेस को बड़े झटके दिए थे जिससे भागीरथ प्रसाद व उदयप्रताप सिंह जैसे नेताओं ने बाजी पलटी थी। इसी तरह खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला ने मंच पर कांग्रेस से दामन तोड़ लिया था। वहीं, विधानसभा चुनावों में भी भाजपा सांसद व पूर्व मंत्री सरताज सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाते ही सरताज सिंह फिर भाजपा में चले गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले संजय सिंह ने भी विधानसभा चुनाव 2018 के ठीक पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया था। पूर्व मंत्री संजय पाठक भी इसी तरह कांग्रेस का साथ छोड़ गए थे तो चौधरी राकेश सिंह की नाराजगी का भी भाजपा ने फायदा उठाते हुए उन्हें अपने साथ ले लिया था। मगर चौधरी राकेश सिंह बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से विधानसभा चुनाव के पास कांग्रेस में लौट आए थे लेकिन उनके भाजपा में जाते ही चौधरी के मुखर विरोधी अजय सिंह की वजह से काफी समय तक उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े होते रहे। प्रदेश में इसी तरह की स्थिति जिलों में भी है। इसलिए कांग्रेस ने असंतुष्ट नेताओं को साधने की कवायद तेज कर दी है।

● **अरविंद नारद**

कांग्रेस में मची कुर्सी की दौड़

विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर कुर्सी की लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं ये तय नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर हर क्षत्रप की नजर और दावा है। भावी मुख्यमंत्री को लेकर नेताओं के अलग-अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। मप्र कांग्रेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बता रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह समर्थक और कमलनाथ विरोधियों को ये बात रास नहीं आ रही है। इसके विरोध में धीरे-धीरे नेता इकट्ठे होते जा रहे हैं। अगर कांग्रेस मप्र में विधानसभा चुनाव जीती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर कांग्रेस में मारामारी की स्थिति होने लगी है। नेता अरुण यादव के बाद अजय सिंह के बयानों ने पार्टी के अंदर के सियासी पारे को उछाल दे दी है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सबसे पहले कहा- पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तय नहीं है। चुनाव में नंबर आने के बाद पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।

मप्र में संत-बाबा अब नेताओं के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच बनते जा रहे हैं। वोटर्स को साधने से लेकर टिकट में दावेदारी तक में नेताओं के लिए संत-बाबा पर्दे के पीछे से मदद करते हैं। इतना ही नहीं, वे नेता को पूरा संरक्षण भी देते हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से प्रज्ञा ठाकुर मैदान में थी, तब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी बताया था। इसके बाद दिग्विजय सिंह के समर्थन में हजारों संत राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतर आए थे।

कथानीति की राजनीति

मप्र में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की भगवान और साधु-संतों के दर पर परिक्रमा शुरू हो गई है। इससे संतों का महत्व भी बढ़ गया है और ये संत अपने कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं की भीड़ बुलाकर अपनी वोट की ताकत का अहसास करा रहे हैं। इससे चुनावी साल में वोट बटोरू संतों की महत्ता बढ़ गई है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि प्रदेश की करीब एक सैकड़ा से अधिक विधानसभा सीटों पर संतों का प्रभाव दिख रहा है। मप्र देश का हृदय प्रदेश होने के कारण यहां के लोगों में धर्म के प्रति अधिक आस्था देखी जाती है। लोगों की आस्था को देखते हुए यहां समय-समय पर साधु-संतों का उभार होता रहता है। वर्तमान में तीन कथावाचकों बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का प्रदेश की जनता पर अधिक प्रभाव है। बाबाओं के प्रभाव का असर यह है कि सत्तापक्ष हो या विपक्ष या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी सभी के नेता इन बाबाओं के दरबार में शरणागत हैं। वहीं अपने-अपने क्षेत्रों में विधायक और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं और नए वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। मतदाताओं को अपने पाले में लेने के लिए मंत्री-विधायकों ने नए-नए हथकंडे अपनाने भी शुरू कर दिए हैं। चुनावी साल आने से पहले ही पार्टी नेता ने अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन कराकर जनता को खुश करने का प्रयत्न किया।

प्रदेश में संतों और बाबाओं के प्रभाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों के जरिए मैदान में अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। राज्य में जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे बाबाओं के दरबार में नेताओं की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। अपने-अपने इलाकों में मंत्री से लेकर विधायक तक उनकी कथाओं के जरिए वोटर्स को साधने में लगे हैं। नेता अपनी छवि बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने में लगे हैं। शिवराज सरकार के कई मंत्री अपने-अपने क्षेत्र में कथा करा चुके हैं तो कुछ वेटिंग लिस्ट में हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा ही धार्मिक आयोजन कर राजनीतिक पुण्य प्राप्ति का जतन कर रही है, कांग्रेस के बड़े नेता भी इन बाबाओं की कथा से राजनीतिक प्रसाद हासिल करने में लगे हैं। प्रदेश में बीते कुछ महीनों के अंदर कई सैकड़ा धार्मिक कथाओं का आयोजन हो चुका है। इनमें से अधिकांश कथाएं नेताओं द्वारा आयोजित कराई जा रही हैं। इसमें तीन कथावाचकों बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा और पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा का प्रदेश की एक सैकड़ा से अधिक विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि अधिकांश मंत्री और विधायक इन बाबाओं के दरबार में शरणागत हैं। वहीं गत दिनों राजधानी भोपाल में भी जया किशोरी की कथा सुनने वालों की तादाद काफी अधिक थी।

चुनावी साल में प्रदेश के अधिकांश नेता कथानीति के सहारे समीकरण साधने में जुटे हुए

तीन दिन की कथा में पांच करोड़ का खर्च

जानकार कहते हैं कि कोई भी कथा या सम्मेलन यदि तीन दिन से अधिक का होता है तो उसका खर्च 4 से 5 करोड़ रुपए तक जाता है। इस तरह इस बार आयोजनों पर 200 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है। भाजपा के पूर्व मंत्री आरडी प्रजापति कहते हैं कि मप्र में जितनी राशि विकास कार्यों में खर्च होती है, उससे ज्यादा की नेटवर्थ 5 बाबाओं की है। कथा का आयोजन कराने वाले भाजपा नेताओं में पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस भी शामिल हैं, जो पिछला विधानसभा चुनाव बुरहानपुर से हार गई थीं। उन्होंने हाल ही में पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन बुरहानपुर में कराया था। वे कहती हैं कि मैं पिछले 15 साल से धार्मिक आयोजन कराती आ रही हूं। इस तरह के आयोजनों के पीछे उन्होंने दो प्राथमिक कारण बताए, पहला- लोगों को एक आदर्श नागरिक बनाने में मदद करना है। जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज को एक आदर्श स्थान बनाएं, जिसमें धर्म और संस्कृति लोगों के जीवन का हिस्सा हो। इन कथाओं में लाखों लोग हिस्सा लेते हैं और उन्हें एक नैतिक दिशा मिलती है। दूसरा- सामाजिक स्तर पर विभाजन को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि जब लोग एक कथा में शामिल होते हैं, तो अपने जातिगत पूर्वाग्रहों और शिकायतों को भूल जाते हैं। यह सामाजिक समरसता कायम करने में मदद करता है। चिटनिस कहती हैं कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, तो लोग आपका समर्थन करने को तैयार रहते हैं।

हैं। मप्र में लगभग सभी नेता भक्ति रंग में रंग गए हैं और वोटरों को इसी रंग के सहारे साधने में जुट गए हैं। चुनावी साल में मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए मंत्रियों की राजनीतिक कथानीति शुरू हो गई है। चुनावी साल में शिवराज के मंत्री भागवत कथाएं करा रहे हैं। इस कड़ी में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में जुलाई 2022 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा व पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन करवाया था। इसमें प्रतिदिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंचे। जल ससांधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर स्थित सिंगापुर सिटी में दिसंबर 2022 तक कथा वाचक मदनमोहन महाराज की कथा करवाई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में दिसंबर 2022 में जया किशोरी की श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करवाया था। पीडल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने सागर के गढकोटा में दिसंबर 2022 में मलूक पीठाधीश्वर जगद्गुरु देवाचार्य राजेंद्र व्यास की कथा करवाई। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई के गुलाबरा बगीचा में दिसंबर 2022 में संत कमल किशोर नागर की कथा करवाई थी। राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने भिंड के दंदरौआ धाम में नवंबर 2022 में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई। विधायक राम दांगोरे ने खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में दिसंबर 2022 में देवी कृष्णदासी आरती दुबे की कथा करवाई। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने अशोकनगर के नई कृषि उपज मंडी परिसर में नवंबर 2022 में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाई थी। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करवाई। सांसद केपी यादव ने अशोकनगर के मोहरी पठान नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में सितंबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई।

चुनावी साल में कांग्रेसी नेता भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। इन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में कथाएं कराई हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोट ने जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नंवबर 2022 में जया किशोरी द्वारा रामकथा का

आयोजन कराया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राऊ में जुलाई 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा कराई। क्षेत्र में रामायण की एक लाख प्रतियां बांटी। विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर के दलाल बाग किला मैदान पर नंवबर 2022 में प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। विधायक अजय टंडन ने दमोह में होमगार्ड मैदान पर 24 दिसंबर से 1 नंवबर तक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया। विधायक शशांक भार्गव ने विदिशा के रामलीला मेला परिसर में नंवबर 2022 में दीदी ऋचा गोस्वामी की कथा करवाई।

पार्टियों में हिंदुत्व और धार्मिकता को लेकर भले ही संग्राम छिड़ा रहता है, लेकिन बाबाओं का दरबार सबके लिए खुला रहता है। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को आजकल सनातन धर्म का पोस्टर बॉय कहा जा रहा है। उनके धार्मिक कार्यक्रमों में आस्था रखने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इनका बुंदेलखंड सहित अन्य इलाकों में भी अच्छा प्रभाव है। वहीं कुबेरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा मालवा-निमाड़, भोपाल और नर्मदापुरम अंचल में लोकप्रिय हैं। इसी तरह पंडोखर सरकार गुरुशरण शर्मा पर आस्था रखने वाले ग्वालियर-चंबल और भोपाल संभाग में ज्यादा हैं। इस कारण प्रदेश में इन बाबाओं की कथाएं कराने की होड़ मची हुई है। बाबाओं के प्रभाव को देखते हुए आगामी दिनों में कई अन्य नेता इनकी कथाएं कराने की तैयारी कर रहे हैं। कमलनाथ जल्द ही अपने गढ़ छिंदवाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाने जा रहे हैं, इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज की कथा कराएंगे। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाने की तैयारी कर रहे हैं। मंत्री रामकिशोर कांवरे परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में धीरेंद्र शास्त्री द्वारा भागवत कराएंगे। विधायक इंदु तिवारी जबलपुर के पनागर में मार्च के अंतिम सप्ताह में धीरेंद्र शास्त्री की कथा कराएंगे। जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है।

शिवराज सरकार में कृषि मंत्री रहे गौरीशंकर बिसेन कथा कार्यक्रम की मेजबानी करने की तैयारी में हैं। बिसेन के मुताबिक यह लोगों तक पहुंचने और उन्हें भगवान से जोड़ने का एक जरिया है। कथा-प्रवचन लोगों को खुश करते हैं और इससे उनका अपने स्थानीय प्रतिनिधि के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है। लोग किसी भी सार्वजनिक-राजनीतिक बैठक से ज्यादा ऐसे आयोजनों को याद रखते हैं।

● **प्रवीण सक्सेना**

आसानी से जुटा सकते हैं 5 लाख तक की भीड़

शिवराज कैबिनेट के एक अन्य मंत्री ने स्वीकारा कि राजनीतिक बैठकों की तुलना में धार्मिक आयोजनों में भीड़ को आकर्षित करने की ताकत अधिक होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बैठकों में हम 1 लाख से अधिक लोगों को नहीं जुटा सकते हैं, लेकिन ऐसे आयोजनों में हम 5 लाख लोगों तक को बड़ी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अंततः ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता और मतदाता लामबंद होते हैं। यह गुजरात में एक बड़ी सफलता थी और इसे गंभीर चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले की तैयारी गतिविधियां माना जा सकता है। गौरतलब है कि गुजरात चुनाव से महीनों पहले कई भाजपा नेताओं ने धार्मिक कार्यक्रमों की मेजबानी की थी, जिसे विपक्षी दल कांग्रेस ने सरोगेट अभियान बताकर इसकी आलोचना की थी। मप्र में भाजपा के नेता भी कथा-भागवत फॉर्मूला अपनाते दिख रहे हैं। वहीं, कांग्रेस के नेता भी इसी तरह के आयोजन करते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सच्चाई यह है कि अधिकांश नेताओं का जमीनी ताल्लुक बचा ही नहीं है। वे हवा में चलते हैं और उनकी राजनीति कंसल्टेंट चलाते हैं। टिकट से लेकर मुद्दे तक सर्वे में तय हो रहे हैं। दरअसल, जमीनी कार्यकर्ता या वोटर्स से नेताओं का संपर्क बचा ही नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों से चुनाव में कोई राजनीतिक लाभ नेताओं को नहीं मिलता। इतना जरूर है कि नेताओं की कमाई खर्च होती है। उन्होंने आगे कहा कि किसी बाबा द्वारा किसी नेता की तारीफ करने से वोट नहीं मिलता।

पैक्स को मजबूत करेगी सरकार

मप्र में सहकारिता से उन्नति का पथ प्रशस्त हो रहा है। सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को खरीफ और रबी फसल के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने, उन्नत बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने के साथ समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं, धान आदि फसलों का उपार्जन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग में विभिन्न क्षेत्रों में रजिस्टर्ड समितियां स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। अब प्रदेश की 4,534 सहकारी समितियां केंद्र की योजना में शामिल होंगी। इसके लिए सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित सहकारिता विभाग को और प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से एक प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की कंप्यूटराइजेशन गति बढ़ाना है। इस निर्णय से मप्र की 4,534 साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन का रास्ता खुल गया है। सभी समितियों के लिए विभाग ने पहले से 145 करोड़ का प्लान तैयार किया है और पिछले साल केंद्र सरकार से पहली किस्त के तौर पर 6 करोड़ की राशि भी हासिल कर चुका है। जानकारी के अनुसार साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करने के लिए दो साल पहले सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की पहल पर सबसे पहले 11 फरवरी 2021 को एक प्रस्ताव प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति में लाया गया। बैठक में बताया गया था कि प्रोजेक्ट पांच साल के लिए है और इसके लिए करीब 145 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 70.37 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के कुछ समय बाद केंद्र सरकार की योजना सामने आई कि देश की 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन के लिए 2,516 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार को 19 जुलाई 2022 को पत्र लिखते हुए साधिकार समिति की बैठक में मिली सैद्धांतिक सहमति की जानकारी दी। सहकारिता आयुक्त आलोक कुमार सिंह का कहना है कि केंद्र के बजट में किए गए प्रावधान के अनुसार उम्मीद है कि अब प्रदेश की सभी 4,534 साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हो सकेगा। विभाग इसके लिए पिछले एक साल से प्रयास कर रहा है। केंद्र से परियोजना को मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। 75 लाख किसानों का डेटा तैयार होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंधित 4,534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं (पैक्स) कार्यरत हैं। 4,534 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए कुल लागत 144.75 करोड़ का व्यय भार आएगा, जिसकी 60 प्रतिशत राशि 86.85 करोड़ केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि 57.90 करोड़ राज्य शासन देगा। प्रदेश में लगभग 75 लाख कृषक इन समितियों के सदस्य हैं। समितियों के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यावधि एवं दीर्घावधि कृषि ऋण वितरण एवं वसूली, किसान क्रेडिट कार्ड का संचालन, बचत बैंक, बचत काउंटर, किसानों को खाद, बीज उपलब्ध कराना। उपार्जन, पीडीएस के लिए खाद्यान्न, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरी, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाएं आदि बेचने का काम होता है। भारत सरकार की पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना में प्रति पैक्स 3,91,369 रुपए लागत अनुमानित की गई है। इसमें सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी और डाटा स्टोरेज, हार्डवेयर, डिजिटलाइजेशन, सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग शामिल है। 8 जुलाई 2022 को सचिव सहकारिता भारत सरकार की अध्यक्षता में एनएलएमआईसी की पहली बैठक वीसी द्वारा हुई। सचिव के निर्देश पर प्रदेश की सभी पैक्स का वार्षिक ऑडिट कराया गया। विभाग ने वर्ष 2022-23 के विभागीय बजट में 20 करोड़ रुपए और पहले अनुपूरक अनुमान में 38 करोड़ का प्रावधान किया। विभाग के प्लान को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी और पहली किस्त के तौर पर 6.46 करोड़ रुपए जारी कर दी। इसकी जानकारी सहकारिता मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर 2022 को पत्र के माध्यम से दी गई। परियोजना को मंजूरी दूसरी नेशनल लेवल मॉनीटरिंग एंड इम्पलीमेंटेशन कमेटी की बैठक में मिली।

● **राकेश ग्रोवर**

पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य

सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पैक्स को सशक्त करने के लिए आईटी से जोड़ा जा रहा है। मप्र पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश की सभी 4 हजार 534 पैक्स का कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 177 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन को अगले 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। पैक्स में माइक्रो एटीएम की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। नाबार्ड की सहायता से 29 जिला सहकारी बैंक की शाखाओं और उनसे संबद्ध पैक्स में 4 हजार 628 माइक्रो एटीएम की स्थापना की जा रही है। माइक्रो एटीएम से पैक्स तक बैंकिंग सुविधा का विस्तार हो सकेगा। सहकारिता विभाग द्वारा अनेक क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी संस्थाओं को फेसिलिटेट भी किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 10 हजार से अधिक महिला बहु-प्रयोजन सहकारी समितियों का गठन सहकारिता विभाग द्वारा किया गया है। ग्रामीण उद्योग और परिवहन, उद्यानिकी, पर्यटन, खनिज, श्रम, सेवा-प्रदाता आदि नए क्षेत्रों में भी विभाग द्वारा 814 सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए नागरिकों द्वारा सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाता है। ऐसे नागरिकों के लिए सहकारी संस्थाओं के गठन को अधिक सुविधाजनक बनाने पंजीयन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। सहकारी संस्थाओं के ऑडिट आवंटन की प्रक्रिया को भी रेंडम तरीके से ऑनलाइन किया गया है। ऐसा करने वाला प्रदेश, देश का पहला राज्य है। सहकारिता में अधिकाधिक जन-समुदाय, विशेषकर युवाओं और महिलाओं को जोड़कर इसे जनआंदोलन का स्वरूप देने पर विभाग कार्य कर रहा है। सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मप्र के स्कूल होंगे चकाचक

मप्र सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ही अब स्कूलों के भवन को भी चकाचक करने जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने सरकारी स्कूलों के लिए 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से प्रदेश के जर्जर 6 हजार से अधिक स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। गौरतलब है कि मप्र सरकार का स्कूली शिक्षा विभाग हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल भवनों की हालत ठीक नहीं है। आलम यह है कि ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कई गांव में तो उचित क्षमता वाला भवन तक नहीं है। अब सरकार ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है।

गौरतलब है कि मप्र के 99,987 स्कूलों में 21 हजार स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हैं तो 18 हजार अधिक क्षतिग्रस्त पाए गए। वहीं करीब 2 हजार स्कूलों में विद्यार्थियों के बैठने के लिए कक्ष व पेयजल की व्यवस्था भी नहीं है। इसके साथ ही 1200 स्कूल शौचालय विहीन और 7 हजार में शौचालय बदहाल स्थिति में हैं। सरकार ने इनमें से 6048 जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया है। दो साल बाद इनकी मरम्मत के लिए बजट मंजूर किया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र ने सभी 52 जिलों में सरकारी स्कूलों के लिए 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्कूलों के सभी काम 31 मार्च 2023 तक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा रीवा, धार, सतना, छिंदवाड़ा जिले में स्कूल जर्जर हैं। अब उम्मीद जताई जा रही है कि नए सत्र में जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो उन्हें जर्जर स्कूल भवन कक्षाओं में नहीं बैठना पड़ेगा।

प्रदेश में 6048 जर्जर स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जो 150 करोड़ 49 लाख रुपए मंजूर की है उससे स्कूलों के दरवाजे, खिड़कियां, फर्श, टॉयलेट, छत, बाउंड्रीवॉल सहित अन्य काम कराए जाएंगे। जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम में शासकीय प्राथमिक शाला कोठी बाजार की हालत खराब है। दीवारों पर सीलन और जगह-जगह दरारें पड़ चुकी हैं। हद तो यह है कि बारिश के समय स्कूल की छत से पानी टपकता है। पॉलीथिन डालकर पानी से बचाव किया जाता है। वहीं हरदा के वार्ड 14 की प्राथमिक शाला शुक्रवारा की दीवारों पर जगह-जगह दरारें आ चुकी हैं। प्लास्टर झड़ चुका है। सीमेंट के टुकड़े आए दिन गिरते रहते हैं। खपरेलनुमा छत की मरम्मत नहीं होने से बारिश में पानी टपकता है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मप्र संचालक धनराजू एस 6048 सरकारी प्राइमरी-मिडिल स्कूलों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मार्च तक मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं।

मप्र में इस साल चुनाव होने हैं। जिसके चलते विकास का सरकारी प्रोपगेंडा शुरू हो चुका है। दावों और वादों की बाढ़ आ गई है, लेकिन प्रदेश की स्कूली शिक्षा का कोई माई बाप नहीं है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2015-16 में मप्र में सरकारी स्कूलों की संख्या 1,21,976 थी जो वर्ष 2021-22 में घटकर 92,695 रह गई। यानी पिछले पांच सालों में 29,281 सरकारी स्कूल बंद हो गए। वर्ष 2015-16 में मप्र में सरकारी स्कूलों में 1,03,60,550 विद्यार्थी एनरोल थे। ये आंकड़ा वर्ष 2021-22 में घटकर 94,29,734 रह गया। स्पष्ट है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की एनरोलमेंट में 9,30,816 की कमी आई है। वर्ष 2015-16 में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 3,44,372 थी जो वर्ष 2021-22 में घटकर 3,03,935 रह गई। यानी 40,437 शिक्षकों की कमी हुई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछले पांच सालों में सरकारी स्कूलों की संख्या, विद्यार्थियों के एनरोलमेंट और शिक्षकों की संख्या में भारी कमी हुई है। आंकड़े बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के मामले में फेल साबित हुई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-16 में मप्र के 4 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं थी। वर्ष 2021-22 तक इसमें मात्र 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अभी भी मप्र के 1,770 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। वर्ष 2015-16 में 10 प्रतिशत स्कूलों में पुस्तकालय नहीं थे जो आंकड़ा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया। यानी 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मप्र के 33,623 स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है। आप ये ना माने कि जहां पुस्तकालय हैं वहां पुस्तकें भी होंगी ही। मप्र के 35,451 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां किताबों वाली लाइब्रेरी नहीं है। वर्ष 2021-22 में ये संख्या 17,466 थी। वर्ष 2015-16 में मप्र के 84 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं थी। वर्ष 2021-22 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ और ये आंकड़ा 84 प्रतिशत से घटकर 57 प्रतिशत पर आ गया। लेकिन अभी भी मप्र के 52,888 स्कूलों में बिजली नहीं है। 2015-16 में मात्र 3 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी ये आंकड़ा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया। मप्र के 31,426 सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। 2015-16 में 56 प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं थी। वर्ष 2021-22 में इसमें थोड़ा सुधार हुआ लेकिन अभी भी 39 प्रतिशत स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है। वर्ष 2015-16 में 23 प्रतिशत स्कूलों में मेडिकल सुविधा नहीं थी जो आंकड़ा वर्ष 2021-22 में बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया। मप्र के 35,822 सरकारी स्कूलों में मेडिकल सुविधा नहीं है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

सबसे अधिक रीवा को फंड

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा रीवा, धार, सतना, छिंदवाड़ा जिले में स्कूल जर्जर हैं। इनमें से रीवा जिले को सबसे अधिक फंड मिलेगा। रीवा जिले के 244 स्कूलों के लिए 7,28,19,106 रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं धार जिले के 216 स्कूलों के लिए 4,28,88,023 रुपए सतना जिले के 198 स्कूलों के लिए 4,92,61,202 रुपए, छिंदवाड़ा जिले के 198 स्कूलों के लिए 3,76,15,275 रुपए, बैतूल जिले के 158 स्कूलों के लिए 3,77,05,922 रुपए, सिवनी जिले के 158 स्कूलों के लिए 3,51,25,225 रुपए, शिवपुरी जिले के 156 स्कूलों के लिए 5,25,13,425 रुपए, बडवानी जिले के 154 स्कूलों के लिए 2,64,39,573 रुपए, बालाघाट जिले के 154 स्कूलों के लिए 4,10,76,045 रुपए और छतरपुर जिले के 148 स्कूलों के लिए 3,68,95,601 रुपए मंजूर किए गए हैं।

दक्षिण भी अब मंदिर पथ पर

2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भाजपा की चुनावी पिच तैयार होने लगी है। माहौल और हालात को देखते हुए तस्वीर साफ होने लगी है कि भाजपा के चुनावों का एजेंडा हिंदुत्व का ही रहने वाला है। यह बात अलग है कि हिंदुत्व के एजेंडे के साथ विकास का तड़का लगाकर चुनावी दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। फिलहाल भाजपा का पूरा फोकस दक्षिण के राज्यों पर है। लेकिन दक्षिण के राज्यों को खाद-पानी उत्तरी भारत के शहरों से ही मिलने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। 2024 के लिए पार्टियों ने नैरेटिव सेट करने शुरू कर दिए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि उत्तर भारत की राजनीति में धर्म और धर्मस्थल हावी हैं। भाजपा अपनी **हिंदुत्ववादी पहचान** और राम मंदिर को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रोजेक्ट करती रही है, लेकिन अब तक धर्मनिरपेक्षता का नारा देने वाली दक्षिण भारत की पार्टियां भी भाजपा की काट के लिए राजनीति के मंदिर मार्ग पर सरपट दौड़ रही हैं।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने गत दिनों पहले ही कोंडागट्टू जिले में अंजनेय स्वामी मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा की है। तेलंगाना की सत्तारूढ़ बीआरएस के सांसद के. केशवराव कहते हैं- हम प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार करा रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर है। उधर, आंध्रप्रदेश सरकार 1,400 मंदिर बनवा रही है, हालांकि जगन मोहन रेड्डी की सरकार इसे राजनीतिक कदम नहीं मानती है। इस सवाल पर देवधर ने कहा- भ्रष्टाचार में गले तक फंसी पार्टियां इमोशनल एजेंडा बढ़ा रही हैं, लेकिन जनता उनकी हकीकत जानती है। भाजपा अपने विकास के एजेंडे पर बढ़ रही है। जगन मोहन सरकार 26 जिलों में 1,400 मंदिर बनवाने की घोषणा कर चुकी है। इनमें 1030 का निर्माण सरकार खुद करवा रही है और 330 का निर्माण समरसथ सेवा फाउंडेशन करवा रहा है। खास बात यह है कि यह फाउंडेशन आरएसएस से संबद्ध एक एनजीओ है। हर मंदिर के लिए 8-8 लाख और मूर्ति के लिए 2-2 लाख रुपए का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश सरकार के एडवाइजर देउलपल्ली अमर ने कहा कि जगन सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। चंद्रबाबू नायडू के समय विकास के नाम पर ध्वस्त किए 40 मंदिर बनवाए जा रहे हैं। नए मंदिर भी बन रहे हैं। धूप दीप नैवेद्यम योजना के तहत 5000 छोटे मंदिरों को 5000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इमामों को 10 हजार, श्रेणी-1 के मंदिरों के पुजारियों को 15,625 और श्रेणी-2 के पुजारियों को 10 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। पादरियों को भी 5 हजार मिलते हैं।

राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा सरकार को यहां एंटी इंकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने रामदेवरा बेट्टा में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। इस जगह को दक्षिण की अयोध्या के रूप में विकसित करने का दावा है। कोप्पल जिले में अंजनाद्रि पहाड़ी का भी विकास होगा। इसे हनुमानजी की जन्मभूमि माना जाता है। सरकार मंदिरों और मठों के विकास, जीर्णोद्धार पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। केसीआर ने कोंडागट्टू जिले के अंजनेय स्वामी मंदिर के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। 100 करोड़ रुपए पहले ही दिए थे। इससे पहले सरकार ने यदाद्रि भुवनगिरी जिले के प्राचीन यदागिरिगुट्टा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का पुनर्निर्माण 1800 करोड़ रुपए में कराया है। करीमनगर के राज राजेश्वर शिव मंदिर के पुनर्निर्माण की भी योजना बनी है। राज्यसभा सदस्य केशवराव कहते हैं कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर आंध्रप्रदेश के हिस्से में चला गया।

दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र के लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयासों के तहत सत्तारूढ़ भाजपा राज्य के रामनगर जिले में एक भव्य राम मंदिर बनाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बजट में घोषणा की थी कि रामनगर शहर के पास राम देवराबेट्टा (भगवान राम की पहाड़ी) का उत्थान किया जाएगा। रामनगर जिले के प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. सीएन अश्वथ नारायण ने पुष्टि की है कि रामनगर शहर को दक्षिण भारत की अयोध्या के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा, शहर रामनगर के नाम में राम है। जल्द ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी और अगले कदम उठाए जाएंगे। सत्तारूढ़ भाजपा की उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंदिर के शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करने की योजना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अयोध्या और रामनगर के रामदेवरा बेट्टा के बीच एक पारंपरिक संबंध है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर रामदेवरा बेट्टा बनाने की योजना है। अयोध्या से पवित्र मिट्टी एकत्र की जाएगी और निर्माण शुरू होने पर इसे रामदेवरा बेट्टा में मिट्टी में मिलाया जाएगा। मंत्री अश्वथ नारायण ने स्पष्ट किया है कि रामदेवरा बेट्टा के गिद्ध अभ्यारण्य क्षेत्र में आने से चिंता जताई गई है। हालांकि, इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि अभयारण्य प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से आपत्तियां उठाई जाती हैं। पक्षी प्रेमियों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दक्षिण कर्नाटक के मतदाताओं को लुभाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस क्षेत्र में विशेष रूप से सीटें जीतने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां भाजपा की जड़ें कमजोर हैं।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

2024 में हिंदुत्व ही होगा भाजपा का चुनावी एजेंडा!

2024 में होने वाले लोकसभा के चुनावों से ठीक पहले अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि वैसे तो भव्य राममंदिर को सूर्य के उत्तरायण में होने के साथ मकर संक्रांति जैसे शुभ मुहूर्त में ही दर्शन के लिए खोला जाएगा, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एसएन ठाकुर कहते हैं राम मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक अंग बनकर जुड़ा हुआ है। ठाकुर कहते हैं कि जिस राम मंदिर के लिए भाजपा को विपरीत परिस्थियों में भी जमकर लोगों का समर्थन मिलता था, वह तो अब बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में उसका चुनाव में फायदा नहीं होगा, राजनीतिक रूप से यह तो सोचने वाली बात ही नहीं है। ठाकुर का कहना है कि जब राम मंदिर को भक्तों के लिए खोला जाएगा, उसके बाद ही लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा के बगैर कुछ कहे ही माहौल उसके पक्ष में बनने के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं।

एनएसई में लिस्टेड हुआ इंदौर का ग्रीन बॉन्ड

कार्बन क्रेडिट से अर्जित हुई 9 करोड़ की आय

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर लीक से हटकर सोचता है और लीक से हटकर कार्य करता है। इंदौर शहर की सिटी बस सेवा में सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों का समावेश, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए 126 चार्जिंग स्टेशन तैयार करना, शहर के गीले कचरे के निपटान के लिए संयंत्र स्थापित कर उससे उत्पन्न होने वाली बॉयो सीएनजी का उपयोग सिटी बसों के संचालन के लिए करना, शहर में 100 अहिल्या वन और 4 नगर वन विकसित करना तथा शहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पौधरोपण जैसे उल्लेखनीय कार्य हैं। इन नवाचारों से कार्बन उत्सर्जन को कम कर लगभग 4 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किए जा चुके हैं। इनकी वैश्विक बाजार में ट्रेडिंग कर 9 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है। नगर निगम इंदौर ने कार्बन उत्सर्जन को रोकने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए जो बिजनेस मॉडल बनाया है, वह अन्य निकायों को नए नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह इस तथ्य का भी द्योतक है कि विश्वसनीयता और भरोसा हो तो पैसे की कमी नहीं रहती।

स्वच्छता के मामले में देश में पहले नंबर पर रहने वाले इंदौर ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। बिजली के खर्च को कम करने के लिए इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी कर नया इनोवेशन किया है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घंटा बजाकर इंदौर के ग्रीन बॉन्ड के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की औपचारिक घोषणा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को लाइफ अर्थात् लाइफ स्टाइल फॉर एन्वायरमेंट का मंत्र देकर पर्यावरण-संरक्षण को वैश्विक प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के लिए तय किए गए पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मप्र यथासंभव अपना योगदान देगा। भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के साथ शहरों को अपनी क्रेडिट रेटिंग कराना अनिवार्य किया था, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में पहला कदम था। इंदौर देश का ऐसा पहला नगर है जिसने राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में अपने बॉन्ड की लिस्टिंग 2018 में करवाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इस साल 5 और महानगरों में यह लक्ष्य हासिल करना है। प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन, प्रशासनिक दक्षता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता से हम रोडमैप निर्धारित कर अगले 8-10 माह में यह उपलब्धि प्राप्त करेंगे। बॉन्ड से राशि प्राप्त होगी तो शहरों के विकास में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सांची देश की पहली सोलर सिटी होगी। वर्ल्ड हेरीटेज सांची अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस 3 मई को सोलर सिटी बनेगा, जो पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री ने इंदौर के जन-प्रतिनिधि और अधिकारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे बड़े शहरों में इंदौर को सौर नगर के रूप में विकसित करने का संकल्प लें। इंदौर में इस प्रकार की चुनौतियों और नवाचारों को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य है। उन्होंने कहा कि जनता से संवाद, आवश्यक प्रावधान और व्यवस्थाएं करते हुए इंदौर इस दिशा में आगे बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र आर्थिक प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। हमारा प्रदेश अगला इंडस्ट्रियल हब होगा। आईटी, टेक्सटाईल, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रदेश में निरंतर गतिविधियां बढ़ रही हैं। वन्य-प्राणी संरक्षण में भी मप्र ने उल्लेखनीय कार्य किया है। मप्र में अपार संभावनाएं हैं, प्रदेश की बढ़ती रफ्तार को हम थमने नहीं देंगे।

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में यह सिद्ध कर दिखाया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश कार्बन उत्सर्जन कम करने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इंदौर नगर निगम की पहल इसी दिशा में एक कड़ी है। सांसद शंकर लालवानी ने इंदौर में अमृत-2 योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सहयोग उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट में नगरीय निकायों द्वारा बॉन्ड लाने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में हर क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के क्रम में इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा के लिए किया गया यह प्रयास सराहनीय है।

इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि ग्रीन एनर्जी के कॉन्सेप्ट करने के नजरिए से जहां से नर्मदा का पानी इंदौर लाया जाता है वहां मोटर पंपिंग स्टेशन पर बिजली के बिल को कम करने के लिए 60 मेगावाट का सोलर प्लांट खरगोन में लगाया गया। इस खर्च के लिए हम खुद के बॉन्ड जारी करेंगे। वहां ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे। 300 करोड़ बिजली के खर्च को कम करने के लिए ये बॉन्ड जारी किया। एसबीआई, एके कैपिटल और एनएसई की टीम ने काम किया। ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग में इंदौर में पहले दिन 661 करोड़ की राशि आई। कुल 730 करोड़ पर ये बॉन्ड लॉक हुआ। जिस विषय पर लोग जब सोचना शुरू करते हैं तब इंदौर उस काम को पूरा कर चुका होता है।

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि इंदौर देश से आगे चलता है। हमने छह बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जीता। कार्बन उत्सर्जन को लेकर भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाई। बजट में बहुत सा प्रावधान इस दिशा में हुआ है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य में हमारा देश विश्व का नेतृत्व कर रहा है। इंदौर में शहरीकरण और आबादी बढ़ रही है। सांसद ने कहा कि अमृत-2 योजना में हमें 800 करोड़ का गैप है बजट में इस गैप को दूर करने की मुख्यमंत्री से मांग की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंदौर एक दौर है। मैं भी ये मानता हूं इंदौर लीक से हटकर सोचता और करता है। इसके कई उदाहरण हैं।

● **विकास दुबे**

चीतों से पर्यटन को लगेंगे पंख

श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क में चीते आने के साथ ही पार्क के आसपास के इलाकों की जमीनों के भाव आसमान छूने लगे हैं। दरअसल कूनो में चीतों के आने से यहां पर्यटन बढ़ने की उम्मीद जाग गई है, जिसके चलते यहां रिसोर्ट बनाने के लिए उद्योगपति यहां जमीन की तलाश कर रहे हैं या फिर खरीद चुके हैं। ग्रामीणों की मानें तो यहां कुछ माह पहले तक 3 लाख रुपए बीघा की दर से जमीन बिक रही थी जो आज बढ़कर 15-20 लाख रुपए बीघा तक पहुंच गए हैं। ना सिर्फ श्योपुर बल्कि राजस्थान, उप्र, दिल्ली, बिहार समेत कई अन्य प्रांतों के लोग कूनो के आसपास जमीन खरीदने पहुंच रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क और रणथंभौर के बीच 150 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में रणथंभौर में बाघ देखने आने वाले पर्यटक भविष्य में चीते देखने कूनो भी आ सकते हैं। ऐसे में यहां जमीन खरीदने में राजस्थान के लोग भी खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

बीते एक-दो माह के दौरान यहां कई रिसोर्ट भी बनने लगे हैं। कूनो नेशनल पार्क के मुख्य गेट टिकटोली से पहले सेसईपुरा से लेकर तमाम गांवों में जमीन की कीमतों में उछाल आ गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय बढ़ने से विकास और प्रगति को पंख लगेंगे। श्योपुर जिले के 748 वर्ग किमी में विस्तार लिए कूनो-पालपुर आने वाले समय में अब दक्षिण अफ्रीका से आए 20 चीतों का घर बन गया है। भारतीय घर में चीतों के दौड़ने से मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर और राजस्थान राज्य की सीमा से जुड़े श्योपुर की आर्थिक, औद्योगिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ेंगीं। चीता पुर्नस्थापन योजना से कराहल-श्योपुर के अलावा शिवपुरी के पोहरी सहित कूनो और चंबल नदी के आसपास की लगभग 1.8 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर ईको टूरिज्म, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित ईको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

बीते वर्ष सितंबर में 8 और अब 12 चीते आने के बाद हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के निवेशकों ने कूनो नेशनल पार्क के आसपास निवेश करने में रूचि लेना शुरू किया है। आने वाले एक या दो वर्ष में कूनो-पालपुर क्षेत्र टूरिस्ट आधारित इकाइयों के लिए निवेश का बेहतर स्थान बनने की संभावना है। प्रदेश के पिछड़े जिलों में शामिल श्योपुर में अब पर्यटन कारोबार बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। कूनो में पहुंचने वाले सैलानियों की संभावना को देखते हुए होटल मैनेजमेंट ने अत्याधुनिक सुविधाओं वाले टेंट का निर्माण शुरू कर दिया है। नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में सितारा होटल जैसी बेहतर सुविधाओं वाले स्विस टेंट में सैलानी रुक सकेंगे। कूनो नदी से सेसईपुरा के पास बनाए जा रहे इस टेंट में पर्यटकों के ठहरने के साथ भोजन-नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। बाहर से आम झोपड़ियों की तरह नजर आने वाले इस टेंट में अंदर पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं हैं।

कूनो में चीतों का दीदार करने के लिए आने वाले पर्यटकों को आवास के साथ एडवेंचर मुहैया कराने एवं स्थानीय आदिवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य शासन-प्रशासन द्वारा उन्हें होमस्टे योजना से जोड़ने की प्लानिंग की थी। इसके तहत कूनो नेशनल पार्क के पास वनांचल के गांवों में आदिवासियों की झोपड़ियों को होटल के रूप में विकसित करना था, अभी यह योजना परवान नहीं चढ़ सकी है। परंतु मप्र राज्य सहकारी पर्यटन संघ की होटल मैनेजमेंट इकाई ने इसी तर्ज पर पर्यटकों के लिए आशियाने तैयार करना शुरू कर दिया है। सेसईपुरा में नदी के पास विदेशी पर्यटकों, देसी पर्यटकों व स्टूडेंट के हिसाब से तैयारी की जा रही है। 15 स्विस टेंट विदेशी पर्यटकों के लिहाज से तैयार हैं जिनमें पर्सनल लेट बाथ की सुविधा है, इनका किराया 2000 रुपए प्रति व्यक्ति होगा वहीं स्थानीय पर्यटकों व शेयरिंग के हिसाब से 7 टेंट तैयार किए गए हैं, जिनका किराया 1500 रुपए प्रति व्यक्ति होगा। स्थानीय लोगों के लिए 500 रुपए की छूट भी रहेगी।

टेंट में लेट-बाथ अटैच, डायनिंग टेबल, सोफा सेट, गर्मियों में एसी की सुविधा रहेगी। सुबह का ब्रेक फास्ट, स्नेक्स, सलाद, पानी की बोटल, आमलेट, चाय, डिनर शामिल रहेगा। इन टेंट में राजस्थानी संस्कृति का स्वरूप दिया गया है। मप्र राज्य सहकारी पर्यटन संघ भोपाल के प्रदेशाध्यक्ष अरविंद सिंह तोमर ने बताया कि जब चीते खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे तो पर्यटक बढ़ेंगे। कूनो में आने वाले पर्यटकों के ठहरने के लिए टेंट बनाए गए हैं। इन झोपड़ियों में सितारा होटल जैसी सुविधाएं रहेंगी।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

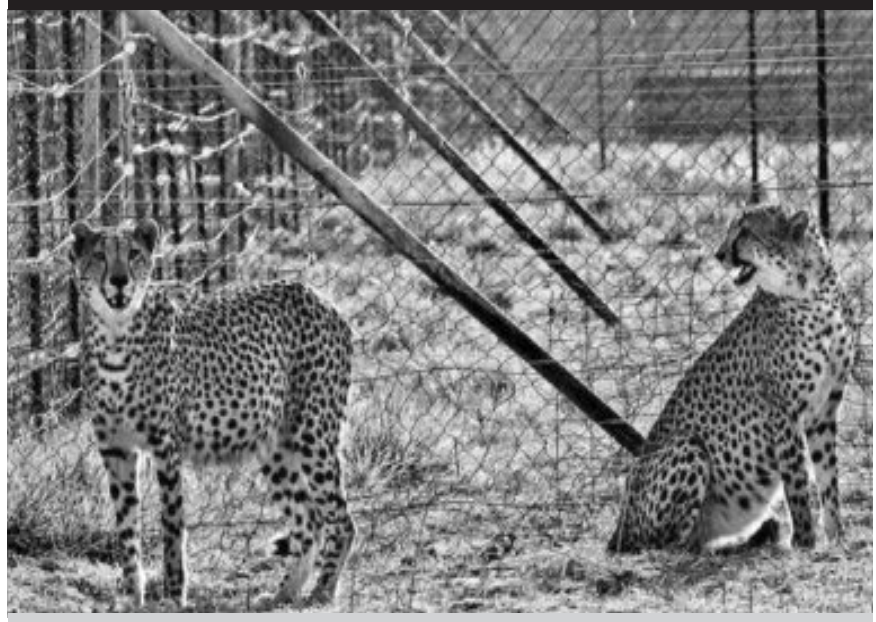

इन कारणों से मिलेगी विकास को रफ्तार

309 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ की शुरुआत हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर श्योपुर का संपर्क भिंड में गोल्डन क्वालिटीलेट्रल (आगरा-कानपुर) हाईवे से होगा। मुरैना में नार्थ-सेंट्रल कॉरिडोर से होगा और राजस्थान में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से हो जाएगा। सड़क मार्ग से संपर्क बढ़ने के साथ ही आने वाले समय में रेलवे की ब्रॉडगेज लाइन का काम भी होना है। इससे आवागमन बेहतर होगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। चीता पुर्नस्थापन योजना के जरिए दिल्ली से खजुराहो या राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क जाने वाले पर्यटक कूनो पालपुर क्षेत्र में ईको टूरिज्म का भी अनुभव कर सकेंगे। आंचलिक टूरिस्ट सर्किट तैयार होने पर चंबल सेंचुरी, सोन चिरैया अभयारण्य और करैरा अभयारण्य भी आपस में लिंक हो सकेंगे। इससे पर्यटन को रफ्तार मिलेगी।

केन-बेतवा पर मेहरबानी

आम बजट 2023-24 में मप्र को केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कागजों में दौड़ रही इस परियोजना को विधानसभा चुनाव से पहले शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए पन्ना-छतरपुर की 5,480 हेक्टेयर गैर-वन सरकारी जमीन हस्तांरित किए जाने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। राज्य सरकार नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति पहले ही दे चुकी है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना पर कुल 46 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 1100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष में दे चुकी है। परियोजना से सबसे ज्यादा फायदा बुंदेलखंड क्षेत्र को होगा। जिसमें मप्र और उप्र के 13 जिले आते हैं। इनमें मप्र के 9 जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन आते हैं। वहीं, उप्र के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले हैं। केंद्र सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया था। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्लान का पहला प्रोजेक्ट है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा। दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी केन-बेतवा लिंक नहर बनाई जाएगी। पिछले महीने भोपाल आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया था कि इंटर रिवर लिंक परियोजना केन-बेतवा जल्द शुरू की जाएगी। अगले 2 से 3 महीने में परियोजना की शुरुआत होगी। शेखावत के मुताबिक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जरूरी अनुमतियां ली जा चुकी हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र उप्र और मप्र में फैला हुआ है। केन-बेतवा इंटरलिंक प्रोजेक्ट की मदद से बुंदेलखंड में सिंचाई व पीने के पानी की कमी दूर हो सकेगी। मार्च 2021 में केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और मप्र व उप्र सरकार के बीच केन-बेतवा लिंक परियोजना का एग्रीमेंट साइन हुआ था।

पिछले महीने 18 जनवरी को केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक दिल्ली में जलशक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। इस दौरान मप्र के नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और उप्र के रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य को राज्य सरकारों ने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाने की अनुमति दी थी। जानकारी के मुताबिक पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना को पारदर्शी और समय पर पूरा करने की देखरेख करने के लिए पुनर्वास व पुनर्स्थापन समिति के गठन के प्रस्ताव को बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया। परियोजना के भू-भाग प्रबंधन योजना (एलएमपी) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के क्रियान्वयन के लिए एक वृहद पन्ना भू-भाग परिषद का भी गठन किया जा रहा है।

8 साल में दो चरणों में पूरा होगी परियोजना

इस परियोजना में यमुना नदी की सहायक नदियों सहित मप्र के पन्ना जिले में केन नदी और उप्र में बेतवा नदी को जोड़कर जल संकट से निपटने के लिए अतिरिक्त पानी वाले नदी के बेसिन से कम पानी वाले बेसिन तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह कार्य 8 वर्षों में दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में छतरपुर जिले के ढ़ोढ़न बांध बनाकर उससे जुड़ी निम्न स्तरीय सुरंग, उच्च स्तरीय सुरंग, 221 किमी लंबी केन-बेतवा लिंक नहर और बिजलीघर बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में लोअर बांध, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना और कोटा बैराज के लिए विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। यहां बता दें कि यह बड़ी परियोजना लगभग 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी की जाएगी। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, परियोजना को लागू करने के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा और केंद्र सरकार परियोजना की कुल लागत का 90 प्रतिशत खर्च उठाएगी, शेष खर्च राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार 470 किमी लंबी केन नदी बुंदेलखंड की प्रमुख नदी है। इससे बेतवा नदी जुड़ जाने से किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका के लिए पानी मिलने लगेगा।

परियोजना में पानी के बंटवारे को लेकर वर्ष 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की मौजूदगी में दोनों प्रदेशों के बीच अनुबंध हुआ था। तब मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर और उप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। तब परियोजना का डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार नहीं हुआ था। केन-बेतवा लिंक परियोजना दो राज्यों मप्र और उप्र का संयुक्त प्रोजेक्ट है। संयुक्त परियोजना होने के कारण दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे का भी प्लान तैयार किया गया है। इसमें हर साल नवंबर से अप्रैल महीने के बीच (नॉन मानसून सीजन) में उप्र को 750 एमसीएम तो वहीं मप्र को 1834 एमसीएम पानी मिलेगा। इन सभी बिंदुओं पर दोनों राज्य सरकारों का केंद्र सरकार के साथ समझौता किया गया है। इसी समझौते को एमओए (मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट) कहा जा रहा है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि नदी जोड़ो परियोजना के तहत 30 लिंक चिन्हित किए गए हैं। केंद्र ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शेखावत ने बताया कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने प्रायद्वीपीय नदियों के 16 लिंक और हिमालयी नदियों के 14 लिंक को चिन्हित किया है। उन्होंने बताया कि सभी लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई है। 24 लिकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके साथ ही 8 लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी पूरी कर ली गई है। शेखावत ने बताया कि भारत सरकार ने 39,317 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में जल उपलब्धता एक समान नहीं होने के कारण कुछ भागों में बार-बार बाढ़ आती है तथा अन्य कुछ भागों में सूखा पड़ता है। जल की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए नदियों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

विधानसभा या औपचारिकता

4 साल में म.प्र. विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चला

15वीं विधानसभा के इस आखिरी बजट सत्र से सबको बड़ी उम्मीदें

मप्र विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से शुरू हो गया है। 29 दिनों तक चलने वाले इस बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार चुनावी बजट भी पेश करेगी। चुनावी साल में होने वाले इस सत्र पर सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सत्तारूढ़ भाजपा जनता की नजर में अपने आपको विकासशील सरकार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार को असफल बताने की कोशिश करेगी। ऐसे में यह सत्र भी हंगामेदार होने के आसार हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र विधानसभा के बजट सत्र में चुनावी रंग दिखेगा। इसकी झलक 27 और 28 फरवरी को दिख गई है। यानी भाजपा इस सत्र के दौरान अपनी सरकार की जमकर ब्रांडिंग करने की कोशिश करेगी, वहीं कांग्रेस लगातार हमलावर रहेगी। इससे इस बात की झलक भी दिखने लगी है कि शायद ही यह सत्र भी पूरे समय चले। गौरतलब है कि मप्र में पिछले 4 साल के दौरान जितने भी विधानसभा सत्र आयोजित किए गए हैं, वे पूरी अवधि तक नहीं चले। ऐसे में 15वीं विधानसभा का आखिरी बजट सत्र बजट पेश होने के बाद कभी भी खत्म हो सकता है। इसकी आशंका इसलिए भी बढ़ गई है कि सत्र के दूसरे दिन ही विधायकों की सामूहिक फोटोग्राफी हो चुकी है। गौरतलब है कि हर विधानसभा में विधायकों की सामूहिक फोटो की परंपरा है। ऐसे में सबका ध्यान इस ओर है कि इस बार भी विधानसभा का सत्र महज औपचारिकता बनकर तो नहीं रह जाएगा।

राज्यपाल ने गिनाईं उपलब्धियां

15वीं विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण के साथ प्रारंभ हुआ। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने सदन में पहुंचकर अपने अभिभाषण में शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने मप्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि 16 साल पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 44 लाख लाडली लक्ष्मी लखपति बन चुकी हैं। अब जल्द ही सरकार लाडली बहना योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को हर साल 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग वह अपने परिवार के कल्याण में कर सकेंगी। बता दें कि सरकार लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देगी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि बीते साल मप्र सरकार ने 23 हजार एकड़ जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई। यह जमीन गरीब और पिछड़ों को दी जा रही है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक का निर्माण किया गया। दूसरे चरण का निर्माण भी तेज गति से किया जा रहा है। शिव अर्पण कार्यक्रम के जरिए हमारी सरकार ने मिट्टी के दीये लगाने को लेकर रिकॉर्ड बनाया है। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थापित की जा रही है। भोपाल के इस्लामपुर का नाम जगदीशपुर करने से गौरव फिर लौट आया है। इंदौर लगातार छह साल से स्वच्छता में परचम लहरा रहा है। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं और 12 नए अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं।

लाडली बहना योजना से होगा बड़ा बदलाव

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अपने भाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और योजनाओं की तारीफ की। राज्यपाल ने अभिभाषण में लाडली लक्ष्मी योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 16 साल पहले लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 44 लाख लखपति लाडली लक्ष्मी बन चुकी हैं। जल्द ही सरकार लाडली बहना योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए और हर साल 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस राशि का उपयोग वह अपने परिवार के कल्याण में कर सकेंगी। उन्होंने अभिभाषण में प्रवासी भारतीय दिवस और इन्वेस्टर समिट का जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की धरती पर आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के द्वारा 70 से अधिक देशों से आए 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में नमो ग्लोबल गार्डन में प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाए गए पौधों के रूप में आयोजन के लिए स्मृति बनेगी। रीवा एयरपोर्ट निर्माण और ग्वालियर में विमानतल का विस्तार और विकास आम आदमी के सभी सपने साकार करेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि सरकार गांव में किसानों को पानी और सिंचाई के लिए चीजें उपलब्ध करवा रही है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में भी काफी अच्छे कार्य हुए हैं। उज्जैन मेडिकल डिवाइस पार्क में मेडिकल डिवाइसेज में स्थापित किए गए हैं। इंदौर और पीथमपुर में इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित किया गया है। विभिन्न किसान हितैषी योजनाओं को लाया गया है। करोड़ों की राशि किसानों के खाते में डाली गई है। दो साल में 100 करोड़ से अधिक की राशि कम ब्याज पर उपलब्ध करवाई गई है।

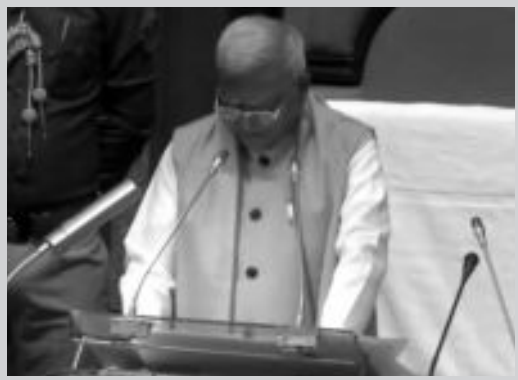

4 साल में कोई सत्र पूरा नहीं

मप्र विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। यह सत्र 29 दिन का है, जिसमें 13 बैठकें होने वाली हैं। लेकिन यह सत्र कितने दिन चलेगा, इस पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि पिछले 4 साल के दौरान विधानसभा का कोई भी सत्र पूरी अवधि तक नहीं चला है। इसको लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं पर जनहित से जुड़े मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। गौरतलब है कि 2022 में लोकसभा वर्ष में 100 दिन, बड़ी विधानसभा 90 से 75 दिन और छोटी विधानसभा में सदन की कार्यवाही 60 दिन चलाने की बात कही गई थी। संसद हो या विधानसभा, जनता के मुद्दों पर चर्चा, सवाल-जवाब और फिर निर्णय पर पहुंचना ही आदर्श संसदीय व्यवस्था है, लेकिन अब स्थितियां बदलती जा रही हैं। विधानसभा सत्रों में चर्चा के नाम पर हंगामा, विरोध और फिर कार्यवाही का स्थगन। बीते कई वर्षों में यही चिंताजनक ट्रेंड मप्र विधानसभा में दिखाई दिया।

मप्र में 15वीं विधानसभा के चार साल से अधिक समय पूरे हो चुके हैं। लेकिन विडंबना यह देखिए कि इन दिनों में विधानसभा का सत्र 63 दिन भी नहीं चला। 15वीं विधानसभा में बजट सत्र के पहले तक 107 दिन बैठकें तय की गई थीं, लेकिन 63 दिन ही हुईं। यह आंकड़ा बता रहा है कि चर्चा का समय लगातार घट रहा है। लोकतंत्र के लिए इसे कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। 15वीं विधानसभा में तीन सत्रों को छोड़कर 4 साल में अन्य कोई भी सत्र (बजट, मानसून और शीतकालीन) अपनी निर्धारित अवधि पूरी नहीं कर सका। यहां तक कि बजट सत्र की बैठकें भी समय से पहले ही समाप्त हो गईं। जबकि यह सबसे लंबा होने की परंपरा रही है।

सत्र चलाने में किसी की रुचि नहीं

दरअसल, सत्तापक्ष हो या विपक्ष किसी की भी रूचि अब अधिक अवधि तक सत्र चलाने में नहीं रह गई है। सरकार का जोर इस बात पर रहता है कि विधायी कार्य पूरे हो जाएं। वहीं, विपक्ष शुरुआत से ही हंगामा करना प्रारंभ कर देता है। स्थिति अब तो यह बनने लगी है कि प्रश्नकाल तक पूरा नहीं हो पाता और अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही बार-बार स्थगित करनी पड़ती है। पिछले मानसून सत्र में यही स्थिति बनी। इससे अध्यक्ष व्यथित भी नजर आए पर सदन के सुचारू संचालन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जाहिर है दोनों पक्ष इसके लिए एक-दूसरे को ही जिम्मेदार बताते हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का आरोप है कि सरकार सदन में चर्चा कराने से भागती है। विपक्ष लोक महत्व के विषयों पर चर्चा करना चाहता है पर सत्तापक्ष हंगामा करने

3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट

उम्मीद की जा रही है कि चुनावी साल होने की वजह से इस साल का बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। बता दें कि बीते 2 बजट 2 लाख 79 हजार करोड़ के थे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के अनुसार बजट सत्र के लिए अब तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 154 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव की तीन, शून्यकाल की 24, अशासकीय संकल्प 31, ऑनलाइन प्रश्न 1 हजार 870 और ऑफलाइन प्रश्न 1 हजार 834 प्राप्त हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा के 79 सदस्यों ने डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करते हुए 1 हजार 870 ऑनलाइन प्रश्न किए हैं। इसके अलावा ऑफलाइन सवाल 1 हजार 834 हैं। इनमें से 1 हजार 849 तारांकित और 1 हजार 855 अतारांकित शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2016 में ऑनलाइन प्रश्न की सुविधा प्रारंभ होने के उपरांत पहली बार ऑनलाइन प्रश्न की संख्या ऑफलाइन प्रश्न से ज्यादा हैं और यह प्रसन्नता की बात है। इस बीच मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी की है। विधानसभा सत्र के मद्देनजर भोपाल में विधानसभा भवन के आसपास के इलाकों में जिला प्रशासन ने ऐहतियातन निषेधाज्ञा लागू की है। इन इलाकों में धरना-प्रदर्शन नहीं हो सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है।

लगता है। संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि कांग्रेस कभी जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती। हंगामा करना ही इनका मकसद रहता है। जबकि, सदन का मंच हमें जनहित पर चर्चा करने के लिए दिया है और सबकी प्रक्रिया निर्धारित है। बड़ी तैयारी के साथ विधायक विधानसभा सत्र के लिए प्रश्न लगाते हैं। एक घंटे के प्रश्नकाल में 25 प्रश्नों का चयन लॉटरी के माध्यम से होता है। जिन सदस्यों के प्रश्न इसमें शामिल होते हैं वे सदन में सरकार का उत्तर चाहते हैं और पूरक प्रश्न भी करते हैं पर हंगामे के कारण प्रश्नकाल ही पूरा नहीं हो पा रहा है। इससे विधायकों के प्रश्न पूछने के अधिकार का हनन भी हो रहा है। अपनी बात रखने का उन्हें मौका भी कम मिल रहा है। इसे लेकर विधायक आपत्ति भी दर्ज करा चुके हैं। विधेयकों को लेकर भी स्थिति अलग नहीं है। इस दौरान अधिकतर विधेयक हंगामे के बीच ध्वनिमत से चंद मिनटों में पारित हो जाते हैं।

आधा भी बजट खर्च नहीं

1 मार्च को शिवराज सरकार अपना बजट पेश करेगी। लेकिन विसंगति यह है कि प्रदेश सरकार के अधिकारी-मंत्री अपने विभागों का पूरा बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। प्रदेश का पंचायत, खाद्य और वाणिज्यिक कर विभाग तो ऐसे हैं जो आधा बजट भी खर्च नहीं कर पाए है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभाग भी अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस विकास पर रहता है, लेकिन उनके निर्देशों के बावजूद विभाग अपना पूरा बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। वहीं मप्र सरकार का 2023-24 का बजट 1 मार्च को आ रहा है। सभी विभाग ने कम से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की डिमांड की है, जबकि वास्तविकता यह है कि पिछले साल मिले पैसे को ही विभाग पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। स्वास्थ्य, कृषि, बिजली के साथ शिक्षा जैसे प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों में भी पूरे बजट का

सदन में संपत्ति ब्यौरा देने में अधिकांश की रुचि नहीं

राजनीतिक सुचिता की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां दावे तो तमाम करती हैं, लेकिन अपने दावों को भूल जाती हैं। मप्र में भी ऐसा ही हो रहा है। यहां सरकार और विपक्ष ने मिलकर नियम बनाया है कि हर साल सभी मंत्री और विधायकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। लेकिन माननीय अपना बनाया नियम भूल गए हैं और सदन में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह इकलौते ऐसे विधायक है जिन्होंने वर्ष 2022-2023 तक का अपना संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। मौजूदा मंत्रियों ने वर्ष 2023 का अपना संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया है। गौरतलब है कि सरकार के मंत्रियों को हर साल विधानसभा के पटल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा रखना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2010 में मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान संपत्ति का ब्यौरा सदन में पेश करने की शुरूआत की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित उनके मंत्रिमंडल के सभी 32 सदस्यों ने अपनी संपत्ति की जानकारी विधानसभा के पटल पर रखी। हालांकि यह सिलसिला 2013 तक चलता रहा। साल 2013 के बाद से पिछले 10 सालों में मप्र के 3 ही मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है जबकि इस दौरान विधानसभा में लगातार संकल्प पारित होते रहे कि मंत्री सहित सभी विधायक अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। विधानसभा की जानकारी के मुताबिक साल 2019 तक वर्ष 2013 से 2018 के कार्यकाल में मंत्री रहे जयंत मलैया और गौरीशंकर बिसेन को छोड़कर 7 साल में दूसरे किसी भी मंत्री ने विधानसभा को संपत्ति की जानकारी नहीं दी। साल 2011 में मुख्यमंत्री सहित सिर्फ 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति बताई। 2012 में मुख्यमंत्री और 16 मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड पेश किया। साल 2013 में मुख्यमंत्री और 17 मंत्रियों ने संपत्ति की जानकारी दी। साल 2015 में शिवराज सरकार के इकलौते मंत्री जयंत मलैया ने सदन में अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड पेश किया। साल 2017 में संपत्ति का ब्यौरा पेश करने वाले शिवराज सरकार के इकलौते मंत्री गौरीशंकर बिसेन थे। 2017 के बाद शिवराज सरकार दूसरी बार सत्ता में आ चुकी है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल के द्वारा सदन में संपत्ति का ब्यौरा पेश नहीं किया गया। मुख्यमंत्री, डॉ. गोविंद सिंह और डॉ. प्रभुराम चौधरी के अलावा पूर्व मंत्री रामपाल सिंह (2020-2021), शैलेंद्र जैन (2019-2020), अजय टंडन (2019-20), नागेंद्र सिंह (2019-20), आरिफ मसूद (2019-20) और (2021-22), संजय यादव (2019-20) और (2021-22), टामलाल रघुजी सहारे (2020-21), लीना संजय जैन (2019-20), ग्यारसी लाल रावत (2019-20), चैतन्य कश्यप (2019-20) आदि ने संपत्ति का ब्यौरा दिया।

इस्तेमाल नहीं हुआ। वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं कि सभी विभागों को दो सप्लीमेंट्री के साथ 3,05,333.21 करोड़ रुपए बजट दिया गया, जिसमें 2,87,051.22 करोड़ रुपए जारी भी किए, लेकिन विभाग 1,69,524.24 करोड़ ही खर्च कर पाया। यानी 1.17 लाख करोड़ रुपए अभी भी सरकार के खजाने में रखे हैं। सरकार ने जोर-शोर से हैप्पीनेस विभाग भी खोला था, जिसे इस साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिले। यह महकमा भी 2 करोड़ 64 लाख रुपए ही खर्च कर पाया। 1 मार्च को मप्र का वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आ रहा है। मंत्रालय सूत्र बता रहे हैं कि यह बजट 3 लाख 20 हजार करोड़ से अधिक हो सकता है।

यह हाल भी तब है जब मुख्यमंत्री लगातार विभागों की समीक्षा कर अफसरों को निर्देशित करते रहते हैं। वे विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए बजट खर्च करने को कहते हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद भी ज्यादातर बड़े विभागों ने 60-70 फीसदी से अधिक पैसा खर्च कर दिया, लेकिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राजस्व और वाणिज्यिक कर पीछे चल रहे हैं। खाद्य विभाग और वाणिज्यिक कर तो आधा पैसा भी अभी खर्च नहीं कर पाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि काम चल रहे हैं। कुछ बाकी भी हैं जो जल्द पूरे होंगे। अभी 31 मार्च तक का समय है। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि 850 सड़कों की मजबूती का बड़ा काम चल रहा है। राशि थोड़ी देर से मिली। हम अपना पूरा बजट खर्च कर लेंगे।

15% बढ़ी प्रति व्यक्ति आय

मप्र विधानसभा में शिवराज सरकार ने वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में 1,40,583 रुपए हो गई, जो 15.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वहीं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 16.48 प्रतिशत की रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। हमारे ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि सरकार काफी ऋण ले रही है लेकिन यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 29 प्रतिशत है जो 2005 में 39 प्रतिशत था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 1,87,000 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना हुई तथा 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध हुए। वर्ष 2022-23 में नवंबर माह तक 2,13,000 लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें 11.30 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

गौरतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षण में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, प्रदेश के ऊपर ऋण, कृषि व औद्योगिक विकास, रोजगार के साथ सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति की जानकारी दी जाती है। प्रचलित भावों के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 24 हजार 685 थी। इसमें वृद्धि संभावित है।

बजट खर्च करने में नहीं दिखाई मुस्तैदी

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी राज्य में कई विभागों के आला अफसर तथा मंत्रियों ने सरकार की मंशा के मुताबिक बजट से कार्य कराने में मुस्तैदी नहीं दिखाई। और अब तो कई विभाग अपना पूरा बजट खर्च कर पाने की स्थिति में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग को 15,523 करोड़ रूपए आवंटित हुए थे उसमें से वह 74.43 प्रतिशत बजट ही खर्च कर पाया। इसी तरह कृषि विभाग ने 14,874 करोड़ में से 80.71 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग ने 10,413 करोड़ में से 77.79 प्रतिशत, नगरीय विकास विभाग ने 13,368 करोड़ में से 85.19 प्रतिशत, लोक निर्माण विभाग ने 10,494 करोड़ में से 73.21 प्रतिशत, स्कूल विभाग ने 27,565 करोड़ में से 79.68 प्रतिशत, पंचायत विभाग ने 6,469 करोड़ में से 47.68 प्रतिशत, जनजातीय विभाग ने 10,777 करोड़ में से 71.68 प्रतिशत, सामाजिक न्याय विभाग ने 3,920 करोड़ में से 91.65 प्रतिशत, खाद्य आपूर्ति विभाग ने 1,155 करोड़ में से 45.80 प्रतिशत, जल संसाधन विभाग ने 6,838 करोड़ में से 81.54 प्रतिशत, पीएचई विभाग ने 8,647 करोड़ में से 66.95 प्रतिशत, महिला बाल विकास विभाग ने 5,607 करोड़ में से 69.18 प्रतिशत, मेडिकल एजुकेशन विभाग ने 2,802 करोड़ में से 85.83 प्रतिशत, अल्पसंख्यक व ओबीसी विभाग ने 1,625 करोड़ में से 64.43 प्रतिशत, अनुसूचित विभाग ने 1,760 करोड़ में से 55.73 प्रतिशत, ग्रामीण विकास विभाग ने 21,390 करोड़ में से 76.76 प्रतिशत, गृह विभाग ने 9,953 करोड़ में से 78.99 प्रतिशत, वाणिज्यिक कर विभाग ने 2,030 करोड़ में से 21.57 प्रतिशत, धर्म-धर्मस्व विभाग ने 109 करोड़ में से 71.55 प्रतिशत, राजस्व विभाग ने 8,963 करोड़ में से 55.90, वन विभाग ने 3,354 करोड़ में से 85.04 प्रतिशत ही खर्च किया है।

विधायकों की परफॉर्मेंस चिंताजनक

मप्र में 4 साल के दौरान जिस तरह विधानसभा के सत्र पूरी अवधि तक नहीं चले वहीं विधायकों की परफॉर्मेंस भी संतोषजनक नहीं रही। मप्र में जनता के सवालों को विधानसभा में पूछने के मामले में मंदसौर से तीन बार के भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया सबसे आगे हैं। उन्होंने 15वीं विधानसभा के अब तक के कार्यकाल में 400 से अधिक सवाल पूछे हैं। उन्हीं की वजह से देशभर में पोस्टमॉर्टम से जुड़ा नियम बदल गया। सबसे पीछे हाटपीपल्या से भाजपा विधायक मनोज चौधरी हैं। विधानसभा की कार्यवाही का रिकॉर्ड बताता है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व पांच बार के विधायक डॉ. सीताशरण शर्मा ने गंभीर मुद्दों की बहस में सबसे ज्यादा बार हिस्सा लिया है, चाहे विधेयक हो या फिर बजट। शर्मा ने अपने अनुभव व तर्कों के साथ अपनी बात सदन में वजन के साथ रखी है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष और 7 बार के कांग्रेस विधायक डॉ. गोविंद सिंह विधानसभा में प्रमाण के साथ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने में सबसे आगे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनुभवी विधायकों की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही। पहली बार के जबलपुर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना भी टॉप विधायकों की सूची में शामिल हैं। सक्सेना सबसे ज्यादा सवाल पूछने वालों की सूची में टॉप 5 में हैं।

मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया कहते हैं कि लंबित कामों को तत्काल कराने के लिए विधानसभा में सवाल लगाने से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, इसलिए विधानसभा में

एक-एक प्रश्न का महत्व है। मैंने एक सवाल किया था कि प्रदेश के 5 बड़े शहरों में कुत्तों की नसबंदी पर कितना पैसा खर्च किया गया है। क्या नसबंदी के बाद आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं खत्म हो गई हैं। सरकार के जवाब से पता चला कि एक एनजीओ को इस काम के लिए 13 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 14वीं विधानसभा के दौरान विधायक सिसोदिया ने ध्यानाकर्षण लगाया था कि सूर्यास्त के बाद पोस्टमॉर्टम क्यों नहीं हो सकता? इस पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सिसोदिया के बीच करीब आधे घंटे तक सदन में बहस हुई थी। इसके बाद मिश्रा ने सरकार की ओर से भोपाल को छोड़कर पूरे प्रदेश में रात 10 बजे तक पोस्टमॉर्टम किए जाने का निर्णय लिया। इस पर सिसोदिया कहते हैं कि मेरे उठाए गए मुद्दे की प्रासंगिकता थी कि बाद में केंद्र सरकार ने इस नियम को पूरे देश में लागू किया।

विधायक विनय सक्सेना कहते हैं कि यदि सदन में तर्कों व प्रमाणों के साथ कोई मुद्दा उठाया जाता है तो कोई वजह ही नहीं होती कि सरकार उसे न माने। जनता के मुद्दे उठाने के लिए पूरी तैयारी के साथ बात रखने का फायदा मिलता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर जबलपुर में (मदन महल से दमोह नाका तक 9 किमी) बन रहा है, लेकिन इसके निर्माण में कई तरह की खामियां थीं। हमने पूरे प्रमाण के साथ इस मुद्दे को उठाया, जिससे सरकार सहमत हुई और इस प्रोजेक्ट के लिए 79 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत हुए। विधानसभा के अब तक के सत्रों में जबलपुर पाटन से भाजपा विधायक अजय विश्नोई ने मात्र 12 सवाल पूछे हैं। इस पर उनका कहना है कि यह सवाल मैंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में लगाए। इसके बाद से प्रदेश में भाजपा की सरकार है।

ऐसे में शासन स्तर पर अफसरों से बात कर समस्या का समाधन हो जाता है तो फिर विधानसभा में सवाल-जवाब करने की जरूरत नहीं है।

विधानसभा में विधायकों की परफॉर्मेंस कम रहने को लेकर विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवान देव इसरानी कहते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण सत्र की बैठकों में कमी आना है। जो विधायक सवाल पूछते भी हैं तो ज्यादातर जवाब सरकार की तरफ से आते नहीं है। मंत्री जवाब में कह देते हैं- जानकारी एकत्रित की जा रही है। यह बड़ा रोग लग गया है। यही वजह है कि विधायकों का सवाल पूछने के प्रति रुझान धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। वे यह भी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि विधायक सदन में मुद्दे नहीं उठाते। भाजपा विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया, कांग्रेस के डॉ. गोविंद सिंह, जीतू पटवारी और कुणाल चौधरी की सदन में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। चूंकि इनमें से कई अनुभवी विधायक हैं, इसलिए ये अपनी बात सदन में रख लेते हैं। लेकिन बैठकें कम होने से नए विधायकों को मौका नहीं मिल पाता है।

अपनों के घेरे में कमलनाथ

चुनावी साल में सरकार जहां एक तरफ अपनी उपलब्धियों के सहारे सत्ता में वापसी का तानाबाना बुन रही है, वहीं कांग्रेस अभी भी गुटबाजी से त्रस्त है। स्थिति यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सत्ता में वापसी के लिए निरंतर हाथ-पांव मार रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह के गुट के नेता कमलनाथ को ही घेरने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल कई बार कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर चुके हैं। यही कारण है कि सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस भाजपा को घेरने में सफल नहीं हो पाई है। इसका फायदा उठाकर सत्तारूढ़ पार्टी निरंकुश होकर काम कर रही है। इसका नजारा 15वीं विधानसभा के विभिन्न सत्रों में देखने को मिल चुका है।

50 वर्षों 550 प्रतिशत बढ़ा विधायकों का वेतन

प्रदेश में आम आदमी की सालाना औसत आमदनी 79 हजार 907 रुपए है, जबकि उनके वोट से जीतकर विधानसभा में पहुंचने वाले विधायक को वेतन-भत्तों के रूप में करीब 13 लाख 20 हजार रुपए सालाना मिलते हैं। यानी आम आदमी की इनकम से 18 गुना ज्यादा। बता दें कि एक विधायक को मानदेय के रूप में 1 लाख 10 हजार रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। विधायक को विधानसभा सत्र शुरू होने से तीन दिन पहले से अतिरिक्त भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। सत्र समाप्त होने के 3 दिन बाद तक यह भत्ता मिलता है। इस हिसाब से यदि किसी सत्र में विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ एक दिन चलती है तो भी विधायक को 7 दिन का भत्ता दिया जाता है। प्रदेश में 1972 से विधायकों को वेतन-भत्ते दिए जा रहे हैं। तब उन्हें 200 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अभी 1.10 लाख रुपए है। बीते 50 साल में इनका वेतन 550 प्रतिशत बढ़ चुका है। 5 साल में विधायकों के वेतन-भत्तों पर कुल 149 करोड़ रुपए खर्च किए। मप्र में आखिरी बार विधायकों का वेतन साल 2016 में बढ़ा था। मप्र में 7 साल बाद विधायकों के वेतन-भत्ते बढ़ने का प्रस्ताव है। अभी उन्हें हर महीने 1 लाख 10 हजार रुपए वेतन मिलता है, जो 40 हजार रुपए बढ़ने वाला है। इससे वेतन 1.50 लाख रुपए महीना हो जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री को 2 लाख, तो कैबिनेट मंत्रियों को 1.70 लाख रुपए मिलते हैं। वेतन-भत्ते बढ़ाने के लिए सरकार ने अन्य राज्यों से जानकारी बुलाई है। इसके बाद वेतन-भत्तों व पेंशन पुनरीक्षण के लिए गठित समिति इस पर फैसला करेगी। समिति में वित्त मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री सदस्य हैं। बता दें कि गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में विधायकों के वेतन-भत्ते मप्र से ज्यादा हैं।

अपनी गलतियों में फंस गए सिसोदिया

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड पर हैं। ये वही सिसोदिया हैं जिनके द्वारा शिक्षा में किए गए नवाचार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी पुत्री ने खूब सराहा था। लेकिन वही सिसोदिया शराब माफियाओं के चक्कर में फंसकर इन दिनों सलाखों के पीछे हैं। सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान सीबीआई ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए थे। एक डिजिटल डिवाइस की जांच के दौरान एजेंसी को एक्साइज पॉलिसी ड्राफ्ट दस्तावेजों में से एक को अलग सिस्टम में ट्रेस किया जो एक्साइज डिपार्टमेंट नेटवर्क का हिस्सा नहीं था। आबकारी विभाग के एक अधिकारी से पूछताछ के दौरान एजेंसी को सिसोदिया के दफ्तर के कम्प्यूटर का सुराग मिला। इसके बाद 14 जनवरी को सीबीआई ने सिसोदिया के दफ्तर के कम्प्यूटर को सीज किया। इसमें ज्यादातर फाइलों को डिलीट किया गया था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्राइव किया।

फॉरेंसिक जांच से पता चला कि ये फाइल एक्सटर्नली ऑरजिनेट की गई थीं और व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। इसके बाद सीबीआई ने 1996 के अधिकारी को समन भेजा। यह अधिकारी सिसोदिया का सेक्रेटरी था। अधिकारी ने पूछताछ में बताया कि सिसोदिया ने मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया था। यहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इस दौरान उन्हें जीओएम रिपोर्ट की प्रति दी गई। इस ड्राफ्ट कॉपी से **12 परसेंट प्रॉफिट** मार्जिन क्लॉस जोड़ा गया। लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड या चर्चा शामिल नहीं है कि कैसे 12 परसेंट प्रॉफिट मार्जिन क्लॉस को जोड़ा गया। सीबीआई ने फरवरी के पहले हफ्ते में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अधिकारी के बयान दर्ज कराए और उसे गवाह बनाया। सिसोदिया के कार्यालय से जब्त कम्प्यूटर और उनके सचिव के बयान की मदद से सीबीआई को सिसोदिया तक पहुंचने में मदद मिली।

सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने जब इन सबको लेकर सिसोदिया से सवाल किए तो वे कोई जवाब नहीं दे सके। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने पूछताछ के दौरान उनके खिलाफ कई सबूत रखे। इसमें कुछ दस्तावेज और डिजिटल एविडेंस थे। इन पर सिसोदिया कोई जवाब नहीं दे सके। इतना ही नहीं सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को सबूतों को नष्ट करने का भी आरोपी पाया है। इसमें उनकी मिलीभगत सामने आई है। वहीं, अधिकारी ने सीबीआई को दिए अपने बयान में कहा था कि एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी और जीओएम के सामने आबकारी नीति रखने से पहले कुछ निर्देश भी दिए गए थे। ये बात भी सामने आई है कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शराब नीति में कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए थे जो पहले मसौदे का हिस्सा ही नहीं थे। इस पर सिसोदिया ये नहीं बता सके कि उन प्रावधानों को कैसे शामिल किया। इतना ही नहीं इस बारे में आबकारी विभाग में हुई चर्चा या फाइलों का कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। ज्यादातर सवालों के जवाब में सिसोदिया ने कहा– मुझे नहीं पता।

रिपोर्ट्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पिछले साल 19 अगस्त को सीबीआई ने दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट की छानबीन की। वहां से एक डिजिटल डिवाइस सीज की गई। इस डिवाइस से सीबीआई को पता चला कि लिकर पॉलिसी का एक दस्तावेज एक ऐसे सिस्टम को भेजा गया था, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के नेटवर्क में था ही नहीं।

इसके बाद सीबीआई ने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया। उस अफसर ने एक सिस्टम की जानकारी दी, जिसे एजेंसी ने इस साल 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया। इस सिस्टम की ज्यादातर फाइल्स डिलीट कर दी गई थीं, लेकिन अपनी फॉरेंसिक टीम की मदद से सीबीआई ने ये डेटा हासिल कर लिया। फॉरेंसिक जांच में पता चला की दस्तावेज बाहर से बना और वॉट्सऐप पर रिसीव किया गया। ये जानकारियां हाथ लगने के बाद सीबीआई ने 1996 बैच के ब्यूरोक्रेट को जांच के लिए बुलाया। ये ब्यूरोक्रेट सिसोदिया के सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके थे। सूत्रों के मुताबिक, अफसर ने सीबीआई को बताया कि मार्च 2021 में सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के दफ्तर में बुलाया था। वहां पर अफसर को शराब नीति ड्राफ्ट पर मंत्रियों की रिपोर्ट दी गई। इस दौरान सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे।

● **राजेश बोरकर**

सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा का बड़ा रोल

मीडिया रिपोर्ट्स में सीबीआई सूत्रों के हवाले से बताया गया कि जब लिकर पॉलिसी के जरिए कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा था, उस दौरान सिसोदिया ने एक दिन में 3 फोन बदले थे। सीबीआई ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि सिसोदिया से जो सवाल किए गए, उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। गिरफ्तारी शराब नीति में गड़बड़ियों और इसके जरिए निजी लाभ पहुंचाने के मामले में हुई है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने कई अहम सवालों के जवाब टाल दिए। हमने उनके सामने सबूत भी पेश किए, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया। एजेंसी ने कहा कि उनसे गहराई से पूछताछ के लिए उन्हें कस्टडी में रखना जरूरी है। सीबीआई ने बताया कि सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ की गई। सिसोदिया से शराब नीति, दिनेश अरोड़ा से सिसोदिया के कनेक्शन के बारे में सवाल किए गए। सिसोदिया ने कई फोन कॉल्स भी किए हैं। कई फोन सेट भी नष्ट किए। उनकी डिटेल्स के आधार पर सिसोदिया से सवाल पूछे गए। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के कारोबारी हैं। उनका रेस्टोरेंट है। इसी मामले में ईडी ने भी जांच की है। उसमें दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया का करीबी बताया है। एजेंसी ने कहा कि अरोड़ा से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चुनावी फंडिंग के संबंध में बात की थी। इसके बाद अरोड़ा ने कई कारोबारियों से फंडिंग में सहयोग मांगा और विधानसभा चुनावों के लिए सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए। शराब नीति केस की जांच शुरू होने के बाद अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने ही सिसोदिया और कई बड़े आप नेताओं का नाम लिया था।

सज गई बिसात मिशन 350 की

भाजपा ने लोकसभा चुनावों से डेढ़ साल पहले ही अपने लिए मुश्किल 160 सीटों की पहचान की। 350 से ज्यादा के लक्ष्य के तहत 160 में से हर सीट जीतने की रणनीति तैयार की।

हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं, जिसका लक्ष्य भारत को परम वैभव दिलाना है। इस यात्रा में कोई आपकी पीठ थपथपाए, कोई शाबाशी दे या कोई उपेक्षा करे, आपको प्रसन्न होने या विचलित होने की जरूरत नहीं। आज आप विस्तारक हैं, कल आप प्रदेश के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हौंसले और आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करने वाला यह भाषण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी पिछले ही महीने पटना में पार्टी की भविष्य की रणनीति के लिहाज से एक बड़े अहम मौके पर दे रहे थे। 21-22 दिसंबर को हुए इस प्रशिक्षण शिविर में वे 100 विस्तारक शामिल थे जो चुनावों के लिहाज से पार्टी के लिए 19 राज्यों की मुश्किल सीटों पर काम करने जा रहे थे।

यह शिविर दरअसल ऐसे दो प्रशिक्षण शिविरों की कड़ी में पहला था। 28-29 दिसंबर को हैदराबाद में हुए दूसरे शिविर में 60 विस्तारकों का प्रशिक्षण हुआ। ये विस्तारक 12 राज्यों की मुश्किल सीटों पर काम करेंगे। इन शिविरों की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, महासचिव सुनील बंसल और एक अन्य महासचिव तथा बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे। जिन राज्यों में शिविर हो रहे थे, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, विधायक और पार्टी के दूसरे पदाधिकारी तो थे ही। अपनी पेप टॉक में नड्डा ने इन विस्तारकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने की भी हिदायत दी।

इससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी पार्टी की चुपचाप जमीनी स्तर पर चल रही तैयारियों का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तैयारियां नितांत जमीनी यथार्थ पर खड़े रहकर की जा रही हैं। यही वजह है कि गुजरात विधानसभा चुनावों में पिछले महीने पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत (182 में से 156 सीटें) के बावजूद उसने 2024 के मुश्किल सीटों की संख्या 144 से बढ़ाकर 160 कर दी। उसने अतिउत्साह में आने से पूरी तरह परहेज किया।

पार्टी ने कुछ उसी तर्ज पर अगले लोकसभा चुनावों में 350 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य तय किया है जिस तरह से उसने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। इसे नाम दिया गया है मिशन 350। 160 मुश्किल सीटों की पहचान करके उन पर अभी से सुनियोजित काम करना पार्टी के इसी मिशन का हिस्सा है। जरूरत पड़ने पर मुश्किल सीटों की संख्या 160 से भी आगे बढ़ाई जा सकती हैं।

दरअसल, पार्टी ने पहले चरण में देशभर में 144 मुश्किल सीटों की पहचान की थी। लेकिन दो वजहों से इन सीटों की संख्या 160 की गई। पहला, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यूनाइटेड का भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से किनारा करना। नीतीश के विपक्षी खेमे में जाने की वजह से ही भाजपा को बिहार में मुश्किल सीटों की संख्या चार से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी। और ये 10 सीटें हैं- नवादा, वैशाली, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मुंगेर, झंझारपुर, गया और पूर्णिया।

इसी तरह से महाराष्ट्र में पार्टी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ाया। भाजपा को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र प्रदेश की सत्ता से बेदखल होने के बाद वहां सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ेगी। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस तथा शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीनों की एकता बनी हुई है। अघाड़ी की उसी एकता को देखते हुए भाजपा ने महाराष्ट्र की 10 नई सीटों को अपनी मुश्किल सीटों की सूची में शामिल किया है। राज्य की बारामती, चंद्रपुर, रायगढ़, शिरूर और सतारा जैसी सीटों को पार्टी अपने लिए मुश्किल मानकर चल रही है। भाजपा ने इन 160 सीटों की सिर्फ पहचान ही नहीं की है, इनके लिए अलग रणनीति बनाकर अभी से ही उन पर सघन काम शुरू हो गया है। क्या करना है, उस पूरे काम के समन्वय के लिए छह नेताओं की एक संयोजन समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उसके संयोजक हैं। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, जी किशन रेड्डी, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा समिति के सदस्य हैं। और इन सभी 160 मुश्किल सीटों में से एक-एक की जिम्मेदारी गहन प्रशिक्षण की खुराक प्राप्त एक-एक विस्तारक को दी गई है।

इतनी बारीकी से काम! टीम, समिति,

भाजपा कमजोर सांसदों को देगी एक और मौका

लोकसभा चुनाव में एक बार फिर धमाकेदार जीत की तैयारी कर रही भाजपा लगातार बैठकें कर रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में बजट सत्र के बाद भाजपा ने अहम बैठक बुलाई, जिसमें नई रणनीति के तहत अपने क्षेत्र में कमजोर सांसदों को पार्टी 6 माह का मौका देगी। नई रणनीति के तहत भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में हारी 160 सीटों पर पार्टी के दिग्गज नेताओं को भेजकर उन्हें जनाधार बढ़ाने का जिम्मा सौंपेगी। इतना ही नहीं वे सांसद जो पार्टी की गोपनीय रिपोर्ट में अपने क्षेत्र में कमजोर पाए गए हैं उन्हें 6 माह का मौका देगी कि वे अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करे और ऐसा नहीं करने पर उनका टिकट कटना लगभग तय है। हालांकि 25 से 30 फीसदी सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है।

70 प्लस नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट

लोकसभा चुनाव 2024 में तीसरी बार जीत हासिल करने के लिए भाजपा ने स्ट्रैटजी बनानी शुरू कर दी है। सूत्रों की मानें तो अब हरेक सांसदों के जिम्मे 100 बूथ और विधायकों के जिम्मे 25 ऐसे बूथ होंगे, जहां पार्टी कमजोर है। इसके साथ ही टिकट वितरण समेत कई फैसले किए गए। पार्टी के उच्चस्तर पर इस बात को लेकर सहमति बनी है कि ऐसे मौजूदा सांसद जिनका जन्म 1955 के बाद हुआ है, उन्हें ही 2024 में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। इससे पहले जन्मे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। यानी 70 प्लस के नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। केवल एक-दो अपवादों में ही इस नियम से छूट मिलेगी। यह नियम लागू हुआ तो भाजपा के मौजूदा 301 सांसदों में से 81 को टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी का मानना है कि नए लोगों को तभी मौका मिलेगा जब पुराने कार्यकर्ता, नए लोगों को रास्ता देंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, यह टिकट काटना नहीं बल्कि बैटन अपने से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को सौंपने जैसा है। 17वीं लोकसभा में भाजपा के लगभग 25 प्रतिशत सांसद 2024 के चुनाव तक 70 से अधिक उम्र के हो जाएंगे। 1956 से पहले जन्मे मौजूदा सांसदों में सबसे अधिक उप्र से 12, गुजरात से 10, कर्नाटक से 9, महाराष्ट्र से 5, झारखंड से 2, बिहार से 6, मप्र से 5 और राजस्थान से 5 हैं।

विस्तारक! भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान सवाल का आशय समझते हुए जवाब देते हैं, यह भाजपा की कार्यपद्धति का सहज-स्वाभाविक हिस्सा है। चुनाव की दृष्टि से पार्टी के ध्यान में वे सीटें भी होती हैं, जहां हम मजबूत हैं और उन सीटों पर भी ध्यान दिया जाता है, जहां हमें अपेक्षाकृत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इन सीटों पर मोदी सरकार की योजनाओं का ठीक से प्रचार-प्रसार हो और लोगों को यह बताया जाए कि उनकी बेहतरी के लिए केंद्र सरकार किस तत्परता से काम कर रही है, इसी नजरिए से पार्टी ने अपनी एक व्यवस्था बनाई है। हमें यकीन है कि इन मुश्किल सीटों पर भी 2024 में जीत हासिल होगी।

लेकिन विस्तारकों वाला पहलू थोड़ा हटकर है। उसके सामने दिए गए नड्डा के भाषण से साफ हो जाता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनसे क्या अपेक्षाएं हैं। पहली बात तो यह कि स्थानीय स्तर के नेताओं से अपेक्षित सहयोग और सम्मान मिले चाहे न मिले लेकिन उन्हें अपना काम करते रहना है। उन्हें किसी तरह के शिकवे-शिकायत की झंझट में नहीं फंसना है। दूसरी बात जो उभरकर आती है वह यह कि विस्तारकों को जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है। यहीं एक और पहलू जुड़ता है काशी थीम का। इन विस्तारकों को मुश्किल सीटों पर काशी थीम के आधार पर काम करने को कहा गया है। इसके तहत कश्मीर, अयोध्या, सरकार की योजनाएं, ऑनर यानी गौरव और ईमानदारी को आधार बनाकर भाजपा के लिए मजबूत जमीन तैयार करने की योजना बनी है।

मुश्किल सीटों के लिए बनाई गई रणनीति और उसके क्रियान्वयन में शामिल पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव बताते हैं कि इन मुश्किल सीटों को चार श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं- सर्वोत्तम, अच्छी, सुधार योग्य और बेहद खराब। सर्वोत्तम के तहत वे सीटें हैं, जहां हमने पिछले चुनाव में जीत भले न हासिल की हो लेकिन पार्टी अगर थोड़ा परिश्रम करे तो जीतने की स्थिति में आ सकती है। अत्यंत खराब श्रेणी में वे सीटें हैं, जहां पार्टी या तो कभी नहीं जीती या फिर बहुत लंबे समय से इन सीटों पर जीत नहीं हासिल कर पाई है। मुश्किल सीटों के जातिगत और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए इन पर सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाई जाएगी। साथ ही इन चुनाव क्षेत्रों के असरदार लोगों का समूह बनाकर उनका ऑनलाइन या ऑफलाइन संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कराने की योजना बनाई गई है। इनमें से कम से कम 40 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली आयोजित कराने की भी योजना है। बाकी सीटों पर या तो शाह की रैली होगी या नड्डा की।

इन मुश्किल सीटों के चयन के बारे में सीएसडीएस के प्रोफेसर और लोकनीति के सह-निदेशक संजय कुमार कहते हैं, भाजपा के लिए चुनौती वाली इन सीटों की सूची में सोनिया गांधी की रायबरेली, कमलनाथ के प्रभुत्व वाली छिंदवाड़ा और शरद पवार के असर वाली बारामती जैसी 20-25 सीटें शामिल हैं। 2019 में भाजपा ने राहुल गांधी की सीट अमेठी से जीत हासिल की थी। ये सिर्फ एक सीट नहीं होती बल्कि इनके जीतने से यह संदेश जाता है कि विपक्षी दलों का एक मजबूत किला ढहा दिया। हर सीट पर पार्टी की गतिविधियां सघन तौर पर चल सकें, इसके लिए इन सीटों में से जहां पार्टी कार्यालय का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की रणनीति बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि देश के हर जिले में भाजपा कार्यालय बनाने का काम अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते ही शुरू हुआ था और उसके लिए बाकायदा आठ सदस्यों की एक समिति बनाई थी। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा।

पार्टी की व्यापक रणनीति के तहत ही मुश्किल सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों के रात्रि प्रवास कार्यक्रम की योजना भी बनाई है। इस काम में 40 केंद्रीय मंत्री लगाए जाएंगे। हर केंद्रीय मंत्री को 3-4 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी जा रही है और उन्हें क्लस्टर प्रभारी बनाया जा रहा है। कर्नाटक और ओडिशा की कुल चार लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी उठा रहे एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बताते हैं, पार्टी को लगता है कि अगर केंद्रीय मंत्री खुद आम लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोकसभा चुनावों में पार्टी को पहले के मुकाबले बेहतर जनसमर्थन मिल पाएगा। मंत्रियों को यह भी हिदायत दी गई है कि योजनाओं के लाभार्थियों से जो फीडबैक मिले उसके आधार पर संबंधित राज्यों के राज्यसभा सांसदों और स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर लोकसभा सीटों के भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक समीकरण पर एक रिपोर्ट तैयार करें। इससे पार्टी इन सीटों के लिए बेहतर रणनीति बना पाएगी। भाजपा के 160 विस्तारकों की टुकड़ी अगर मकसद में कामयाब रही तो पार्टी की जमीन का विस्तार कर डेढ़ साल बाद अपने साथ कई नए सांसदों के दस्ते लेकर लौटेगी। सचमुच?

● **विपिन कंधारी**

पिछले दिनों भाजपा कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता को 2024 तक विस्तारित करने की पुष्टि करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अगले आम चुनावों में पुन: भाजपा के वापस सत्ता में आने की घोषणा की। इसमें कुछ विशेष नहीं था। क्योंकि तमाम राजनीतिक विश्लेषक चाहें दक्षिणपंथी हो या वामपंथ के समर्थक, यह मानकर चल रहे हैं कि वर्ष 2024 के आम चुनाव में सीटों के मामूली फेरबदल के साथ एनडीए सरकार के पुन: सत्ता में लौटने के आसार हैं।

विपक्ष के बौनेपन ने बढ़ाया सत्तापक्ष का कद...!

9 वर्ष से सत्तारूढ़ दल पुन: आम चुनावों को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। उसके आत्मविश्वास की क्या वजह है? क्यों उसे पदस्थता विरोध (एंटी इंकम्बेंसी) का भय नहीं है? असल में इसकी मुख्य वजह मृतप्राय विपक्ष है। यह भारतीय राजनीति का ऐसा दौर है, जब विपक्ष होकर भी नहीं है। अर्थात् विपक्ष रीढ़-विहीन, असहाय-सा है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के विरूद्ध संघर्ष का नैतिक बल शेष नहीं रहा है। क्या इस जम्हूरियत में विपक्ष के पास सत्ता के विरोध का कोई आधार ही नहीं बचा हैं? इसकी भी समीक्षा कर लेनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 14 वर्षों में गरीबों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में 41.5 करोड़ (415 मिलियन) लोग गरीबी के चंगुल से बाहर निकले हैं। संयुक्त राष्ट्र इसे ऐतिहासिक बदलाव कह रहा है। किंतु तब भी देश में आज 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। दिसंबर, 2022 में गरीबों की संख्या बढ़कर 8.30 फीसदी पर पहुंच गई। यह पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा रही थी। भारत की खुदरा महंगाई दर अप्रैल, 2022 में पिछले 8 साल के शीर्ष पर पहुंच गई थी। सन् 2014 की एनडीए सरकार के 66 सदस्यीय मंत्रिमंडल में एक समय करीब एक-तिहाई मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें कम-से-कम पांच मंत्रियों के खिलाफ रेप और सांप्रदायिक हिंसा जैसे गंभीर मामले अदालत में चल रहे थे। तब से स्थिति बहुत नहीं बदली आज भी सबसे ज्यादा दागी, अपराधी सत्ताधारी दल के संरक्षण में हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, 2,495 उम्मीदवारों के हलफनामों अवलोकन से पता चलता है कि कुल 363 सांसदों और विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इन 363 में 83 सदस्यों (सांसद और विधायक दोनों) के साथ भाजपा सूची में शीर्ष राजनीतिक दल हैं, जिनके सदस्यों ने उनके खिलाफ आपराधिक आरोप घोषित किए हैं। भाजपा के चार केंद्रीय मंत्रियों पर अपहरण, डकैती और मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। दूसरी ओर, आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष भी कमजोर पड़ा है। याद रहे, कश्मीर में धर्म आधारित आतंकवाद एवं कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन का मुद्दा उठाकर भाजपा ने देशभर से समर्थन बटोरा। अब भाजपा ही आतंकवाद एवं कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं को धार्मिक नजरिये से न देखने की सलाह दे रही है। इसके दो ही अर्थ हैं- पहला, या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं। दूसरा, आप अनैतिक-सिद्धांतविहीन दल हैं, जो सत्ता के लिए कुछ भी कह और कर सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में कांग्रेस नेताओं के जिस अहंकारपूर्ण रवैये एवं उसके शीर्ष नेतृत्व के स्वेच्छाचार की सदैव आलोचना होती रही है। आज यही विकृति भाजपा नेतृत्व में है, बल्कि कहीं अधिक असभ्य रूप में है। साथ ही आज राज्य से लेकर केंद्र तक भाजपा में ऐसे नेताओं की बहुलता है, जो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण सरकार से लेकर पार्टी पदों पर जमे हुए हैं। ऐसे और भी गंभीर मसले हैं, जिनके आधार पर विपक्ष सरकार के विरूद्ध गंभीर विमर्श और आंदोलन पैदा कर सकता था। जिन मुद्दों के सहारे आज के विपक्ष और बीते कल के सत्तापक्ष की कटु आलोचना

क्या नीतीश कर पाएंगे समाधान?

नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दलों के आपस में टकराते हितों को साधते हुए एक मंच पर लाने की होगी। इसे हल कर पाना आसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सभी राज्यों में एक सोची-समझी रणनीति के अनुसार सीटों के आधार पर गठबंधन बनाकर और सभी दलों को एक सम्मानजनक संख्या में सीटें देकर एक मंच पर लाने की कोशिश की जा सकती है। पूर्व में यूपीए और एनडीए में इस तरह के गठबंधन कामयाब हुए हैं। लिहाजा एक नई रणनीति के अनुसार इसे अमल में लाया जा सकता है। जहां तक प्रमुख विपक्षी दलों का संबंध है, तो यहां हाथ अपनी पकड़ ढीली कर रहा है। कांग्रेस ने हाल के दिनों में पहली बार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर खुलकर हमला बोला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी के नेता कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई बैठकों में शामिल होते हैं, लेकिन बाद में एक लाइन कहते हैं, जो सत्तारूढ़ भाजपा से मेल खाती है। टीएमसी सहित सारा विपक्ष अडानी मुद्दे पर एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के लिए सहमत हुआ था, लेकिन बाद में टीएमसी ने अदालत की निगरानी में जांच की बात कही। यह शायद पहला मौका है जब कांग्रेस ने टीएमसी पर भाजपा की बी-टीम होने का आरोप लगाया है। कुछ ऐसा ही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगाया जाता रहा है।

करके भाजपा ने देश में अपना राजनीतिक रसूख पैदा किया, वे सारे दुर्गुण आज खुद उसके अंदर मौजूद हैं। फिर भी विपक्ष अगर जनता के समक्ष इसे आंदोलित रूप में उपस्थित नहीं कर पा रहा है, तो यह उसकी कमजोरी है। वास्तव में विपक्ष की अपनी दुनिया है। उसे सरकार में बढ़ती नौकरशाही की दादागीरी के विरोध से कोई मतलब नहीं। विपक्ष विरोध करेगा, तो हर घर झंडा अभियान का। वह सेना के अभियानों के दावों पर सवाल उठाएगा। भारतीय सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत को अपमानित करेगा। उसे यह तक नहीं पता की सरकार का विरोध करते-करते, वह राष्ट्रविरोध की सीमा तक पहुंच जाता है। अगर मदरसों के सर्वे से उनमें व्याप्त अनियमितता दूर की जा सके और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज बिलकिस बानो मामले में धार्मिक आधार पर पक्ष बन जाने का कारण ही यही है कि विपक्ष को गोधरा के पीड़ितों के परिवारों के दर्द याद नहीं है। ऐसी एक तरफा तकरीरें समाज में विखंडन पैदा करेंगी और सत्ताधारी दल को लाभ भी पहुंचाएंगी। विपक्ष जनता से आंदोलित होने की अपील कर रहा है, लेकिन खुद के स्वार्थानुकूल। जो कांग्रेस गांधी परिवार के विरूद्ध ईडी की जांच रुकवाने के लिए सड़कों पर उतर आया, वह बच्चों द्वारा अग्निपथ योजना के विरोध के समय मात्र ट्विटर और न्यूज चैनलों पर बयानबाजी कर रहा था। असल समस्या ये है कि विकास की दौड़ में भारतीय राजनीति विलासी हो गई है। एक भी दिन विपक्षी खेमे से प्रधानमंत्री पद की महत्वकांक्षा पाले बैठा कोई नेता बेरोजगारी, सरकारी रिक्तियों पर कुंडली मारे बैठी केंद्र एवं राज्य सरकारों, प्रशासनिक अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली, कमीशनखोरी जैसे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरा? कोई धरना-प्रदर्शन या अनशन किया? फिर जनता आपके साथ कैसे खड़ी हो?

बस सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों के पास धर्म-जाति का झुनझुना है। दोनों चाहते हैं कि बस इसे बजाएं और जनता इसमें उलझी रहे। विपक्ष ने लोकतंत्र के संघर्ष को निजी लड़ाई में तब्दील कर दिया है। यही वजह है कि जनता भी विपक्ष के समर्थन में नहीं आ रही। अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो विपक्ष को जांच का निर्भीक होकर सामना करना चाहिए। लेकिन इनकी बेचैनी जनता के अंदर संदेह उत्पन्न करती है। हालांकि सरकार निरंतर शुचिता स्थापित करने का दावा करती रही है और ऐसा करती हुई दिखना भी चाहती है। इसीलिए ईडी और सीबीआई के छापे तथा धर-पकड़ अभियान जारी हैं। लगातार नेताओं एवं नौकरशाहों के भ्रष्टाचारों की जांच हो रही है। एक तरफ मोदी-शाह जैसे जमीनी राजनीति एवं सांगठनिक अनुभव में तपे-परखे लोग हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक की वंशवाद-परिवारवाद से उपजे नेताओं की फौज है। चूंकि इन्हें बिना संघर्ष के, बिना जमीनी हकीकत के पार्टी की सत्ता मिली है। अपरिपक्वता से भरे, पीड़ित ये नेता कब क्या बोल देंगे? किसके बारे में बयान दे देंगे? ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। इससे भाजपा नेताओं को उपहास करने और गंभीर मुद्दों को हल्के स्तर की परिचर्चा में तब्दील कर देने का अवसर मिल जाता है। और उन्हें यह गलतफहमी हो जाती है कि इसी से जनता सतही बातों में उलझकर रह जाएगी। परंतु अब इससे काम चलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर ली। भाजपा विरोधी राजनीतिक-सामाजिक एवं मीडिया वर्ग ने इसे खासी तरजीह दी, किंतु यह यात्रा भी धार्मिक एकता, सद्भावना, भाईचारे के वही पुराने मुद्दे पर आधारित थी। केवल आजादी के संघर्ष में कांग्रेस की भागीदारी, नानाजी-दादीजी ने देश को आजाद कराया और उसके लिए जान दी। हमारे पिताजी लोहिया के उत्तराधिकारी थे, और असली समाजवादी हमारी ही पार्टी है। हमारे पिताजी अगड़ा के खिलाफ पिछड़ा-दलित की लड़ाई लड़े और सामाजिक न्याय के मसीहा थे, इत्यादि रटी हुई बातें...बस। विपक्ष के कर्णधारों को ये समझना ही होगा कि पुराने प्रतीकों-नारों से आधुनिक लोकतंत्र का संघर्ष नहीं किया जा सकता। ऊपर से विपक्ष में उम्मीदों को पलीता **लगाने वाले नेताओं** की कमी नहीं है। कभी रामचरितमानस का अपमान, तो कभी जातिवाद के आश्रय से 21वीं सदी के लोकतंत्र के सिरमौर बनने का ख्वाब मूर्खतापूर्ण है। विपक्ष अपने मनुवाद-सामंतवाद के पुरातन नारे से निकल ही नहीं पा रहा है। और ऐसी तकरीरें स्वयंभू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की उन्नायक सत्तारूढ़ दल के समर्थन में और इजाफा करती हैं तथा उसकी चुनावी रणनीति के भी अनुकूल है। सत्ता में टिकने की इच्छुक कोई भी सरकार राष्ट्रवाद या धर्म के आधार पर लामबंदी करने का प्रयास करेगी ही करेगी।

● **इन्द्र कुमार**

क्या महागठबंधन संभव है?

महागठबंधन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला का कहना है कि यह विपक्ष की खिचड़ी है जो कभी नहीं पकती। इसका बड़ा कारण है कि इन दलों के अपने राजनीतिक हित एक-दूसरे के साथ टकराते हैं। इनमें से कोई दल अपना राजनीतिक बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होगा, लिहाजा इस तरह के गठबंधन की बात केवल जुबानी जमाखर्च से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता ने दिखा दिया है कि इस तरह के अवसरवादी गठबंधन उसे किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हैं। पूर्व में उप्र में इसी तरह का गठबंधन सपा-बसपा और सपा-कांग्रेस के बीच हो चुका है और इनका परिणाम शून्य रहा है। नेताओं के बीच के गठबंधन के होते हुए भी एक दल के वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर नहीं हुए, इसे देखते हुए भी महागठबंधन बनाने की कोशिश करने वाले नेताओं को सीख लेनी चाहिए। प्रेम शुक्ला का कहना है कि नीतीश कुमार बिहार में भी तीसरे नंबर के दल हैं। वे बिहार के कब तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे, यह तय नहीं है। बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता अब लगभग समाप्त हो चुकी है और अपने डेढ़ दशकों से ज्यादा के समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार को विकास के पैमाने पर कहीं नहीं ले जा सके हैं। उन्होंने कहा कि अपनी खोती प्रासंगिकता को बचाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह का सियासी शिगूफा छोड़ रहे हैं। वे स्वयं भी जानते हैं कि इस कवायद का कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

छग में राहुल के लिए जमीन तैयार

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का तीन दिनी महाधिवेशन सपन्न हो गया। इस अधिवेशन का लबोलुआब यह था कि राहुल गाधी के लिए जमीन तैयार करनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी की नजरों में उतनी ही अहमियत रखते हैं, जितना अशोक गहलोत। राजस्थान के मामले में जो रवैया अशोक गहलोत ने अख्तियार कर रखा है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का भी वही हाल है। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट के लिए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं हुए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने टीएस सिंह देव से किया गया राहुल गांधी का वादा नहीं पूरा होने दिया। जैसे गहलोत बार-बार राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की मांग करते रहे, इस बार भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी का नाम उछाल दिया है। कहते हैं, देश के हालात बेहद खराब हैं, सभी की नजरें राहुल गांधी पर हैं।

जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठाते रहे हैं, उनको सामने रखते हुए भूपेश बघेल कहते हैं, ऐसे वक्त जब राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा करते हैं, आज पूरा देश राहुल गांधी की ओर उम्मीदों भरी निगाह से देख रहा है। लगे हाथ ये भी दावा कर डालते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है क्योंकि उनकी सरकार राहुल गांधी के विजन पर काम कर रही है। राहुल गांधी ने जो लोगों से वादा किया था, सरकार पूरा करने में सफल रही है। और फिर अपना सबसे बड़ा दांव चल देते हैं, कांग्रेस है तो विश्वास है, हम सबकी इच्छा है कि राहुल जी नेतृत्व करें और 2024 में प्रधानमंत्री बनें।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तक राष्ट्रीय अधिवेशन में कई नेताओं के भाषण में विपक्षी एकता पर जोर देखने को मिला है। कांग्रेस की तरफ से विपक्ष को जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें यूपीए के ही नए वर्जन की झलक मिलती है, लेकिन शर्तें पहले की ही तरह लागू हैं। बल्कि पहले वाले ही कंडीशन है, नए सिरे से घोषणा कर दी गई है। और अपनी तरफ से कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में भी नया अपडेट पेश कर दिया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राहुल गांधी की सफल यात्रा के बाद नई पेशकश भी विपक्ष पर दबाव बढ़ाने की ही रणनीति लगती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी तपस्या का जिक्र किया, पहले ही संकेत मिल गए थे कि अगला एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से ठीक पहले देश के लोगों के नाम एक संदेश जारी किया था और उसमें तपस्या का जिक्र किया था। बाद में भी कई बार राहुल गांधी अपनी यात्रा को तपस्या के तौर पर लोगों के बीच रखने की कोशिश कर चुके हैं। कांग्रेस अधिवेशन खत्म होने के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यात्रा के अगले स्वरूप की रूपरेखा समझाने की कोशिश की। जयराम रमेश के मुताबिक, हो सकता है ये यात्रा पासीघाट से शुरू हो और इसका समापन पोरबंदर में हो। इसे लेकर काफी उत्साह है। निजी तौर पर मेरा मानना है कि इसकी जरूरत भी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कदम-कदम पर लोगों को अपडेट देते रहे जयराम रमेश का कहना है कि पूरब से पश्चिम के बीच निकलने वाली यात्रा का प्रारूप, दक्षिण से उत्तर की ओर निकाली जाने वाली यात्रा से अलग होता है, शायद ये यात्रा उतने व्यापक स्तर पर न हो। भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने से लेकर समापन तक कांग्रेस ने विपक्ष को साथ लेने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कुछ तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की निजी वजहों से, और कुछ विपक्षी नेताओं के राहुल गांधी से परहेज के कारण।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि हर कांग्रेसी ही नहीं, बल्कि हर देशवासी को आगे बढ़कर ये नारा लगाना होगा, क्योंकि आज देश को इसकी जरूरत है, क्योंकि देश कठिन दौर से गुजर रहा है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस नेतृत्व को बार-बार आगाह कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी विपक्ष को उसी अंदाज में जवाब दिया है, सिर्फ एक साल का वक्त है। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन में प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को कांग्रेस से सबसे ज्यादा उम्मीद है। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से सलाहभरी अपील की। उन्होंने कहा कि हम सब को एकजुट होकर लड़ना होगा, विपक्षी दल एक साथ आएं, हमें एक साथ होना चाहिए। साथ लड़ने की जरूरत है। प्रियंका गांधी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विपक्षी दलों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 2023 और 2024 में हमारा एजेंडा साफ है, हम देश के मुद्दों पर संघर्ष भी करेंगे, कुर्बानी भी देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने विपक्ष को कांग्रेस की तरफ से की जा रही पेशकश को भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। वे बोले, 2004 से 2014 के बीच यूपीए गठबंधन में समान विचारधारा वाले कई दल हमारे सहयोगी थे, 10 साल हमारी सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को सामने रखकर चली, आज फिर से उसी गठबंधन को और मजबूती देने की जरूरत है। मतलब, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि विपक्ष यूपीए 3 के लिए मन बना ले और कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि वे तमाम दल जो भाजपा और आरएसएस के खिलाफ हैं, हम उनको भी अपने साथ लेने को तैयार हैं।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

मुकाबले का सीन ही कहां है

हाल की में एक चुनावी रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दावा रहा कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में ही विपक्ष की सरकार बनेगी और अब उसी चीज पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी मुहर लगा दी गई है। लेकिन पेंच वहीं फंसा है। कांग्रेस उन राज्यों में भी ड्राइविंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है जहां बस जैसे-तैसे सांस ले पा रही है। 2020 में बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस 19 विधायक ही जुटा पाई, तो आरजेडी के नेता आक्रामक हो गए थे। 2017 में जब 100 से ज्यादा सीटें देने के बाद भी कांग्रेस के 7 ही उम्मीदवार जीत पाए तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन ही तोड़ लिया था। आज की तारीख में उप्र में कांग्रेस के सिर्फ दो विधायक हैं, लेकिन न तो वो अखिलेश यादव के लिए ड्राइविंग सीट छोड़ने को तैयार है, न ही बिहार में अगली बार समझौते के आसार समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस खुद तो डूबेगी ही, क्षेत्रीय दलों को भी डुबाएगी, अगर वे उसकी शर्तें मानने को राजी नहीं हुए। और जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रही है, वहां तो उसकी कोई ऐसी शर्त समझ में नहीं आती। महाराष्ट्र की सरकार तो जाती रही, लेकिन झारखंड, तमिलनाडु और बिहार में अब भी कांग्रेस सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है लेकिन जिन राज्यों में विपक्षी खेमे की पार्टियों की सरकारें हैं, वे कांग्रेस से पहले से ही दूरी बनाकर चल रहे हैं।

अब शिवसेना शिंदे की

शिवसेना मामले में अब आगे क्या?

आयोग ने पिछले साल अक्टूबर में ठाकरे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और सिंबल जलती हुई मशाल दी थी। आयोग ने कहा है कि फिलहाल ठाकरे गुट यही नाम और सिंबल इस्तेमाल करेगा। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। हालांकि, कानून कहता है कि राजनीतिक पार्टी में विवादों का निपटारा सिर्फ चुनाव आयोग ही कर सकता है। दरअसल, 1967 में जब एसपी सेन वर्मा मुख्य चुनाव आयुक्त बने तो उन्होंने एक चुनाव चिन्ह आदेश बनाया, जिसे सिंबल ऑर्डर 1968 कहा जाता है। इस ऑर्डर के पैरा 15 में लिखा है कि राजनीतिक पार्टी में विवाद या विलय की स्थिति में फैसला लाने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग के पास है। 1971 में सादिक अली बनाम चुनाव आयोग के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 15 की वैधता को बरकरार रखा था। राजनीतिक पार्टी का असली मालिक कौन होगा? इसका फैसला मुख्य रूप से तीन चीजों पर होता है। पहला- चुने हुए प्रतिनिधि किस गुट के पास ज्यादा हैं? दूसरा- ऑफिस के पदाधिकारी किस ओर हैं? और तीसरा- संपतियां किस तरफ हैं? लेकिन, किस धड़े को पार्टी माना जाएगा? इसका फैसला चुने हुए प्रतिनिधियों के बहुमत के आधार पर होता है। मसलन, जिस धड़े के पास ज्यादा चुने हुए सांसद-विधायक होंगे, उसे पार्टी माना जाएगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का धड़ा ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे को दे दिया है। 78 पन्नों के फैसले में चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम शिवसेना और सिंबल धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट को दे दिया। आयोग ने ये भी बताया कि पिछले साल अक्टूबर में शिंदे गुट को जो पार्टी का नाम बालासाहेबांची शिवसेना और सिंबल दो तलवार और एक ढाल दिया था, उसे अब फ्रीज कर दिया जाएगा। हालांकि, उद्धव ठाकरे ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जरूरी दी है। लेकिन चुनाव आयोग का ये फैसला एक ओर जहां उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका है तो दूसरी ओर शिंदे गुट के लिए ये बड़ी जीत है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने जैसा बताया है। वहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे सच्चाई की जीत कहा है।

पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी। शिंदे शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों को अपने साथ ले गए थे और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इस सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में हुए इस सियासी बदलाव के बाद से ही उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली शिवसेना की लड़ाई चल रही थी।

अपने फैसले में चुनाव आयोग ने बताया है कि शिंदे गुट को ही असली शिवसेना क्यों माना गया है? चुनाव आयोग ने बताया कि एकनाथ शिंदे के पास 55 में से 40 विधायकों और लोकसभा के 18 में से 13 सांसदों का समर्थन है। अपने आदेश में चुनाव आयोग ने बताया, शिंदे के समर्थन में जो 40 विधायक हैं, उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में 36.57 लाख यानी 76 फीसदी वोट मिले थे। जबकि, ठाकरे गुट के पास जो 15 विधायक हैं, उन्हें 11.25 यानी लगभग 23.5 फीसदी वोट ही मिले थे। आयोग के मुताबिक, 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना को कुल 90.49 लाख वोट मिले थे। इसमें हारे हुए उम्मीदवारों को मिले वोट भी शामिल हैं। इनमें से करीब 40 विधायक शिंदे गुट के समर्थक विधायकों को मिले थे और 12 फीसदी वोट ठाकरे गुट के विधायकों को। इतना ही नहीं, शिंदे गुट का समर्थन करने वाले 13 लोकसभा सांसदों को 2019 के चुनाव में 1.02 करोड़ यानी करीब 73 फीसदी वोट मिले थे। वहीं, उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो पांच लोकसभा सांसद हैं, उन्हें 27.56 लाख यानी 27 फीसदी वोट मिले थे।

चुनाव आयोग के इस फैसले को उद्धव ठाकरे ने लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार का गुलाम बन गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि ये फैसला पार्टी संविधान के परीक्षण और बहुमत के परीक्षण के आधार पर लिया गया है। आयोग के मुताबिक, ठाकरे गुट ने पार्टी के नाम और सिंबल पर दावे के लिए 2018 के पार्टी संविधान का हवाला दिया था। लेकिन पार्टी ने 2018 में हुए संशोधन के बारे में चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दी थी।

चुनाव आयोग के इस फैसले से एक बात साफ हो गई और वो ये कि अब शिवसेना पार्टी पूरी तरह से एकनाथ शिंदे की हो गई है। ये फैसला ठाकरे परिवार के लिए इसलिए झटका है, क्योंकि ये पहली बार है जब शिवसेना से ठाकरे परिवार का कंट्रोल हटा है। शिवसेना की स्थापना 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने की थी और तब से ही इस पार्टी को ठाकरे परिवार चला रहा था। वहीं, ये एकनाथ शिंदे के लिए इसलिए बड़ी जीत है, क्योंकि अब पार्टी पर उनका अधिकार है। पार्टी से जुड़े सारे फैसले एकनाथ शिंदे ही लेंगे। कुल मिलाकर 54 साल से जो पार्टी ठाकरे परिवार के हाथों में थी, वो अब शिंदे के हाथ में आ गई है। इतना ही नहीं, अब ठाकरे गुट के विधायकों और सांसदों पर भी नया खतरा खड़ा हो गया है। वो ये कि इनके खिलाफ अब अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

ये पहला मौका नहीं है, जब किसी राजनीतिक पार्टी में दावे को लेकर दो धड़ों में जंग छिड़ गई हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव बनाम शिवपाल यादव, आंध्र प्रदेश में एनटीआर बनाम चंद्रबाबू नायडू, अपना दल में अनुप्रिया पटेल बनाम कृष्णा पटेल में जंग हो चुकी है। पिछले साल लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान बनाम पशुपति कुमार पारस के बीच भी बंटवारा हो गया था। दो साल पहले जब लोक जनशक्ति पार्टी में जंग हुई तो पशुपति कुमार पारस ने खुद को पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर दिया था। बाद में मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के पास गया, तो उन्होंने पशुपति कुमार पारस को लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल का नेता चुन लिया था। एलजेपी के लोकसभा में 6 सांसद हैं, जिनमें से 5 सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए थे। बाद में चिराग पासवान ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी, लेकिन अदालत में ये याचिका खारिज हो गई थी।

● **बिन्दु माथुर**

वसुंधरा राजे के लौटेंगे दिन?

राजनीति की माहिर खिलाड़ी वसुंधरा राजे

भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति की माहिर खिलाड़ी मानी जाती हैं। भैरो सिंह शेखावत को छोड़ दें, तो वसुंधरा राजे ही एकमात्र नेता हैं, जिनके पास भाजपा की ओर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का अनुभव है। वसुंधरा राजे दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं। वे राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी थीं। वे दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 और दिसंबर 2013 से दिसंबर 2018 तक मुख्यमंत्री रही हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने से पहले वसुंधरा राजे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। 69 साल की वसुंधरा राजे फ़िलहाल भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झालरापाटन से विधायक हैं। 2013 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में भाजपा ने राज्य की 200 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ 21 सीट पर सिमट गई थी।

राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। ऐसे में यहां मप्र के साथ नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकता है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 101 सीट का है। राजस्थान में पिछले 6 चुनाव से भाजपा और कांग्रेस बारी-बारी से सत्ता में आती है। ये सिलसिला 1993 से जारी है। 1993 से यहां कोई भी पार्टी लगातार दो बार चुनाव नहीं जीत सकी है। परंपरा कायम रहने के हिसाब से देखें, तो सत्ता की दावेदारी भाजपा की बन रही है। लेकिन राज्य में पार्टी की सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता वसुंधरा राजे के रुख से भाजपा की चिंता बढ़ गई है।

जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, भाजपा के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल सभी के जेहन में दौड़ने लगा है। मुख्यमंत्री फेस बनने के लिए भाजपा में दावेदारी बढ़ते जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही कई ऐसे नाम हैं, जो अपने-अपने तरीके से खुद को इस रेस में मान रहे हैं। इनमें आमेर से एमएलए और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थान के **सियासी गलियारे** में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम की भी सुगबुगाहट है। इनके अलावा स्थानीय नेता गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर और किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता भी शामिल हैं, जो अपने हिसाब से खुद के लिए अभियान चला रहे हैं। हालांकि इनमें कोई भी नेता खुलकर अपनी दावेदारी पर बात नहीं कर रहा है। वैसे तो हर राज्य में चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खुले मंच से ऐलान कर चुके हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर लड़ा जाएगा। अगर चुनाव तक वसुंधरा राजे के आक्रामक तेवर ऐसे ही बने रहे, तो भाजपा, कांग्रेस के अंदरूनी कलह का फायदा उठाने से चूक सकती है। ये जगजाहिर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 2018 से ही तनातनी है। ऐसे में भाजपा इसका फायदा उठाना चाहेगी। इसके लिए जरूरी है कि वसुंधरा राजे पूरे मन से भाजपा के हाल में सक्रिय हो चुकी है। करीब ढाई दशक से राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द-गिर्द ही घूमते रही है। पर जीत के बाद कौन? यह प्रश्न बना रहता है। कई नाम आ रहे थे पर उन सब के मंथन करने के बाद जो नाम उभरकर आ रहा है वह है वसुंधरा राजे का।

राजस्थान की राजनीति में पुराने गठजोड़ ताजा होने से विरोधी कैंप सतर्क होने लगे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद किरोड़ी लाल मीणा की गुफ्तगू सियासी गलियारों में हलचल का सबब बन गई है। पूर्व में डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे एक-दूसरे के घोर विरोधी माने जाते थे, परंतु पिछले कुछ समय से दोनों के बीच जिस प्रकार से नजदीकियां बढ़ीं हैं वो सभी को बता रही है कि क्या होने वाला हैं। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की सभा के बाद दोनों ही नेताओं में लंबी अवधि तक हुई गुफ्तगू भाजपा के विरोधी गुट में कौतूहल का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री की सभा के बाद दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई है, दरअसल जब राजस्थान पेपर लीक को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। तब भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर लिखा था कि डॉ. साहब अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि आनन-फानन में भाजपा के नेताओं का डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के धरना स्थल पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसी के बाद डॉ. किरोड़ी लाल ने भी अपने बयान में भाजपा के प्रदेश इकाई अध्यक्ष सतीश पूनिया को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि पूनिया से निराश हैं और उनको भाजपा प्रदेश इकाई से कोई भी सहयोग नहीं मिला, जिसके बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी।

प्रधानमंत्री की सभा के बाद हुई दोनों नेताओं की बैठक को सियासी जानकार किसी गठजोड़ से भी जोड़कर देख रहे हैं। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को पूर्वी राजस्थान का कद्दावर नेता माना जाता है और पूर्वी राजस्थान की 50 सीटों पर इनका भी प्रभाव देखा जाता है। हालांकि जो भीड़ और समर्थन भारत जोड़ो यात्रा के दौसा आने पर दिखा था वो प्रधानमंत्री की रैली में नहीं नजर आया जिसका प्रमुख कारण मीणा हाईकोर्ट से रैली को कैंसिल कर स्थान परिवर्तन बताया जा रहा है। जिसके चलते मीणा समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं।

कांग्रेस में सचिन पायलट के कारण गुर्जर नाराज हैं और जिसका पूरा फायदा भाजपा लेने की जुगत में लगी हुई है, ऐसे में डॉ. किरोड़ी लाल मीणा का एक बार बढ़ता हुआ कद पूर्वी राजस्थान में **भाजपा को बढ़त** दिला सकता है। वहीं दूसरी ओर दोनों नेताओं वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के बीच की बातचीत भाजपा के ही बड़े नेताओं की धड़कन बढ़ रही है। 2018 में भाजपा में ही घोर विरोध के बाद भी वसुंधरा राजे 72 सीट लाने में कामयाब हुई थीं, जिसमें 5 साल सरकार चलाने के बाद का विरोध और भाजपा का अंदरूनी विरोध भी शामिल था। इसलिए इस बार भी वसुंधरा राजे की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

अर्थ के मंत्र से बड़ा लक्ष्य

उ प्र के ताजा बजट में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे कामों को आगे बढ़ाने का संकेत देकर भाजपा के राजनीतिक रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश साफ दिखती है। बजट में मदरसों के विकास तथा मुस्लिम छात्रों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने में मदद के लिए घोषणाएं कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर काम करने का संदेश दिया गया है। पर, यह संदेश इस सावधानी के साथ दिया गया है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर सरकार के दृढ़ता से काम करने पर सवाल न उठे।

प्रदेश का बजट एक तरह से केंद्र सरकार के बजट की घोषणाओं को प्रदेश में आगे बढ़ाने का रास्ता आसान बनाता नजर आ रहा है। साथ ही यह भी संदेश देने की कोशिश करता दिख रहा है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार के कारण काफी बदलाव हुआ है। इस बदलाव को जारी रखने के लिए आगे भी केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार जरूरी है। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार की अपेक्षा है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर हो जाए, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। योगी सरकार का 2023-24 का बजट **उसी दिशा में काम** को आगे बढ़ाता दिख रहा है। जिसका प्रमाण बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए होना है।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, योगी सरकार ने लगातार दूसरी बार रिकार्ड आकार का बजट लाकर तथा इसका बड़ा हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर खर्च करने का प्रावधान करके भविष्य का संकेत साफ कर दिया है। इस बजट में सड़कों के निर्माण, बिजली आपूर्ति का प्रबंध, गांवों की दशा सुधारने, शहरों को सड़क तथा हवाई मार्गों से जोड़ने एवं आंतरिक परिवहन को सुधारने, मेट्रो रेल परियोजना सहित अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए उद्योगपतियों को राज्य के बड़े बाजार से लाभ उठाने का जो संदेश देने की कोशिश की है, उसका लाभ निकट भविष्य में दिखाई देगा। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर करने का सपना भी साकार करने में मदद मिलेगी।

अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, बजट का आकार प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष काफी बड़ा है। यह प्रदेश सरकार की राज्य की आर्थिक मजबूती के लिए काम करने का प्रमाण है। अर्थशास्त्री प्रो. अंबिका प्रसाद तिवारी कहते हैं कि बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ रुपए है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 34 प्रतिशत बैठता है जबकि केंद्र के बजट का आकार जीडीपी का लगभग 14 प्रतिशत ही है। बजट में विकास और बुनियादी ढांचे पर ज्यादा फोकस एक तरह से प्रदेश के अर्थतंत्र को और मजबूत कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम का संकल्प है। सरकार का बजट में किया गया यह दावा कि कानून-व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर फोकस के चलते ही प्रदेश में निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसका प्रमाण इसी महीने लखनऊ में हुई ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए हुए समझौते हैं। यह आंकड़ा सरकार के लोगों को रोजगार, नौकरी जैसे विकल्पों को बढ़ाने के वादे को मदद करता दिख रहा है। वहीं सरकार पर लोगों की अपेक्षाओं का बोझ भी कम करने वाला नजर आ रहा है। रोजगार के ज्यादा अवसर और काम करने के ज्यादा मौके निश्चित रूप से सरकार को राजनीतिक लाभ देंगे ही।

बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों सहित हर वर्ग के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था, युवाओं को लैपटॉप व टैबलेट मुहैया कराने के लिए धन का इंतजाम, वैकल्पिक ऊर्जा, प्राकृतिक व मोटे अनाज की खेती, ग्रीन एनर्जी पर काम को प्रोत्साहन, **छुट्टा पशुओं** से होने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए किए गए उपायों की घोषणा शामिल है। अर्थ के सहारे सभी को संतुष्ट कर सबको साधने की कोशिश दिख रही है। बजट में अल्पसंख्यकों के लिए भी की गई घोषणाएं तथा मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के प्रबंध, अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सुविधाओं पर ध्यान सरकार की पसमांदा मुस्लिमों में भी सेंधमारी की कोशिश दिखाती है। वहीं, सरकार ने बजट के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को धार देकर चुनावी गणित को 60 बनाम 40 बनाने की कोशिश को भी नजरों से ओझल नहीं होने दिया है। अयोध्या, मथुरा, काशी, विंध्याचल सहित हिंदुओं की आस्था से जुड़े अनेकों स्थानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके साथ सिख, जैन, बौद्ध मतावलंबियों की आस्थाओं पर काम के लिए धन की व्यवस्था तथा प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिए भव्य इंतजामों का संकल्प व्यक्त किया गया है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना का संकल्प योगी सरकार के सांस्कृतिक एजेंडे पर काम करने के लक्ष्य को साधते हुए दिख रहा है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

बेरोजगारी दर घटाने पर फोकस

बजट में वित्तमंत्री ने बेरोजगारी दर घटाकर 4.2 प्रतिशत होने की बात सबसे पहले की। लेकिन डायरेक्ट वैकेंसी निकालने की एक भी बात नहीं की। हां, अलग-अलग फील्ड में रोजगार मिलने की बातें कई बार कीं। इसके साथ 5 साल में 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कौशल विकास मिशन के तहत पिछले सालों में 4.88 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। लेकिन नई नौकरियां कितने युवाओं को मिलेगी इसका जिक्र नहीं है। एन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए के सीड फंड की व्यवस्था की गई। आईटी और स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। युवा वकीलों को पढ़ाई-लिखाई के लिए कुल 15 करोड़ रुपए दिया गया है। पूरे बजट में सरकार का सबसे ज्यादा फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ही है। करीब-करीब सभी पुराने प्रोजेक्ट्स में बजट बढ़ाया है। गोरखपुर-वाराणसी जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट का विस्तार दिया जाएगा। कानपुर मेट्रो का भी विस्तार होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के किनारे 6 जगहों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाया जाएगा। राज्य के दो पिछड़े इलाकों पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विशेष योजना के लिए अलग से बजट जारी किया गया है। इसमें पूर्वांचल के लिए 525 करोड़ और बुंदेलखंड के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

राजद को राम नाम से नफरत क्यों?

अगर आप हिंदू हैं, तो संभवत: रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से आपकी भावना भी आहत हुई होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। यह नफरत को बोने वाले ग्रंथ हैं। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, तीसरे युग में गुरु गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये सभी देश को, समाज को नफरत में बांटते हैं।

प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जब ये बयान दिया था तो वो अधिकारिक रूप से, शिक्षा मंत्री होने के कारण नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित थे। इस लिहाज से ये मानने में कोई हर्ज नहीं कि ये बिहार सरकार के मंत्री का अधिकारिक बयान था। वो राजद के नेता हैं इसलिए उनके बयान को राजद और उसके समर्थकों की अधिकारिक वैचारिक स्थापना मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। अब सवाल है कि इतने पर बात खत्म हो जाती है क्या? नहीं, असल में बात यहीं से शुरू होती है और बिहार की राजनीति की करवट को समझने के लिए हमें इसे अन्य घटनाओं से मिलाकर देखना होगा। सबसे पहली बात जो इस एक घटना में दिखती है, वो ये है कि यह कोई पहला विवादित बयान नहीं है।

थोड़े ही दिन पहले राजद के ही एक दूसरे बड़े नेता, जगदानंद सिंह ने बयान दिया था कि रामजन्मभूमि मंदिर तो नफरत की जमीन पर बन रहा है। उनके बयान के पीछे कारण ये माना जा सकता है कि उनके सुपुत्र सुधाकर सिंह जो हाल तक बिहार की सरकार में राजद की ओर से कृषि मंत्री थे, उन्होंने विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर कई बयान दिए थे। उनका मंत्रिपद तो जाता रहा, लेकिन राजद पर भ्रष्टाचार के पुराने आरोप फिर से आ गए। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए पुराने समय में राजद की सरकार में जल संसाधन मंत्री रह चुके जगदानंद सिंह ने राम नाम का आश्रय लिया। इससे जो नया विवाद छिड़ा, उसके क्रम में लोगों का ध्यान राजद और भ्रष्टाचार के चोली-दामन के संबंध से हट गया।

आगे समस्या ये थी कि राजद की ओर से सरकार में शामिल उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार बनने से पहले बयान दिया था कि नई सरकार पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरियां देने का काम करेगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं जारी थीं, उनके विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर पुलिस की लाठियां जमकर बरसीं। इस पर जब सत्तापक्ष से पत्रकारों ने सवाल किया तो जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने कहा कि कौन सा ये पहली बार हुआ है? पहले भी प्रदर्शन करने पर पुलिस की मार पड़ती रही है। चूंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला था और बिहार में शिक्षक पहले भी कभी अनियमित वेतन तो कभी संविदा के बदले स्थायी बहाली की मांग करते रहे हैं इसलिए जनता का ध्यान शिक्षा से हटाना आवश्यक था।

फिलहाल बिहार में शिक्षा की दशा, अथवा दुर्दशा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा में स्थिति ये है कि बिहार में अभी 15 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, मगर इनमें से 5 भी ऐसे नहीं हैं जो 3 वर्षों में स्नातक का पाठ्यक्रम पूरा करवाकर डिग्री देने में समर्थ हों। विद्यालय के स्तर पर प्रमोट करके पुराने समय के प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय और मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय अवश्य बना दिया गया है। इन प्रमोट किए गए विद्यालयों में स्थिति ये है कि शिक्षकों की भर्ती तो हुई नहीं इसलिए राम भरोसे ही पढ़ाई चल रही है। ड्राप-आउट रेट यानि पढ़ाई छोड़ने की दर देश की सबसे ऊंचे दरों में से है। लड़कियों को साइकिल और पोशाक देने के दावों के बाद भी बिहार में स्कूल छोड़ने की दर 20 प्रतिशत से ऊपर ही है। ऐसे में शिक्षा मंत्री भला शिक्षा पर क्या कहते? जिस राम भरोसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, उसी राम की शरण ले ली!

चूंकि रामचरितमानस को बिना पढ़े उस पर अशोभनीय टिप्पणी करते समय वो शिक्षा मंत्री के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित थे, इसलिए इसे उनका निजी विचार कहकर टरकाया भी नहीं जा सकता। बिहार की लुंज-पुंज स्थिति वाली भाजपा रामजन्मभूमि मंदिर और रामचरितमानस पर हो रही अशोभनीय टिप्पणियों का उतना मुखर विरोध नहीं कर पा रही है। इसके बाद भी आम लोगों में जो इन बयानों को लेकर क्षोभ है, वो अब राजद स्वयं ही महसूस कर रही है। इसका एक बड़ा कारण राजद का वो जातीय समीकरण है, जिसे साधकर वो सत्ता में आने के इच्छुक होते हैं। यादव वोट बैंक पर निर्भर राजद के लिए नित्य रामचरितमानस का पाठ करने वाले यादवों के बीच जाना मुश्किल हो गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि राजद के दूसरे नेता अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयानों से पल्ला झाड़ रहे हैं और उनका वोट बैंक अपना दबाव फिर भी कम नहीं कर रहा।

● **विनोद बक्सरी**

राजद में पद और नेतृत्व को लेकर भी संघर्ष जारी

लालू यादव के नेपथ्य में जाने से कमजोर पड़ी राजद में पद और नेतृत्व को लेकर भी संघर्ष जारी है। ये संभव है कि जैसा दूसरे राज्यों में ऐसी परिवार आधारित पार्टियों का हश्र हुआ, कुछ वैसा ही बिहार में भी देखने को मिले। अगर बिहार में राजद किसी तरह शिवसेना गति को प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से इसका फायदा बिहार भाजपा को होगा। दूसरी बड़ी पार्टी जदयू पहले ही कमजोर पड़ चुकी है और चुनावों का दौर (2024 का लोकसभा चुनाव और उसके तुरंत बाद विधानसभा) नजदीक आते ही सियासी मोहरे अपनी-अपनी चाल चलना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में राजद के कुछ नेताओं को लगता है कि राम निंदा वाली नब्बे के दशक की सुनहरी राजनीति अभी भी सफल हो सकती है इसलिए अपनी निजी चुनौतियों को कम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से राजद के भीतर से ऐसे बयानों को समर्थन नहीं मिला उससे संकेत साफ है कि राम नाम से नफरत करने वाली राजनीति के दिन अब लद चुके हैं।

सहानुभूति का पात्र नहीं पाकिस्तान

पुरानी सरकार से अलग है मोदी सरकार का रवैया

यूं तो भारत हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र है, मगर वह सदियों से दुश्मन के जाल में फंसता आया है। यही हिंदुओं की एक बड़ी कमजोरी रही है। भारत को दुश्मन के जाल में फंसने से बचना चाहिए। उसे पाकिस्तान द्वारा दिए जख्मों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। न ही यह भूलना चाहिए कि आर्थिक रूप से डूबने के बावजूद पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के लिहाज से एक बुरी बात यह भी है कि अभी भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। इस सरकार का रवैया पूर्व की कांग्रेस और गठबंधन सरकारों से अलग है, जिनमें उस बिगड़ैल पड़ोसी देश के प्रति सख्त फैसले लेने का साहस नहीं था जो मित्रता के योग्य ही नहीं है। इसी कारण मोदी सरकार ने दो-टूक कह दिया कि वार्ता और आतंकवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। स्पष्ट है कि पाकिस्तान को अब मोदी के नेतृत्व वाले नए भारत के साथ ताल बैठानी होगी, जहां अनावश्यक सहानुभूति का कोई भाव नहीं है।

पाकिस्तान बड़ी लुंज-पुंज अवस्था में है। उसकी अर्थव्यवस्था रसातल में है। महंगाई आसमान पर है। खाने-पीने के सामान से लेकर पेट्रोल-डीजल की भारी किल्लत हो गई है। आम जनजीवन बुरी तरह त्रस्त है। तिस पर जिस मुजाहिद्दीन को पाकिस्तान ने इतने वर्षों तक पाला-पोसा, वही उसे निगलने पर आमादा है। कुछ ही देशों ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से स्वयं को आत्मघात की राह पर इस तरह आगे बढ़ाया होगा, जैसा पाकिस्तान ने 1947 के बाद से किया। भारत के प्रति नफरत एवं ईर्ष्या के साथ ही असहिष्णुता की भावना में कमी और मानवीय मूल्यों का अभाव इसकी मुख्य वजह रहीं। फिलहाल अपनी जनता के दुख-दर्द से भी पाकिस्तानी नेताओं के दिल नहीं पसीज रहे। इस माहौल में भी वे अपना आपा खोकर झूठे दिलासे देने में लगे हैं। यही कारण है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति-सद्भाव का सुर तो छेड़ा, लेकिन बाद में अपने बयान से पलटी मार गए, ताकि जनता को साध सकें।

पहले तो उन्होंने कहा था कि तीन बार भारत से युद्ध करके पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है और अब वे भारत के साथ शांति चाहता है। बाद में उन्होंने परमाणु ताकत की वही पुरानी घुड़की दे डाली। गंभीर आर्थिक संकट में फंसा होने के बावजूद पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर की आजादी की हास्यास्पद बातें कर रहा है। 5 फरवरी को पाकिस्तानी नेताओं ने न केवल कश्मीर एकजुटता दिवस का आयोजन किया, बल्कि नेशनल असेंबली से कश्मीर की आजादी का संकल्प भी पारित कराया। क्या आपने दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे किसी देश का ऐसा शुतुरमुर्गी रवैया और बड़बोलापन देखा-सुना है? पाकिस्तानी डीप स्टेट ने आरंभ से ही आतंकी तत्वों को खाद-पानी देने का काम किया। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और राजनीतिक बिरादरी ने आतंकी गतिविधियों के लिए हरसंभव संसाधन उपलब्ध कराए। वे भारत को छद्म युद्ध के जरिए घाव देकर उसे झुकाने की उम्मीद पाले हुए थे। कालांतर में इन आतंकी समूहों ने अपने ही देश में हिंदुओं और भारतीय धरा पर जन्मे अन्य धर्मावलंबियों के अलावा शिया मुस्लिमों और सूफियों जैसे आंतरिक दुश्मनों को मारने का अभियान भी छेड़ दिया। तहरीक-ए-तालिबान के उभार से पाकिस्तान को खुद आतंक का कोप झेलना पड़ा। यानी पाकिस्तान ने इतने समय से जिस राक्षस को पाला-पोसा, वही उसे निशाना बनाने लगा है, जो फौजियों-पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्श रहा।

पाकिस्तान में आतंक के आकाओं को इसका पहला अनुभव 2014 में पेशावर के उस हमले में हुआ, जिसमें 130 छात्रों और अध्यापकों का कत्ल कर दिया गया था। हालांकि हाल में जो हुआ उसके बारे में सेना और आईएसआई ने सोचा भी नहीं होगा। एक आत्मघाती हमलावर ने उच्च सुरक्षा वाले पुलिसिया घेरे को धता बताकर एक शिया मस्जिद में धमाका कर दिया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए जबकि 220 घायल हुए। अधिकांश मृतक पुलिस कर्मी थे। अब पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्ला ने स्वीकार किया कि मुजाहिद्दीन का गठन एक भारी भूल थी और समय आ गया है कि अब आतंक के विरूद्ध एकजुट कार्रवाई की जाए।

आतंक के साथ पाकिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। कश्मीर घाटी पर कब्जे के लिए उसने 75 साल पहले घुसपैठियों का सहारा लिया था। फिर 1965 में भारत के विरूद्ध युद्ध छेड़ा। इसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) की जनता ने जब पाकिस्तानी शासन व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह किया तब पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले बोल दिए। इसके बाद 1999 में कारगिल संघर्ष हुआ। इन सभी अवसरों पर भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस एवं अनुकरणीय शौर्य से पाकिस्तान को बुरी तरह पटखनी दी, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। तब तो हद ही हो गई जब उसने भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक संसद भवन पर आतंकी हमला करा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेन में 2006 के धमाकों में 200 से अधिक लोग मारे गए। मुंबई ने ही नवंबर 2008 में वह दुर्दांत आतंकी हमला झेला, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।

पाकिस्तान के ऐसे आतंकी इतिहास को देखते हुए उसे विश्व में सबसे विश्वासघाती देश के रूप में याद किया जाएगा। इस कारण वह किसी भी प्रकार की दया या सहायता का पात्र नहीं। भारत की जनता न तो उसे माफ करे और न ही उसे उसकी करतूतें भुलानी चाहिए। मौजूदा मुश्किल से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से गुहार लगा रहा है। आईएमएफ ने कड़ी शर्तें रखी हैं। जैसे उसने सरकार से बिजली दरें बढ़ाने को कहा है। पेट्रोल की दरें बढ़ाने का भी दबाव है जो पहले ही करीब 250 रुपए प्रति लीटर के आसपास हैं। इससे आम जनता की कमर और टूट जाएगी जो पहले ही 50 प्रतिशत के स्तर पर पहुंची महंगाई की दर से परेशान है। आईएमएफ ने यह शर्त भी रखी है कि उसके राहत पैकेज की रकम का इस्तेमाल पाकिस्तान कर्ज अदायगी में नहीं कर सकता। हमें भी पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

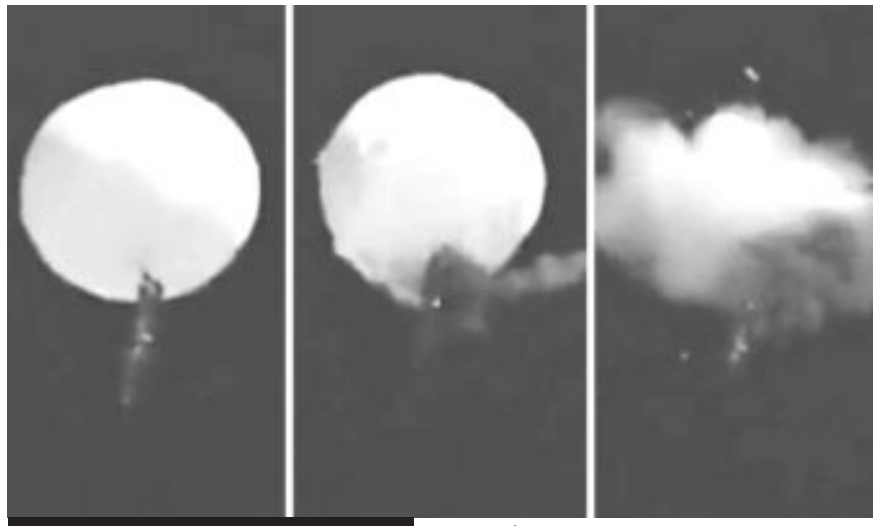

रहस्यमयी गुब्बारे

अमेरिका ने दावा किया है कि चीन कई देशों की जासूसी कर रहा है। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन ने भारत और जापान सहित कई देशों में जासूसी गुब्बारों के एक बेड़े को संचालित किया है। चीनी गुब्बारों का यह मामला तब गर्म हुआ, जब अमेरिका और भारत में ये गुब्बारे देखे गए। अमेरिका ने एक हफ्ते में चार चीनी गुब्बारे को निशाना बनाकर नष्ट कर दिए हैं। चीन का कहना है कि ये गुब्बारे मौसम की जानकारी लेने से जुड़े हैं, लेकिन भारत सहित कई देश मान रहे हैं कि इनका मकसद जासूसी रहा है। अमेरिका के अधिकारियों ने बाकायदा अपने मित्र देशों और सहयोगियों को चीनी गुब्बारों को लेकर अवगत कराया है। इनमें भारत भी शामिल है। उसने कुल जमा 40 दूतावासों के अधिकारियों को इस बारे में बताया है। इससे मामले की गंभीरता का अहसास होता है। यह सही है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते हाल में काफी खराब हुए हैं। लेकिन यह भी सही है कि चीन के इरादों पर गहरी शंका पैदा हो रही है, क्योंकि जिन इलाकों में इन चीनी गुब्बारों को देखा गया है, वह संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं। दिलचस्प यह भी है कि ये गुब्बारे साधारण गुब्बारे नहीं हैं। यह खासे बजनी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में मार गिराए गए चीनी गुब्बारों का वजन हजारों किलो था और पकड़े जाने पर उनमें खुद को नष्ट कर देने के लिए विस्फोटक बंधा था।

विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि ये जासूसी गुब्बारे हैं। चीन के संदिग्ध गुब्बारे को फरवरी के पहले हफ्ते अमेरिका ने अटलांटिक महासागर के ऊपर साउथ कैरोलिना के तट पर एक लड़ाकू विमान द्वारा नष्ट कर दिया था। अमेरिकी अखबार 'द वाशिंगटन पोस्ट' की एक रिपोर्ट, जो अनाम रक्षा और खुफिया अधिकारियों से बातचीत पर आधारित है में दावा किया गया है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) वायुसेना से संचालित इन जासूसी गुब्बारों (जो वास्तव में निगरानी यान हो सकते हैं) को पांच महाद्वीपों में देखा गया है। अखबार ने एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के हवाले से कहा कि ये गुब्बारे पीआरसी के निगरानी बेड़े का हिस्सा हैं। इन्हें निगरानी अभियान चलाने के लिए तैयार किया गया है। इस अधिकारी का कहना है कि चीन ये गुब्बारे भेजकर अन्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। हाल के वर्षों में अमेरिका के हवाई, फ्लोरिडा, टेक्सास और गुआम में चार गुब्बारे देखे जाने की बात कही थी। पेंटागन ने तस्वीरें जारी कर दावा किया था कि फरवरी में देखे गए चीनी गुब्बारों के अलावा बाकी तीन चीनी गुब्बारे डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान देखे गए थे। बात सच निकली।

अमेरिका ही नहीं भारत पर भी चीनी जासूसी गुब्बारों की नजर है। अमेरिका के मोंटाना में जो जासूसी गुब्बारा मार गिराया गया, उसके बाद कुछ हैरान करने वाली जानकारियां सामने आईं। मसलन, यह गुब्बारा अंडमान निकोबार से होकर गुजरा था। जब यह जानकारी सामने आई, तो रक्षा विशेषज्ञ परेशान हो गए। अंडमान निकोबार भारत के लिहाज से हिंद महासागर में रक्षा के लिए अहम रणनीतिक भूमिका निभाता है। वहां भारत की तीनों सेनाओं की मौजूदगी है। निश्चित ही यह माना जा रहा है कि चीन भारत की सेना की जासूसी भी कर रहा है। बहुतों को जानकारी नहीं होगी कि अंडमान निकोबार कमांड इकलौती कमान है, जहां भारत की तीनों सेनाएं मौजूद हैं। अंडमान भारत की दृष्टि से बहुत अहम द्वीप और मार्ग है, जहां से भारत का ज्यादातर व्यापार होता है। चीन इस रास्ते को रोकने का षड्यंत्र करता रहा है, इसके बावजूद भारत ने कभी इस रास्ते से व्यापार बंद नहीं किया। भारत ने तीनों सेनाओं की एकीकृत कमान की शुरुआत साल 2001 में की थी। इसका मकसद दक्षिण एशिया में भारत की रणनीतिक जरूरतों को ताकत देना था। हाल के महीनों में देखा गया है कि चीन की नौसेना लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को काफी सक्रिय बनाए हुए है। वहां कई बार चीनी पनडुब्बियां दिखी हैं। जिस तरह चीन हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है उसे देखते हुए भारत ने इसे काउंटर करने के लिए मैरीटाइम सर्विलांस और क्षमताओं को बढ़ाया है।

अब चूंकि अमेरिका में देखे गए चीन के जासूसी गुब्बारे को पहले अंडमान निकोबार में देखा गया था, यह साफ हो गया है कि चीन कुछ शरारत कर रहा है। इस गुब्बारे का आकर इतना बड़ा था कि पोर्ट ब्लेयर में 6 जनवरी को आम लोगों तक ने इसे ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा था। इससे कुछ महीने पहले की बात करें, तो दिसंबर 2021 में अंडमान निकोबार कमांड ने तीनों सेनाओं वाला बड़ा युद्धाभ्यास किया था। निश्चित ही चीन इस इलाके में भारतीय कमांड की गतिविधियों की टोह लेना चाहता होगा। भारतीय सेनाओं की अंडमान में तैनाती से निश्चित ही चीन में बेचैनी रही है।

● **कुमार विनोद**

कई देशों में चीन भेज चुका है गुब्बारे

अमेरिकी के एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि चीन का यह जासूसी गुब्बारा, दक्षिण एशिया में भी दिखा है। उनके मुताबिक, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हाल के वर्षों में ऐसे गुब्बारे भेज चुकी है और यह कई देशों, जिनमें पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप के पांच महाद्वीपों के देश शामिल हैं, में दिखे हैं। चीनी गुब्बारों को लेकर अमेरिका काफी सक्रिय है। अमेरिका ने एफ-22 जेट फाइटर उसके पीछे लगाकर न केवल चीनी गुब्बारे को मार गिराया, बल्कि मित्र देशों को इसे लेकर एकजुट किया है। भले अमेरिका की कार्रवाई से चीन गुस्से में हो, अमेरिका को इसकी परवाह नहीं है। अमेरिका ड्रैगन की लगातार पोल खोल रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि वो चीनी जासूसी गुब्बारा था और 200 फुट ऊंचा था। जाहिर है यह गुब्बारा नाम का ही था और वास्तव में एक बड़े यात्री विमान के बराबर वजन का पेलोड ले जा रहा था। इसे लेकर विशेषज्ञों का मत है कि इस गुब्बारे में विस्फोटक भी थे, ताकि पकड़े जाने पर उसे नष्ट किया जा सके। अमेरिका नौसेना इसकी जांच कर रही है। पहले गुब्बारे के मलबे की जांच की गई है और उसमें क्या उपकरण थे, इसे लेकर भी कुछ जानकारियां पेंटागन के सामने आई हैं।

आदर्श प्रस्तुत करती हैं सिंगल मदर

मां शब्द किसी लाचारी का नहीं वरन् नारी के जीवन की गुणगाथा का सजीव चित्रण है। मां सर्वसमर्थ होती है फिर चाहे वो अकेली हो या पति के साथ, गरीब हो या अमीर। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कवि मैथिलीशरण गुप्त की इन पंक्तियों से मुक्त होकर आज नारी ने हर क्षेत्र में अपने कदम रखकर ये साबित कर दिया है कि सबला जीवन आज तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध, इरादों की ठानी। जीवन की कंटीली पगडंडियों पर अपने रास्ते बनाती नारी कभी किसी समस्या से घबराती नहीं है। इरादे मजबूत कर ले तो पीछे हटती नहीं है। लाख संकट सामने हों फिर भी कभी लड़खड़ाती नहीं है।

बीते दौर में समाज में उपेक्षित भाव से देखी जाने वाली नारी चारदीवारी में कैद होकर सबकी चाकरी करने वाली समझी जाती थी। मां-बहू के रूप में कठिन परीक्षाओं से गुजरती हर कदम पर तानों, व्यंग्य बाणों और अत्याचारों को सहन करती थी। ससुराल की चौखट पर दम तोड़ना ही उसकी नियति थी। विवाह पश्चात विदा होते हुए यही शिक्षा लेकर जाती थी कि डोली में जा रही हो अर्थी में ही लौटना। इन्हीं जंजीरों में बंधी नारी अपने लिए कोई निर्णय ले ही नहीं पाती थी। पति के द्वारा त्याग देने पर तो और भी असहाय हो जाती थी। हर जगह पति के नाम से उसकी पहचान थी। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की राय की कोई कीमत नहीं थी। अपनी अभिलाषाओं का गला घोंटना उसे बखूबी आता था। बेटी होने के कारण माता-पिता के यहां भी उपेक्षित ही रहती थी क्योंकि पराया मानकर उसका लालन-पालन होता था। शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव होने से विवाह के बाद की परेशानियों से जूझना उसके लिए असंभव था। पति से संबंध विच्छेद होकर रहना या उसकी मृत्यु पश्चात् जीवन जीने की कल्पना से भी आशंकित हो जाती थी। अकेले संतान पालना तो वह सोच भी नहीं सकती थी। पति के बिना नारी समाज का कटा अंग बनकर रह जाती थी। समय ने करवट बदली और नारी ने अपने को संवारा। अपने अस्तित्व को पहचाना। अपने इरादों को मजबूत किया और समाज में अपनी भूमिका से सबको हतप्रभ कर दिया।

आज नारी बदलती विचारधारा की मजबूत चट्टान है। उसे समाज का, परिवार का, किसी के व्यंग्य बाणों का कोई भय नहीं है। उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। वह परेशानी आने पर पति के और परिवार के बिना जीना सीख गई है। आज मोह के बंधन से, घर की घुटन से आजाद होकर वह अपना और अपने बच्चे का भविष्य संवार रही है। उसका आत्मबल उसे हर राह पर आगे ले जाता है। कभी कमजोर पड़ती भी है तो अपनी संतान का मुंह देखकर संभल जाती है। सिंगल मदर होना अभिशाप नहीं है। पर जब जीवन पर गाज गिरती है तो संभलने में वक्त लगता है। सहज नहीं होता अकेले जीवन व्यतीत करना। कष्टों से हार ना मानकर नारी ने निभाना ही सीखा है पर कई बार विपत्ति के अलावा भी अलगाव की स्थिति आ जाती है। विचारों के मेल ना होने से स्वेच्छा से भी दंपत्ति अलग हो जाते हैं। अलग होकर जीना चुनौती बन जाता है। समाज में जब पिता का नाम ही सर्वमान्य होता था तब अकेली नारी को संघर्ष करना पड़ता था। पिता का नाम कागजों में नहीं होने से बच्चों को और मां को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था। दिल्ली की गीता देवी का बाल विवाह हुआ था। अपने बच्चे के वजीफे के लिए जब पिता के नाम की जरूरत पड़ी तो उनके बच्चे को वजीफा नहीं मिला। सिंगल मदर ने तीन वर्षों तक लंबी लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका अधिकार मिला। उनके प्रयत्नों से उनके बच्चे को वजीफा मिला उसकी शिक्षा पर वो अकेली ध्यान दे रहीं हैं। ऐसे कितनी ही मां हैं जो बाल विवाह की यंत्रणाएं झेल रही हैं या जो कमजोर हैं। जब उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है तो वे संघर्ष करती हैं। अपनी संतान की खातिर कोई मजदूरी कर रही है, कोई रिक्शा चला रही है। पढ़ी-लिखी महिलाएं भी अकेली रहकर संतान का भविष्य बना रही हैं। संतान की परवरिश करने के लिए आज नारी को पति के सहारे और नाम की जरूरत नहीं है। अपने नाम के संरक्षण में अपनी संतान का जीवन बुनती है, सजाती है, संवारती है। वह अकेली है पर अपनी संतान के लिए पिता का फर्ज निभाती है।

माता-पिता का भी दृष्टिकोण बदला है। बेटी को गर्व से पालते हैं। शिक्षा देते हैं और विवाह के बाद भी परछाई बनकर उसके साथ रहते हैं। सिंगल मदर होने पर हर कदम उसका साया बनते हैं। समाज से मुंह नहीं छिपाते हैं। अकेली बेटी जीवन यापन करने में समर्थ है। उसका संबल बनते हैं। रूही की जिंदगी अंधेरे में डूब गई जब उसे शराबी पति के साथ रहना पड़ा। उसके अत्याचारों को सहना पड़ा। मरने का विचार भी आया पर अपने अंदर पनप रहे नन्हे जीव की जान बचाने के लिए नारकीय जीवन से दूर रहकर जिंदगी काटने की सोची। शुरू में परेशानी हुई। झिझक भी हुई फिर बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए पति को छोड़ दिया।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

जीवन को सरल बनाने का रहस्य

हिंदू धर्म में श्रीमद्भगवत गीता को बहुत ही पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जो भी इसका श्रवण या पाठन करता है उसे जीवन के कई रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। भगवत गीता में ना केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है, बल्कि धर्म, जय, पराजय, व्यवहार इन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। भगवान श्रीकृष्ण ने जिस तरह महाभारत के युद्ध भूमि में धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था। उसी तरह वर्तमान समय में गीता अनेकों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन को बिना किसी अड़चनों के कैसे जिया जाता है। आइए गीता ज्ञान के इस भाग में जानते हैं कि श्रद्धा किसे कहते हैं और जीवन कैसे बनाया जा सकता है सरल।

भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन और धर्म के विषय में कहा है कि

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।।

इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात् एक समान रहता है। ना सौभाग्य में प्रसन्न होता है और ना ही किसी विवाद या क्लेश में निराश होता है। उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है।

इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। जो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है। फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है। वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोध का साथ देता है। ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं।

येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्।।

इस श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन! जो भक्त दूसरे या अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, वह भी मेरा ही पूजन कर रहा है। लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। इस श्लोक में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि व्यक्ति विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करता है। जिस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी-देवताओं की पूजा करता है। लेकिन वह श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। इस पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है।

धार्मिक ग्रंथों ने सदियों से ही मानवता को सही दिशा और जीवनशैली सिखाई है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसी आदर्शों पर आगे बढ़ते हैं, ये आदर्श हमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हीं आदर्शों का पालन करते आए हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद्भगवतगीता को सबसे पवित्र माना गया है। यह सबसे रहस्यमयी ग्रंथ हैं। गीता मुश्किलों में राह दिखाती है, उलझनों को सुलझाने का तरीका बताती है, जिंदगी और मृत्यु का सत्य सुनाती है। इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है, जीवन जीने का तरीका बताया गया हैं। आज-कल, जन्म-मृत्यु, धन-संपदा, प्रकृति, जलवायु, आदि-अंत, परमात्मा सभी का पूर्ण वर्णन है। यह बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही रहस्यमयी पुस्तक है।

अगर श्रीमद्भगवत गीता का अध्ययन नित्य किया जाए तो इस बात का आभास होता है कि उसमें सिखाया कुछ नहीं गया है, बल्कि समझाया गया है कि इस संसार का स्वरूप क्या है? उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि आप इस तरह चलें या फिर उस तरह चलें, बल्कि यह बताया गया है कि किस तरह की चाल से आप किस तरह की छवि बनाएंगे? उसे पढ़कर आदमी कोई नया भाव नहीं सीखता बल्कि संपूर्ण जीवन सहजता से व्यतीत करें, इसका मार्ग बताया गया है। ये स्वयं परमपिता परमेश्वर के मुखकमल से प्रकट हुई है, भगवान ने स्वयं सारें रहस्य का वर्णन स्वयं किया है। सभी मनुष्यों को समय गंवाए बिना श्रीमद्भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, आपको कोई और गुरू बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि श्रीमद्भगवत गीता ही आपकी गुरू हैं।

गीता में कहा गया है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है जिससे बुद्धि व्यग्र हो जाती है। भ्रमित मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है। तब सारे तर्कों का नाश हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि आत्ममंथन करके स्वयं को पहचानो क्योंकि जब स्वयं को पहचानोगे तभी क्षमता का आंकलन कर पाओगे। ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को काटकर अलग कर देना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी क्षमता का आंकलन कर लेता है तभी उसका उद्धार हो पाता है।

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है, किंतु केवल यह शरीर नश्वर है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती और पानी गीला नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक वस्त्र बदलकर दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं उसी प्रकार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे जीव में प्रवेश करती है।

● **ओम**

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

महिला एथलीटों की व्यथा

बीते दिनों घर की दहलीज से बाहर निकलकर अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप जीतकर महिला खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया है। अपने कंधे पर तिरंगा रखकर जब वह क्रिकेट स्टेडियम के चक्कर काट रही थीं, तब न उन्होंने केवल अपना जज्बा दिखाया बल्कि उस समाज के खिलाफ अपना हौंसला भी बुलंद किया जिसने उनके रास्ते में कभी गरीबी, तो कभी कुंठित ख्यालों का रोड़ा डाला। कुछ कर दिखाने का जज्बा इनके हौंसले को कुंद नहीं कर पाया। वह खेलीं और बेहतरीन खेलते हुए दुनिया भर में छा गईं।

महिला क्रिकेटरों के हक में कई चीजें बदल रही हैं जो जेंडर संवेदनशीलता के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। बीते दिनों विमेंस क्रिकेट के हक में पुरुष क्रिकेटरों के बराबर मैच फीस का फैसला, विमेंस टी-20 आईपीएल के फैसले के बाद, विमेंस क्रिकेट अंदर-19 टी20 वर्ल्ड कप जीतना एक बड़ी उपलब्धि है, साथ ही साथ ऐतिहासिक घटना भी है। राज्य स्तर पर क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी और कई खेलों के माध्यम से गांव-कस्बों और छोटे शहरों में खेलों के माध्यम से पुरुषवादी मानसिकता को तोड़ने का काम हो रहा है और समाज को जेंडर संवेदनशील बनाने का प्रयास हो रहा है। जो बेशक देख के कई महिला एथलीटों के लिए नए दरवाजे खोलेगा। फिर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ मुख्यधारा का मीडिया परायेपन का व्यवहार क्यों कर रहा है? क्या यह विमेंस एथलीट की तमाम उपलब्धियों पर पानी फेरने जैसा नहीं है। जाहिर है विमेंस एथलीट आगे बढ़ रही हैं पर मुख्यधारा का मीडिया उनकी उपलब्धियों का जश्न तो मना रहा है किंतु अपनी पुरुषवादी मानसिकता में पिछड़ रहा है।

किक्रेट मैच खेलने के दौरान या अन्य किसी भी खेल के मैदान पर तो वह सिर्फ एक एथलीट होती हैं। कामयाबी का परचम लहराने के बाद समाचार की दुनिया में देश की बेटी-बहन बनने के साथ-साथ प्रेरणा बन गई। नहीं बन सकी तो बस विमेन एथलीट, जिसके लिए मेहनत की, खून जलाया-पसीना बहाया और अपने खेल में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। क्या यह अजीब नहीं है, जिस खेल क्रिकेट ने समय के साथ लैंगिग भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शब्दों से पहरेज कर लिया। जहां मैन ऑफ द मैच या सीरीज या बैट्समैन अब प्लेयर ऑफ द मैच और बैटर हो गया, उस खेल का समाचार लिखने में हम जेंडर संवेदनशील नहीं हो पा रहे हैं।

हम महिला क्रिकेट खिलाड़ियों से उसके बेहतरीन एथलीट होने का हक लगातार छीन रहे हैं। किसी भाई की बहन और किसी पिता की बेटी तो वो है ही फिर देश की बहन-बेटी बनाने की मानसिकता क्यों है? पुरुष खिलाड़ियों की कामयाबी पर तो हम नहीं कहते देश के भाई-बेटों ने कामयाबी का परचम दुनिया में लहरा दिया। उनके लिए मुलतान का सुल्तान, नेशन हीरो और नए-नए विशेषण। परंतु, महिला खिलाड़ियों के साथ शब्दों या विशेषणों का अभाव क्यों?

विमेन एथलीटों को बेटी-बहन बोलकर उनके बेहरीन प्रर्दशन के बारीक बातों को तो कोई स्पेस ही नहीं मिलता। उनकी खेल क्षमता का मूल्यांकन करते हुए एथलीट क्षमता और उनकी निपुणता पर ध्यान केंद्रित करना तो दूर की कौड़ी लाने के बराबर है। न ही उनके सफलता के खबर लिखते समय उनके बनाए गए रिकार्ड या पहले के उपलब्धियों पर कोई बात दिखती है। अगर कैरियर के एक पड़ाव पर है तो शादी कब कर रही है और अगर गर्भवती है तो उनका कैरियर खत्म।

विमेन एथलीटों के कपड़े तो हमेशा से ही पुरुषवादी मीडिया के निशाने पर रहते हैं। शायद ही कोई महिला एथलीट हो जिसकी सुंदरता उनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनी हो। उनके चेहरे-मोहरे और रंग को प्राथमिकता देने के चक्कर में उनकी खेल प्रतिभा को पीछे ढ़केल दिया जाता है। समाज में महिला सौंदर्य को लेकर गढ़ी गई परिभाषाएं हमेशा उनकी खेल प्रतिभा के सामने बाधा बन जाती है। बीते दिनों द गार्जियन अखबार ने स्पोर्ट इंग्लैड की रिपोर्ट के आधार पर लिखा कि कुछ महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण में 75 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि वे खेलों में भाग लेना चाहती थीं लेकिन समाज और मीडिया द्वारा उनके रूप रंग और शारीरिक गठन के कारण उनके बारे में राय न बना ले, इस डर से उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए। पहले तो यह मानने को तैयार न थे कि कोई भी खेल महिलाओं के लिए भी है। महिला एथलीटों ने यह साबित किया कि कोई भी खेल लड़के-लड़कियों का नहीं स्टेमिना का होता है। फिर कहने लगे, चूल्हा-चौका करने वाली छोरियां देश के लिए कैसे खेलेंगी? छोरियों ने मेडल अपने नाम किए तो कहने लगे, मारी छोरियां, छोरों से कम है के। फिर कहा, इतने छोटे-छोटे कपड़े पहनकर टांगे दिखाना सही तो नहीं है? महिला एथलीटों ने अपने खेल पर ध्यान दिया, कपड़ों पर नहीं और कामयाब होती चली गईं।

● **आशीष नेमा**

पाक्षिक पत्रिका अक्स के स्वामित्व एवं अन्य विषयों संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन	:	भोपाल
प्रकाशन अवधि	:	पाक्षिक
मुद्रक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रकाशक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
संपादक का नाम	:	राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	:	भारतीय
पता	:	150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा	:	राजेन्द्र आगाल 150 जोन-1, प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल

जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।

मैं राजेन्द्र आगाल एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 01.03.2023 **राजेन्द्र आगाल**

हस्ताक्षर

नीलम को पहली शादी में मिला था धोखा, खूबसूरती ऐसी की गोविंदा भी हो गए फिदा

90 के दशक में नीलम कोठारी मेकर्स की पहली पसंद हुआ करती थीं। अपने एक्टिंग कैरियर में एक्ट्रेस ने गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ स्क्रिन शेयर किया था। लेकिन वह शुरुआत से ही एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं। एक्टिंग में आना तो बस किस्मत की बात थी। मुंबई वह अपनी दादी से मिलने आई थीं। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। हॉन्गकॉन्ग में जन्मीं नीलम की दादी के पास वाले अपार्टमेंट में ही फिल्म निर्देशक रमेश बहल भी रहा करते थे। उनकी बेटी और नीलम की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। ये उस दौरान की बात जब रमेश बहल अपनी फिल्म जवानी के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्होंने नीलम को देखते ही सोच लिया था कि उन्हें कास्ट करना है और एक्टिंग करने का ऑफर एक्ट्रेस को दे दिया था। साल 1984 में आई इस फिल्म में नीलम और गोविंदा साथ नजर आए थे। इसके बाद वह गोविंदा के साथ फिल्म इल्जाम और खुदगर्ज में भी नजर आईं।

गोविंदा संग हुए थे प्यार के चर्चे

गोविंदा और नीलम ने तकरीबन 10 फिल्मों में साथ काम किया। दोनों के अफेयर की भी खूब चर्चा होती थी। गोविंदा उस समय नीलम को लेकर काफी सीरियस थे। वह तो एक्ट्रेस संग शादी भी करना चाहते थे। नीलम का नाम बॉबी देओल संग भी जोड़ा गया था। खबरों की मानें तो नीलम बॉबी से शादी करना चाहती थीं लेकिन धर्मेंद्र को रिश्ता पसंद नहीं था। इसके बाद उन्होंने बैंकॉक के बिजनेसमैन ऋषि सेठिया संग शादी रचा ली, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला महज 2 साल बाद दोनों अलग हो गए। फिर नीलम ने एक्टर समीर सोनी से साल 2008 में शादी कर ली। नीलम और समीर दोनों ही उस समय तलाकशुदा थे।

संजय दत्त नहीं, कोई और था खलनायक, मेकर्स की पसंद पर चमका संजू बाबा का सितारा

सुभाष घई की फिल्म खलनायक में संजय दत्त ने बल्लू नामक विलेन का रोल निभाया था। इस किरदार को आमिर खान भी निभाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन मेकर्स इन दोनों के अलावा किसी तीसरे हीरो को इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। लेकिन बाद में ये किरदार संजय दत्त को मिला। कौन था वो तीसरा एक्टर? इससे पहले सुभाष घई ने डर के दौरान आमिर खान से बात की थी, लेकिन तब आमिर विलेन का किरदार निभाना नहीं चाहते थे। इसलिए मेकर्स ने इस फिल्म में आमिर को नहीं लिया था। लेकिन संजय दत्त के बारे में भी नहीं सोचा गया था क्योंकि सुभाष घई इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नाना पाटेकर के साथ बनाना चाहते थे। इस बात का जिक्र सुभाष ने अपने कई इंटरव्यू में किया है कि पहले नाना पाटेकर बल्लू का किरदार निभाने वाले थे। लेकिन जैसे-जैसे फिल्म आगे बढ़ी तो स्क्रिप्ट की डिमांड पर किसी और को इस फिल्म में लेने की बात सामने आई। नाना पाटेकर जब फिल्म से बाहर हुए तो सुभाष घई ने संजय दत्त को फिल्म के लिए साइन कर लिया। बता दें कि बल्लू का किरदार संजय दत्त, आमिर खान, नाना पाटेकर ही नहीं पहले अनिल कपूर भी इस किरदार को निभाना चाहते थे।

अभिनेता डैनी की पहली गर्लफ्रेंड थीं परवीन बाबी, ब्रेकअप के बाद भी पहुंच जाती थीं उनके घर

बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बाबी ने 18 साल पहले अपनी अंतिम सांस ली थी, लेकिन वह आज भी अपनी फिल्में और जीवन को लेकर फैंस के दिलों में जिंदा हैं। परवीन बाबी एक प्रतिभाशाली स्टार होने के अलावा, अपनी निजी जीवन के मुद्दों के लिए भी चर्चा में रहीं। उन दिनों परवीन बाबी का नाम कुछ बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया। इन्हीं में से एक डैनी डेन्जोंगपा भी थे, जिनके साथ परवीन की नजदीकियों के हर तरफ चर्चे रहे। बॉलीवुड के फेमस विलेन कभी परवीन बाबी के साथ रिलेशनशिप में थे और उन्होंने खुलकर इस पर बात भी की थी। परवीन और डैनी जुहू गैंग का हिस्सा कहे जाते थे। इस गैंग में शेखर कपूर, प्रोतिमा बेदी, कबीर बेदी और परीक्षित साहनी भी शामिल थे। कभी एक-दूसरे के प्यार में डूबे परवीन और डैनी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक उनके बीच दूरियां बढ़ने लगीं। इसके बाद दोनों ने ब्रेकअप का फैसला कर लिया। एक इंटरव्यू में डैनी ने परवीन के बारे में बात की और बताया- मैं और परवीन सेम बिल्डिंग में रहते थे। मैं पहली मंजिल में और वो चौथी मंजिल में रहती थीं। वो मेरी पहली गर्लफ्रेंड थीं। हम दोनों यंग थे और चार साल तक साथ रहे। उन दिनों ये बड़ी बात थी। हमने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया।

दोषी कोई और है, मैं नहीं

इस असार संसार में एकमात्र निर्मल प्राणी यदि कोई है, तो वह मनुष्य ही हो सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए मनुष्य से अच्छा प्रमाण मिलना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए यदि आपसे कोई गलत, अनैतिक, अनुचित, असामाजिक, अवैध या देश, कानून और समाज की दृष्टि में गलत कार्य जाने या अनजाने में हो जाता है, तो बिना सोचे समझे आप यही कहेंगे कि यह मैंने नहीं फलां व्यक्ति ने अथवा किसी और ने किया है, मैंने नहीं किया। आप शत-प्रतिशत नकार जाएंगे कि उसे आपने ही अंजाम दिया है। किसी भी तरह आप अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे। स्वदोष स्वीकार न करने की यह कला, प्रवृत्ति या संस्कार मनुष्य मात्र में स्वभावगत है। आपके स्थान पर मैं या कोई अन्य व्यक्ति भी होगा तो वह भी वही करेगा, जो आपने किया है।

यदि मनुष्य स्व दोषों को सहजता से स्वीकार कर लेता तो आज के संसार की दशा और दिशा कुछ और ही होती। ये कचहरियां, दीवानियां, अदालतें, जज, अधिवक्ता, स्टाम्प वेंडर आदि कुछ भी न होते। हजारों-लाखों लोगों का व्यवसाय ही चौपट हो जाता। अदालतें अदालतें न होकर दंगल के मैदान हैं, जहां लड़ाई झूठ और झूठ के बीच नहीं, बल्कि सच और सच के बीच है। वादी अपने को सच कहता है, और प्रतिवादी अपनी सच्चाई का बिगुल बजाता है। फिर ये झूठ क्या वकील साहब के काले कोट की जेब में छिपा बैठा रहता है। यदि प्रतिवादी के खिलाफ मजबूत प्रमाण मिल गए और उन्होंने सही सिद्ध भी कर दिया तो प्रतिवादी पराजित हो जाता है। वह दोषी सिद्ध हो जाता है। यदि सहजता से उसके द्वारा अपना दोष स्वीकार कर लिया जाता तो कोर्ट कचहरी (जहां मुकदमा लड़ते-लड़ते कच का हरण हो जाए) का इतना सारा बखेड़ा क्यों खड़ा होता। पर इससे कुछ लोगों का रोजगार चलना भी तो जरूरी था, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए काले कोटों के बीच सफेदी की लड़ाई करनी आवश्यक हो गई।

इसके विपरीत स्थिति में विचार करके देखें तो स्पष्टत: यह तथ्य प्रत्यक्ष होता है कि मनुष्य बुरे और बुरे से भी बुरे कार्य करने का दायित्व दूसरों पर डालता है। किंतु यदि अच्छा कार्य करता है तो फोटो खिंचवाकर, वीडियो बनवाकर, अखबारों, टीवी और सोशल मीडिया पर प्रसारित करवाकर स्व श्रेय लूटने में पीछे नहीं रहता। मात्र स्वदोष का प्रक्षेपण ही दूसरों पर किया जाता है। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति की देन हैं ये समस्त प्रकार के कोर्ट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसका अर्थ यह भी हुआ कि कोर्ट अच्छे कार्य के लिए न होकर उसके दोषों को उजाकर करने और उसकी सचाई बाहर लाने के लिए ही बनाए गए हैं, किंतु क्या इन सबके बावजूद उसने गलत काम करना, अपराध करना अथवा झूठ से दूर रहना छोड़ा है? इस कार्य में कोई कमी न आकर और भी बढ़ोत्तरी हुई है। आदमी दिन प्रतिदिन किस दिशा में जा रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उसके निरंतर दिशा-विवर्तन के कारण ही उसकी दशा का सुरूप कुरूप होता जा रहा है।

अपने को खटाई में न डालकर दूसरों को खटाई में झोंक देने का स्वभाव मनुष्य की काइयांपन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। मैं सुरक्षित बचा रहूं, सब भाड़ में जाएं। यह सोच उस आदमी की है जो बहुत अधिक धार्मिक, पवित्र, उदार, मानवतावादी, आध्यात्मिक, परोपकारी, जनसेवी और करुणाशील होने के दंभ में चूर रहता है। लेकिन जब समय, कानून और न्याय का डंडा उसकी पूंछ उठाकर उसका नग्न यथार्थ जगजाहिर कर देता है, तो उसे अपना मुंह छिपाने के लिए भी सुरक्षित जगह की खोज करनी पड़ती है।

इस प्रकरण की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पढ़े-लिखों और बिना पढ़े लिखों में कुछ तो अंतर अवश्य होता ही है। साधारणत: जितने काइयांपन और चतुराई से पढ़ा-लिखा व्यक्ति स्वदोष पर आवरण डालने में कुशल होता है, उतनी कुशलता एक सीधा और सरल व्यक्ति नहीं दिखा पाता। पढ़-लिखकर स्वदोषों को छिपाने की कलाओं, युक्तियों, बुद्धि-चातुर्य, जुगाड़बाजी आदि की मात्रा में कई गुना वृद्धि हो जाती है। पढ़ा ही इसीलिए जाता है। पढ़ा-लिखा व्यक्ति कोरी स्लेट नहीं होता। पढ़-लिखकर भी यदि कोई कोरी स्लेट बना रह गया तो उसका पढ़ना-लिखना ही अकारथ! इसलिए स्वदोष प्रक्षालनार्थ पढ़ाई एक अनिवार्य कर्म है। स्वदोष प्रक्षालन का साबुन है पढ़ाई। वही दोष के मैल को रगड़-रगड़ कर साफ कर देती है। इसलिए मनुष्य को खूब पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वह अपने दोषों को दूसरों के सिर मढ़ने के संस्कार से इस मनुष्य यौनि में तो मुक्त हो नहीं सकता। सभी युगों में जो मनुष्य स्वदोषों को छिपाकर पर प्रक्षेपण में जितना प्रवीण होता है, वह उतना ही बड़ा नेता, अधिकारी, कर्मचारी, आम या खास नर-नारी बनकर उभरता है। जिनकी कार गुजरियों से टीवी, अखबार, सोशल मीडिया आबाद रहता है। यदि विश्वास न हो तो आज का ही अखबार उठाकर देख लीजिए, अथवा टीवी खोल लीजिए और ज्यादा दूर न जाना चाहें तो हाथ के मोबाइल की झांकियां देख लीजिए। वैसे भी इसमें बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं, ये संसार ही गुण-दोष मय है। 'जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत-हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार।।

अब आप और हम न तो संत हैं और न ही हंस हैं, जो वारि-विकार को छोड़कर केवल दुग्ध पान ही करें। अपने अनिवार्य दोषों को ढंक पाने की कला भी न सीख पाए तो मनुष्य होने का लाभ ही क्या? सबसे बुद्धिमान प्राणी होने का गौरव जो मिला हुआ है! जिसमें 'स्वदोष-छिपावन-कला' की प्रवीणता भी तो सम्मिलित है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

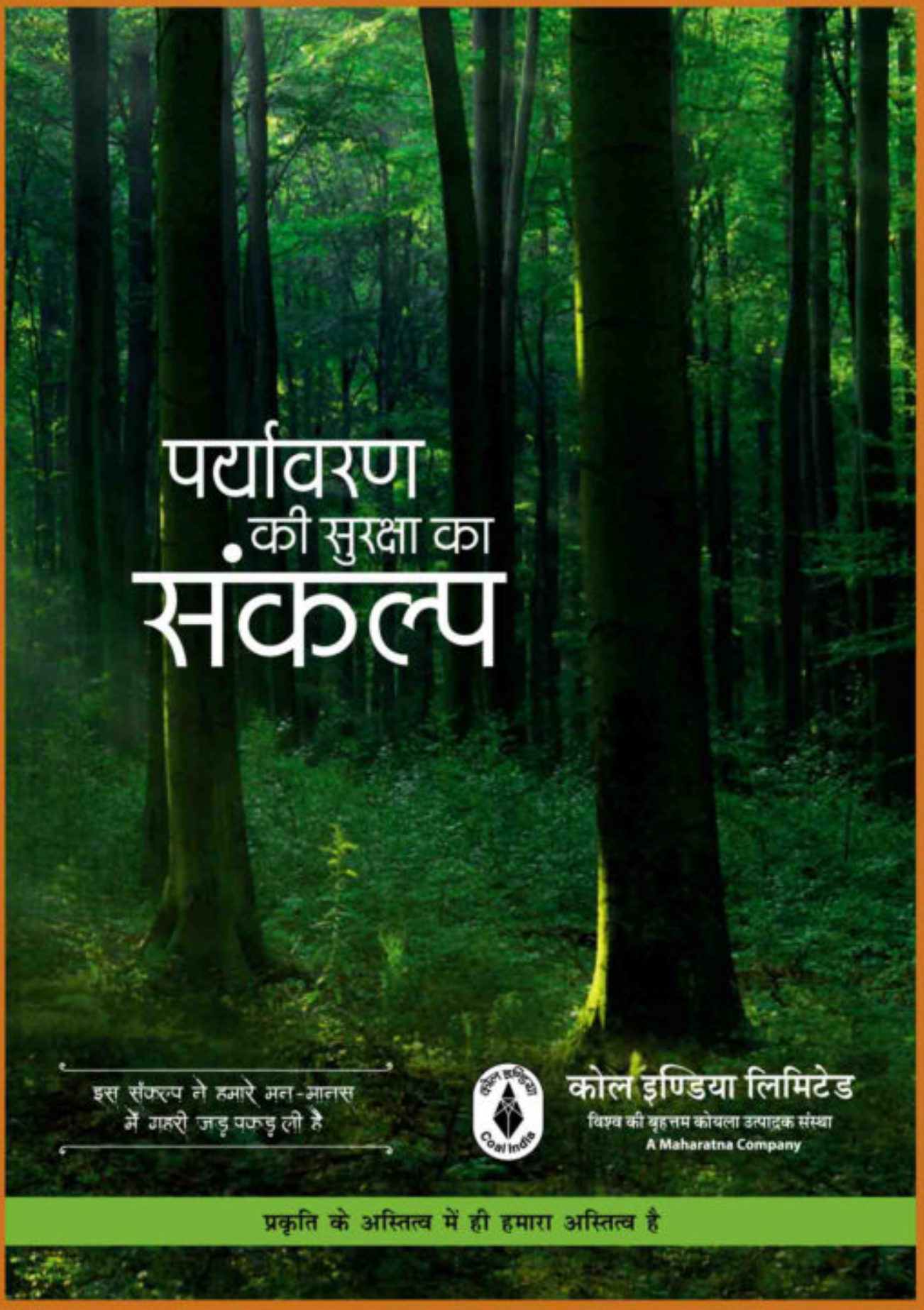
पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है